**SHORT DURATION DISCUSSION**

**The unprecedented spurt in violence in Gaza and West Bank area of Palestine causing death of scores of civilians**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Short Duration Discussion. Shri Ghulam Nabi Azad.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, in the morning I raised a very important issue. Will the Government give some assurance whether they will look into the matter regarding the appointment of ... *(Interruptions)*...

**श्री नरेश अग्रवाल** (उत्तर प्रदेश) : सर, यह सरकार की ...(**व्यवधान**)...

DR. V. MAITREYAN: I just want an assurance from the Minister whether he will look into the matter abut the judges. The Government assured us that they will bring a Bill. I would like to know whether they are going to bring any Bill. I just want an assurance. That is all. Nothing more. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the issue now. No ... *(Interruptions)*... We are now going to take up Short Duration Discussion.

**श्री के.सी. त्यागी** (बिहार) : सर, सरकार नहीं चाहती है ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it cannot be allowed. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called Mr. Ghulam Nabi Azad. He is on his legs. Dr. Maitreyan, I am not talking to you. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: I am requesting, through you, Sir, ... *(Interruptions)*... I would like to know whether the Government will look into the matter.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS AND THE MINISTER OF OVERSEAS AFFAIRS (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): Yes, we will look into the matter. ... *(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, how can you allow this? ... *(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): The Member has all the options. He can write and all hon. Members' letters or suggestions have always been looked into.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can write to the Government. Now Shri Ghulam Nabi Azad.

**विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद)** : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं चेयर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज दूसरी दफा, दूसरे अटेम्प्ट में पूरी अपोजिशन की, कांग्रेस और अपोजिशन की जो दरख्वास्त थी, पैलस्टाइन और इज़राइल के बीच में जो कंफ्लिक्ट चल रहा है...**(व्यवधान)**...

**श्री के.सी. त्यागी** (बिहार) : सर, यह गलत है ...**(व्यवधान)**... यह सीधा हमला है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री गुलाम नबी आज़ाद** : मैं उस पर आने वाला हूं। उस पर चर्चा करने का मौका दिया और मुझे इस बात का भी खेद है कि अगर आज से छः दिन पहले हमने इस विषय पर चर्चा की होती, तो शायद पूरे विश्व के देशों के साथ और नेताओं के साथ हमारे भारत का भी नाम जुड़ जाता, हमारे सदन का भी नाम जुड़ जाता क्योंकि उस वक्त, जब छःदिन पहले यह लिस्ट हुआ था, उस वक्त इज़राइल की तरफ से पैलस्टाइन में सिर्फ हवाई हमले हो रहे थे और मरने वालों की जो संख्या थी, वह दो सौ से कम थी, लेकिन इस बीच में यह लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही है और मैं अपने मित्र से इत्तफाक करता हूं कि आज जिस तरीके से इज़राइल की तरफ से पैलस्टाइन पर हमला चारों तरफ से किया जा रहा है और अगर इसे रोका नहीं गया, तो पैलस्टाइन की और खास तौर से गाज़ा स्ट्रिप रहेगी या नहीं रहेगी, पैलस्टाइन को इसकी बड़ी चिंता है। माननीय उपसभापति, मैं पहली सेंच्युरी से सातवीं सेंच्युरी तक जाना नहीं चाहता हूं कि किसके पास इज़राइल की जमीन थी और सातवीं सेंच्युरी के बाद बीसवीं सदी तक यह जमीन किस के पास थी। लेकिन मेरे ख्याल में इस झगड़े को समझने के लिए हमारे जो कई साथी हैं, उनके लिए दो-चार मिनट में बैक ग्राउंउ बताना चाहता हूं। मैं 1917 के Balfour declaration के बारे में भी नहीं जाना चाहता, जबकि उस वक्त के ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ही अपने Lord Rothschild को लिखा। Balfour declared his support for the establishment of a Jewish homeland in the area known as Palestine.

तो कब से यह शुरू हुआ, मैं इस पूरी हिस्ट्री में इन तमाम चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 1947 के साथ हम जुड़े हैं, हमारा भारत भी उसी दौरान स्वतन्त्र हुआ। 1947 में यूनाइटेड नेशंस का जो पीस प्लान था इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में कि किस तरह से जमीन का बंटवारा हो जाए, उसको अगर आज 65-66 साल के बाद देखेंगे, मेरे पास नक्शा है कोई भी गूगल से निकाल सकता है, मैंने भी उसी से निकाला है। 1947 में इस नक्शे में ब्लैक वाला फिलिस्तीन है और कहीं-कहीं व्हाइट वाला इज़राइल है। इतने वर्षों में क्या हुआ? 1947 में फिलिस्तीन का एरिया जो फिलिस्तीनी अरब के पास था, वह 95 से 98 प्रतिशत था। मैंने परसेंटेज सिर्फ इसके हिसाब से निकाली है, दो-चार परसेंट आगे-पीछे हो सकता है, क्योंकि इसमें अलग-अलग चार एरियाज़ दिखाए हैं, जो पुरानी पोजिशन और आज की पोजिशन है। तकरीबन फिलिस्तीनी अरब के पास 95 से 98 प्रतिशत एरिया था, इज़राइल के पास 2 से 5 प्रतिशत। मैं

1947 से पहले की बात कर रहा हूं और जिस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने पार्टिशन प्लान दे दिया, उस वक्त फिलिस्तीन या अरब के पास तकरीबन 55 प्रतिशत और इज़राइल के लिए 45 प्रतिशत जमीन दे दी, जो कि दोनों फरीकों को मंजूर नहीं है, इज़राइल को भी और फिलिस्तीन को भी। लेकिन 1947 से 1967 तक क्या हुआ? आहिस्ता-आहिस्ता इज़राइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर लिया और 1967 में यह पोजिशन पहुंच गई कि फिलिस्तीन 35 परसेंट और इज़राइल 65 परसेंट। सब से बड़ा चिंता का विषय यह है कि अगर आप इसी नक्शे से देखेंगे कि आज इज़राइल 92 परसेंट से 98 परसेंट हो गया और फिलिस्तीन 5 से 8 परसेंट रह गया, तो यह बुनियादी है झगड़े की। अगर इस झगड़े के पीछे देखेंगे तो आज फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस आएंगे, फिर हमारी कूटनीति आएगी, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आएंगे। अगर 1917 से लेकर आज तक का इतिहास देखेंगे, तो पाएंगे कि जमीन किसी एक की है, लेकिन तीसरे आदमी ने दूसरे आदमी को कहा कि कब्जा करो। आप देखें, जिसकी जमीन है, उससे नहीं पूछा गया। यही इस झगड़े की वजह है।

महोदय, मैं देख रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है, लेकिन कोई बड़े देश बोलने को तैयार नहीं हैं। जब इन विकसित देशों, पॉवरफुल मुल्कों का कोई सेल्फ-इंटरेस्ट होता है, तो वे एक छोटे मुल्क को दबाने में 24 घंटे भी नहीं लगाते हैं, लेकिन यहां 15 दिनों से युद्ध चल रहा है, वह लिप-सिंपैथी तो जरूर शो करते हैं, परंतु वे धृतराष्ट्र की तरह बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मैं बड़े देशों की बात कर रहा हूं क्योंकि कूटनीति व फॉरेन पॉलिसी बीच में आती है। मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप समझते हैं। पिछले 10-12 सालों में हमने देखा है कि इन बड़े देशों का जहां सेल्फ-इंटरेस्ट था, चाहे तेल का इंटरेस्ट था, दूसरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट या ग्रुपबंदी या ब्लॉक का इंटरेस्ट था, उन्होंने दिलचस्पी ली, लेकिन यहां लिप-सिंपैथी के सिवाय कुछ नहीं हो रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, यहां किसी एक व्यक्ति के सहयोग या साथ का प्रश्न नहीं है। आज सवाल है कि भारत कहां खड़ा है? हमारा सेल्फ इंटरेस्ट कभी भी किसी एक धर्म, एक व्यक्ति या एक देश के साथ नहीं रहा है। आजादी से पहले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और हमारे दूसरे लीडर्स उस वक्त भी जबकि कम्युनिकेशन के इतने साधन मौजूद नहीं थे - टेलिफोन या टेलिविजन नहीं थे, वे पूरे विश्व पर नज़र रखते थे। वे जानते थे कि कौन से देश कमजोर हैं, कौन से देश ताकतवर हैं, आर्थिक तौर पर कौन कमजोर है, आर्थिक तौर पर कौन मजबूत है, हथियारों की दौड़ में कौन आगे है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज उस समय भी उठायी। मुझे अफसोस है कि आज भारत का नाम, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, एक बड़ी ताकत माना जाता है, आबादी के हिसाब से ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले डेमोक्रेटिक देश के रूप में लिया जाता है और जब भारत एक इकॉनोमिक पॉवर के रूप में दुनिया में उभर रहा है, लेकिन इस वक्त वह एक तमाशाई बनकर बैठा है। हमें सात दिन यह सोचने में लग गए कि हम इस विषय पर चर्चा करें या न करें।

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

उपसभापति महोदय, आज भारत दुनिया का सब से पहला देश होना चाहिए था और इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन हम से चूक हो गयी। विपक्ष ने यह मसला उठाया जबकि यह काम विपक्ष का नहीं बल्कि सरकार का था। अगर दुनिया में कोई छोटा या कमजोर देश एक ताकतवर देश के द्वारा दबाया जा रहा है, तो यह भारत का काम है क्योंकि हम यह भुगत चुके हैं। महोदय, सैकड़ों साल हिन्दुस्तान को ताकत से दबाया गया, लेकिन आज हम अगर चुप बैठ जाते हैं, तो यह भारत के लिए अच्छी बात नहीं है।

उपसभापति जी, यह झगड़ा 12 जून से शुरू हुआ जब 3 इज़राइली नौजवान गुम हो गए। कहा जाता है कि एब्डक्ट हुए और इज़राइल ने कहा कि 'हमास' ने इन्हें मार दिया है। 'हमास' ने कहा कि हमने नहीं मारा है। और तीन हफ्ते बाद, 7 जुलाई को इज़राइल ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया, एअर स्ट्राइक्स से हमला कर दिया। हालांकि पेपर्स ने लिखा है कि इजराइल को दूसरे-तीसरे दिन ही मालूम हो गया था कि वे नौजवान मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने बराबर टेम्पो बनाने के लिए, दुनिया की हमदर्दी हासिल करने के लिए, एक नेशनल ओपिनियन बनाने के लिए तीन हफ्ते तक इस पर पर्दा डाला और कहा कि वे हमें मिल नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं और फिर 7 जुलाई को इतना बड़ा हमला कर दिया। मेरे ख्याल से जो एक छोटी सी गाज़ा पट्टी है, उस पर 1500 से ज्यादा एअर-स्ट्राइक्स किए और सैकड़ों टन, जहां तक मुझे याद है कि तीन दिन पहले तक 1050 टन के करीब एम्युनिशन गाज़ा पट्टी पर, वहां के लोगों पर फेंका गया। जिस वक्त हम इस सदन में चर्चा कर रहे थे और चाहते थे पूरी चर्चा करना, उस वक्त सिर्फ हवाई हमले हो रहे थे, लेकिन आज पांचवां दिन है और इज़राइल ने संयम रखने के बजाय, लड़ाई रोकने के बजाय हवाई हमले जारी रखे, ग्राउंड हमले शुरू किए और समुद्र के हमले भी शुरू किए। दुनिया का एक आधुनिक हथियार रखने वाला देश एक छोटी सी जगह के लिए, एक छोटी सी पट्टी , गाज़ा पट्टी, जो 41 किलोमीटर लंबी है और कुल 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, उसके लिए कितना एम्युनिशन डालेगा, उसमें उसकी कितनी फौज जाएगी, कितने टैंक जाएंगे और आप कितना बारूद उस पर फेंकेंगे? उस बारूद से क्या निकलता है? यूनाइटेड नेशन एजेन्सीज़ ने, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज़ ने इन्क्यूलिडिंग अल-जज़ीरा के अनुसार अभी 20 जुलाई तक इन स्ट्राइक्स में, जमीनी और हवाई हमलों में मरने वालों की तादाद 450 पहुंच गई है। एक ही दिन में, 12 जुलाई को तो 56 लोगों की मौत हुई, कल इतवार को अलसरिया में 60 लोग मारे गए। हजारों की तादाद में लोग अफरा-तफरी में भाग रहे हैं और आज की सुबह तक, जब मैंने लास्ट टेलीविजन अल-जज़ीरा देखा, तो आज तक 60 लाख लोग बेघर हो गए हैं और हजारों की तादाद में, करीब 3500 फिलिस्तीनी अभी तक जख्मी हुए हैं। इन 3500 की तादाद में से सैकड़ों की तादाद में बच्चे और औरतें जख्मी हुए हैं। सिविलियन कैजुअल्टीज़ भी अब 80 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है, कल जो मैंने उनके स्वास्थ्य मंत्री का बयान अल-जज़ीरा से सुना, क्योंकि वहां बहुत सारी डिस्पेंसरीज़, हॉस्पीटल्स, नर्सिंग होम्स तबाह हो गए हैं, बरबाद हो गए हैं, वहां कोई दवा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये जो 3500 लोग

जख्मी हुए हैं, ये कोई कान दर्द के पेशेंट नहीं हैं या पेट दर्द के नहीं हैं कि इंतजार कर सकें, ये तो वे जख्मी हैं, जिनमें से किसी की टांग नहीं है, किसी के बाजू नहीं है और वहां के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि इनमें से कितने बचेंगे, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर नहीं हैं। कल तक 1800 मकान बरबाद हो चुके थे और वहां 9 लाख लोगों के लिए पानी नहीं है। 22 लाख लोग युनाइटेड नेशन्स के शैल्टर कैम्पों में हैं और हज़ारों की तादाद में भाग रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले इज़राइल में अभी तक मरने वालों की तादाद 18 है, जिसमें 13 इज़राइली फौजी, कल जब Palestine में घुस गए, तब उस लड़ाई में मारे गए। तो आप देखिए, अगर आप एक तरफ से Palestine में मरने वालों की संख्या देखेंगे, ज़ख्मी होने वालों की, अस्पतालों की, बिल्डिंगों की, मकानों की, कैम्पों में दूसरी साइड से इज़राइल की स्थिति देखेंगे, तो उनका कहीं भी कोई भी, मुकाबला नहीं है- न मरने वालों की तादाद में... हम यह नहीं कहते हैं कि इजराइल के लोग मरें, लेकिन जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, तो मुकाबले की लड़ाई होती है। यहां तो कोई मुकाबला नहीं है। According to the *Times of Israel* – I am quoting the Times Israel, I am not quoting Times of Palestine – 'the UN Ambassador, Riyadh Mansoor wept during his speech at the Un Security Council Meeting held on Friday, 18th July afternoon to deliberate on the situation in Gaza.' *The Times of Israel* is quoting, and I quote the Ambassador, according to the newspaper, 'With every moment that passes, the life of another Palestine child or mother or father is cruelly taken by the Israeli occupying forces in their murderous rampage of airstrikes and artillery bombardment of civilian areas and now a massive ground invasion in the Gaza Strip, threatening the safety and survival of the entire Palestinian civilization and civilian population.' The Palestinian Ambassador said that Israel is not acting in self-defence, which is being made out by some big countries, but with planned 'vengeful military aggression'.

माननीय उपसभापति जी, मैं पांच मिनट और लूंगा। हमारे देश की एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी रही, इस तरह के देशों को समर्थन करने की, सपोर्ट देने की। आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने Palestine के संबंध में कहा। 1938 में, भारत की आज़ादी से 10 साल पहले, आपको मालूम होगा कि उस वक्त 'द हरिजन' नाम का एक अखबार निकलता था, जिसको गांधी जी एडिट भी करते थे और उसके लिए लिखते भी थे। उसमें 1938 का, गांधी जी का जो लेख है, उसका टाइटल है The Jews in Palestine. यह टाइटल है 'हरिजन' में, 1938 का अखबार है, And what Gandhiji writes ... *(Interruptions)*...

**श्री अवतार सिंह करीमपुरी** (उत्तर प्रदेश) : ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, हरिजन शब्द पर बैन है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Karimpuri, please. ... *(Interruptions)*...

**श्री गुलाम नबी आज़ाद** : मैं आपको बताऊंगा ...(**व्यवधान**)... मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा, उस वक्त, 1930 में एक अखबार था, उसका वह नाम था, जैसे आज एक अखबार है, जिसका नाम 'हिन्दू' है। हम उसे सुबह पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a name. ... *(Interruptions)*... आप बोलिए।

**श्री गुलाम नबी आज़ाद** : तो मैं हिस्ट्री तो चेंज नहीं कर सकता हूं। जो अखबार 1938 में था, मैं उसको दूसरे नाम से कैसे बुलाऊं?

**श्री उपसभापति** : ठीक है। आप बोलिए। Please continue.

**श्री गुलाम नबी आज़ाद** : 'द हरिजन', तो उसमें महात्मा गांधी क्या कहते हैं, वह सुनो। I Quote, "Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to English or France to French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. The nobler course would be to insist on the treatment of the Jews wherever they are born and bred. ..." The Jews born in France are French, in precisely the same sense the Christians born in France are French." यह गांधी जी तब से कहते हैं। उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर आज तक, अगर मैं केवल कांग्रेसी लीडर्स को कोट करूंगा तो शायद सदन के उस तरफ के लोग कहेंगे कि यह सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसी थी, बी.जे.पी. की पॉलिसी नहीं थी, इसलिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे टॉलेस्ट लीडर थे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : हैं।

SHRI GHULAM NABI AZAD: I am sorry, I take my words back. उस वक्त जो लीडरशिप थी, भगवान करे कि उनकी आयु लम्बी हो, हम सब उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, across the party lines. मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि पांच साल तक वे उस सदन में लीडर ऑफ अपोज़िशन रहे और मैं उन पांच सालों में पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर रहा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस में किसी को उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे मिला, इसीलिए मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। On an official visit to Syria, in November 2003, the then Primes Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, said, "We fully support the Palestinian cause and there is no change in India's position on establishing peace in West Asia." Shri Yashwant Sinha, the then External Affairs Minister, reportedly briefed the Media after Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's meeting with Syrian Prime Minister, Bashar al-Assad. He quoted Vajpayee*ji*, as telling Syrian President, that India was fully with Palestinian cause. हम यह कोई नयी रेखा, नयी लाइन आज नहीं खींच रहे हैं। 1938 से लेकर, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू से डा. मनमोहन सिंह जी तक, कांग्रेस के प्रधान मंत्रियों के समय में और उन प्रधान मंत्रियों के समय में, जिनका हमने समर्थन किया, उन प्रधान मंत्रियों के समय में, जिन्हें आपने भी समर्थन

दिया, मोरारजी देसाई से लेकर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तक के समय में यह पॉलिसी रही। ...(**समय की घंटी**)... मैं समय की घंटी आज इस सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई बदलाव आया है? ...(**समय की घंटी**)... गांधी जी की पॉलिसी, नेहरू जी की पॉलिसी, इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी, राजीव गांधी जी की पॉलिसी, लाल बहादुर शास्त्री जी की पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पॉलिसी, डा. मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी जो कल तक थी, पैलस्टाइन से संबंधित वही पॉलिसी आज भी इस सरकार की है। क्या उसमें कोई बदलाव आया है? माननीय उपसभापति महोदय, एक तो पैलस्टाइन का मसला है। इसके साथ साथ-साथ वेस्ट एशिया में हिन्दुस्तान का सेल्फ इंटरेस्ट भी है। 70 लाख के करीब हमारे हिन्दुस्तानी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज वेस्ट एशिया में रहते हैं, जहां से हिन्दुस्तान के लिए 70 परसेंट तेल, पेट्रोल, डीज़ल और बाकी चीज़ें आती हैं और तकरीबन चार लाख करोड़ यहां मेरे कुलीग आनन्द शर्मा जी बैठे हैं, ये मुझे करेक्ट करेंगे, मिनिस्टर यहां नहीं हैं, 65 बिलियन जो हमारी ग्लोबल अर्निंग है, रेमिटेंस है, वह तकरीबन चार लाख करोड़ बनती है और इसमें से आधा तो वेस्ट एशिया से ही आता है। मज़दूर से लेकर डॉक्टर और नर्स तक, वेस्ट एशिया में कौन सी ऐसी कम्पनी है जहां हिन्दुस्तानी काम नहीं करता? उनकी वजह से वहां की ग्रोथ और डेवलपमेंट में फायदा होता है और जो वहां से पैसा आता है, उससे हमारी economy को, हिन्दुस्तान की economy को तथा हमारी गुरबत को हटाने में फायदा मिलता है। मैं बताना चाहूंगा कि जब श्री बान की मून वेस्ट एशिया के दौरे पर थे, मैंने पौने बारह बजे तक उनका इंटरव्यू सुना, मुझे खुशी है कि श्री बान की मून, यूनाइटेड नेशन्स के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, I quote: "While I was *en route* to Doha, dozens of civilians were being killed in the Israeli strikes. I condemn the atrocious action. Israel must exercise maximum restraint. I repeat my demand to all sides that they must respect international humanitarian law. The violence must stop now." *(Time-bell rings)*

Lastly, Sir, I request the Indian Government and this Parliament to rise to the occasion and pass Resolution that Israel's heavy and disproportionate use of force must stop forthwith. Defiant rocket attacks by Hamas on Israeli territory should also come to an end. Prevent further loss of life and property in Palestine. United appeal has to be made to both the sides to de-escalate tensions. The Government needs to realize India's true status and walk its talk. India adopt a pro-active approach in the matters of West Asia. सर, मेरी आखिरी अपील होगी कि पूरा सदन, जो पैलस्टाइन पर हमले हो रहे हैं, उनको कंडेम करे और एक रेजोल्यूशन पास करे कि यह भारत, हमारा सदन और हमारी सरकार, इस देश की अपोजिशन, 124 करोड़ जनता, इस वक्त की humanitarian values की कद्र करती है और जो भी ...(**समय की घंटी**)... massacre पैलस्टाइन में हो रहा है, वह खत्म होना चाहिए। उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

†[ **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : مائنے ڈپٹی چیئرمین صاحب، میں چیئر کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ آج دوسری دفعہ، دوسرے اٹیمپٹ میں پوری اپوزیشن کی، کانگریس اور اپوزیشن کی جو درخواست تھی، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جو کنفلکٹ چل رہا ہے ...(مداخلت)...

**شری کے۔سی۔ تیاگی** : سر، یہ غلط ہے ...(مداخلت)... یہ سیدھا حملہ ہے ...(مداخلت)...

**جناب غلام نبی آزاد** : میں اس پر آنے والا ہوں۔ اس پر چرچا کرنے کا موقع دیا اور مجھے اس بات کا بھی کھید ہے کہ اگر آج سے چھہ دن پہلے ہم نے اس وشئے پر چرچا کی ہوتی، تو شاید پوری دنیا کے دیشوں کے ساتھہ اور نیتاؤں کے ساتھہ ہمارے بھارت کا نام بھی جڑ جاتا، ہمارے سدن کا بھی نام جڑ جاتا، کیوں کہ اس وقت، جب چھہ دن پہلے یہ لسٹ ہوا تھا، اس وقت اسرائیل کی طرح سے فلسطین میں صرف ہوائی حملے ہو رہے تھے اور مرنے والوں کی جو تعداد تھی، وہ دو سو سے کم تھی، لیکن اس بیچ میں یہ لڑائی بڑے پیمانے پر لڑی جا رہی ہے اور میں اپنے دوست سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج اس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر حملہ چاروں طرف سے کیا جا رہا ہے اور اگر اسے روکا نہیں گیا، تو فلسطین کی اور خاص طور سے غزہ اسٹرپ رہے گی یا نہیں رہے گی، فلسطین کو اس کی بڑی چنتا ہے۔

مائنے اپ سبھا پتی، میں پہلی صدی سے ساتویں صدی تک جانا نہیں چاہتا ہوں کہ کس کے پاس اسرائیل کی زمین تھی اور ساتوں صدی کے بعد بیسویں صدی تک یہ زمین کس کے پاس تھی۔ لیکن میرے خیال میں اس جھگڑے کو

†Transliteration in Urdu Script.

سمجھنے کے لئے ہمارے جو کئی ساتھی ہیں، ان کے لئے دو چار منٹ میں بیک-گراونڈ بتانا چاہتا ہوں۔ میں 1917 کے Balfour Declaration کے بارے میں بھی نہیں جانا چاہتا، جب کہ اس وقت کے برٹش فارن منسٹر نے خود ہی اپنے Lord Rothschild میں لکھا ہے۔ Balfour declared his support for the establishment of a Jewish homeland in the area known as Palestine.

تو کب سے یہ شروع ہوا، میں اس پوری ہسٹری میں ان تمام چیزوں کا الیکھہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن 1947 کے ساتھہ ہم جڑے ہیں، ہمارا بھارت بھی اسی دوران آزاد ہوا۔ 1947 میں یونائیٹیڈ نیشنس کا جو پیس-پلان تھا اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں، کہ کس طرح سے زمین کا بنٹوارا ہو جائے، اس کو اگر آج 65-66 سال کے بعد دیکھیں گے، میرے پاس نقشہ ہے کوئی بھی گوگل سے نکال سکتا ہے، میں نے بھی اسی سے نکالا ہے۔ 1947 میں اس نقشے میں بلیک والا فلسطین ہے اور کہیں کہیں وہائٹ والا اسرائیل بھی ہے۔ اتنے سالوں میں کیا ہوا؟ 1947 میں فلسطین کا ایریا جو فلسطینی عرب کے پاس تھا، وہ 95 سے 98 فیصد تھا۔ میں پرسنٹیج صرف اس کے حساب سے نکالی ہے، دو-چار فیصد آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کیوں کہ اس میں الگ-الگ چار ایریاز ہیں، جو پرانی پوزیشن اور آج کی پوزیشن ہے۔ تقریبا فلسطینی عرب کے پاس 95 سے 98 فیصد ایریا تھا، اسرائیل کے پاس 2 سے 5 فیصد۔ میں 1947 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور جس وقت یونائیٹیڈ نیشنس نے پارٹیشن پلان دے دیا، اس وقت فلسطین یا عرب کے پاس تقریبا 55 فیصد اور اسرائیل کے پاس 45 فیصد زمین دے دی، جو کہ دونوں فریقوں کو منظور نہیں ہے، اسرائیل کو بھی اور فلسطین کو بھی۔ لیکن 1947 سے 1967 تک کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا اور

1967 میں یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ فلسطین 35 فیصد اور اسرائیل 65 فیصد۔ سب سے بڑا چنتا کا وشئے یہ ہے کہ اگر آپ اسی نقشے کو دیکھیں گے کہ آج اسرائیل 92 فصید سے 98 فیصد ہو گیا اور فلسطین 5 سے 8 فیصد رہ گیا، تو یہ بنیاد ہے جھگڑے کی۔ اگر اس جھگڑے کے پیچھے دیکھیں گے تو آج پھر ہمارے انٹرنیشنل رلیشنس آئیں گے، پھر ہماری کوٹ-نیتی آئے گی، ہمارے ڈپلومیٹک رلیشنس آئیں گے۔ اگر 1971 سے لے کر آج تک کا اتیہاس دیکھیں گے، تو پائیں گے کہ زمین کسی ایک کی ہے، لیکن تیسرے آدمی نے دوسرے آدمی کو کہا کہ قبضہ کرو۔ آپ دیکھیں، جس کی زمین ہے، اس سے نہیں پوچھا گیا۔ یہی اس جھگڑے کی وجہ ہے۔

مہودے، میں دیکھہ رہا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر لڑائی ہو رہی ہے، لیکن کوئی بڑے دیش بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب ان وکست دیشوں، پاورفل ملکوں کا کوئی سیلف-انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک چھوٹے ملک کو دبانے میں 24 گھنٹے بھی نہیں لگاتے ہیں، لیکن یہاں 15 دنوں سے جنگ چل رہی ہے، وہ لپ-سمپیتھی تو ضرور شو کرتے ہیں، لیکن وہ دھرتراشٹر کی طرح بیٹھہ کر تماشہ دیکھہ رہے ہیں۔ میں بڑے دیشوں کی بات کر رہا ہوں کیوں کہ کوٹ-نیتی و فارن پالیسی بیچ میں آتی ہے۔ میں ان دیشوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں۔ پچھلے 12-10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان بڑے دیشوں کا جہاں سیلف-انٹرسٹ تھا، چاہے تیل کا انٹرسٹ تھا، دوسرا پالیٹکل انٹرسٹ یا گروپ-بندی یا بلاک کا انٹرسٹ تھا، انہوں نے دلچسپی لی، لیکن یہاں لپ-سمپیتھی کے سوائے کچھہ نہیں ہو رہا ہے۔

مانئے اپ سبھا پتی مہودے، یہاں کسی ایک شخص کے سہیوگ یا ساتھ کا سوال نہیں ہے۔ آج سوال ہے کہ بھارت کہاں کھڑا ہے؟ ہمارا سیلف-انٹرسٹ کبھی بھی کسی ایک دھرم، ایک شخص یا ایک دیش کے ساتھ نہیں رہا ہے۔ آزادی سے پہلے، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، اور ہمارے دوسرے لیڈرس اس وقت بھی جبکہ کمیونی-کیشن کے اتنے سادھن موجود نہیں تھے - ٹیلی فون یا ٹیلی ویژن نہیں تھے، وہ پوری دنیا پر نظر رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کون سے دیش کمزور ہیں، کون سے دیش طاقتور ہیں، آرتھک طور پر کون مضبوط ہے، ہتھیاروں کی دوڑ میں کون آگے ہے، لیکن انہوں نے اپنی آواز اس وقت بھی اٹھائی۔ مجھے افسوس ہے کہ آج بھارت کا نام، بڑے سمّان کے ساتھ لیا جاتا ہے، ایک بڑی طاقت مانا جاتا ہے، آبادی کے حساب سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے آبادی والے ڈیموکریٹک دیش کے روپ میں لیا جاتا ہے اور جب بھارت ایک اکانومک پاور کے روپ میں دنیا میں ابھر رہا ہے، لیکن اس وقت وہ ایک تماشائی بن کر بیٹھا ہے۔ ہمیں سات دن یہ سوچنے میں لگ گئے کہ ہم اس وشئے پر چرچا کریں یا نہ کریں۔

اپ سبھا پتی مہودے، آج بھارت دنیا کا سب سے پہلا دیش ہونا چاہئے تھا اور اس بارے میں آواز اٹھانی چاہئے تھی، لیکن ہم سے چوک ہو گئی۔ وپکش نے یہ مسئلہ اٹھایا جبکہ یہ کا وپکش کا نہیں بلکہ سرکار کا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی چھوٹا یا کمزور دیش ایک طاقتور دیش کے ذریعے دبایا جا رہا ہے، تو یہ بھارت کا کام ہے کیوں کہ ہم یہ بھگت چکے ہیں۔ مہودے، سینکڑوں سال ہندوستان کو طاقت سے دبایا گیا، لیکن آج ہم اگر چپ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھارت کے لئے اچھی بات نہیں ہے۔

اپ سبھاپتی جی، یہ جھگڑا 12 جون سے شروع ہوا جب 3 اسرائیلی نوجوان گم ہو گئے، کہا جاتا ہے کہ ایبڈکٹ ہوئے اور اسرائیل نے کہا کہ "حماس" نے انہیں مار دیا ہے۔ "حماس" نے کہا کہ ہم نے نہیں مارا ہے۔ اور تین ہفتے بعد، 7 جولائی کو اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، ائیر اسٹرائیکس سے حملہ کر دیا۔ حالانکہ پیپرس میں لکھا ہے کہ اسرائیل کو دوسرے-تیسرے دن ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ نوجوان مارے گئے ہیں، لیکن انہوں نے برابر ٹمپو بنانے کے لئے، دنیا کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے، ایک نیشنل اوپنئن بنانے کے لئے تین ہفتے تک اس پر پردہ ڈالا اور کہا کہ وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں، مل رہے ہیں اور پھر 7 جولائی کو اتنا بڑا حملہ کر دیا۔ میرے خیال سے جو ایک چھوٹی سے غزہ پٹّی ہے، اس پر 1500 سے زیادہ ائیر-اسٹرائکس کئے اور سیکڑوں ٹن، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ تین دن پہلے تک 1050 ٹن کے قریب ایمیونیشن غزہ پٹّی پر، وہاں کے لوگوں پر پھینکا گیا۔ جس وقت ہم اس سدن میں چرچا کر رہے تھے اور چاہتے تھے پوری چرچا کرنا، اس وقت صرف ہوائی حملے ہو رہے تھے، لیکن آج پانچوان دن ہے اور اسرائیل نے سنیم رکھنے کے بجائے، لڑائی روکنے کے بجائے ہوائی حملے جاری رکھے، گرائنڈ حملے شروع کئے اور سمندر کے حملے بھی شروع کئے۔ دنیا کا ایک جدید ہتھیار رکھنے والا دیش ایک چھوٹی سر جگہ کے لئے، ایک چھوٹی سے پٹّی، غزہ پٹّی، جو 41 کلو میٹر لمبی ہے اور کل 6 سے 12 کلو میٹر چوڑی ہے، اس کے لئے کتنا ایمیونیشن ڈالے گا، اس میں اس کی کتنی فوج جائے گی، کتنے ٹینک جائیں گے اور آپ کتنا بارود اس پر پھینکیں گے؟ اس بارود سے کیا نکلتا ہے؟ یونائیٹیڈ نیشن ایجنسیز نے، انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے

انکلوڈنگ الجزیرہ کے مطابق ابھی 20 جولائی تک ان اسٹرائکس میں، زمینی اور ہوائی حملوں میں مرنے والوں تعداد 450 پہنچ گئی ہے۔ ایک ہی دن میں، 12 جولائی کو تو 56 لوگوں کی موت ہوئی، کل اتوار کو السریا میں 60 لوگ مارے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ افراتفری میں بھاگ رہے ہیں اور آج کی صبح تک، جب میں نے لاسٹ ٹیلی ویژن الجزیرہ دیکھا، تو آج تک 60 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں، قریب 3500 فلسطینی ابھی تک زخمی ہوئے ہیں۔ ان 3500 کی تعداد میں سے سیکڑوں کی تعداد میں بچے اور عورتیں زخمی ہوئے ہیں۔ سویلئن کیجولٹی بھی اب 80 فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سب سے بڑی چنتا کا وشئے ہے، کل جو میں نے ان کے سواستھ منتری کا بیان الجزیرہ سے سنا، کیوں کہ وہاں بہت ساری ڈسپینسریز، ہاسپٹلس، نرسنگ ہومس تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، وہاں کوئی دوا نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ جو 3500 لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ کوئی کان درد کے پیشینٹ نہیں ہے یا پیٹ درد کے نہیں ہیں کہ انتظار کر سکیں، یہ تو وہ زخمی ہیں، جن میں سے کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے اور وہاں کے ہیلتھ منسٹر کہہ رہے تھے کہ ان میں سے کتنے بچیں گے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ کل تک 1800 مکان برباد ہو چکے تھے اور وہاں 9 لاکھ لوگوں کے لئے پانی نہیں ہے۔ 22 لاکھ لوگ یونائیٹیڈ نیشنس نے شیلٹر کیمپوں میں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بھاگ رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے اسرائیل میں ابھی تک

مرنے والوں کی تعداد 18 ہے، جس میں 13 اسرائیلی فوجی، کل جب فلسطین میں گھن گئے، تب اس لڑائی میں مارے گئے، تو آپ دیکھئے، اگر آپ ایک طرف سے فلسطین میں مرنے والوں کی تعداد دیکھیں گے، زخمی ہونے والوں کی، اسپتالوں کی، بلڈنگوں کی، مکانوں کی، کیمپوں میں اور دوسری سائڈ سے اسرائیل کی حالت دیکھیں گے، تو ان کا کہیں بھی، کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے، نہ مرنے والوں کی تعداد میں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ مریں، لیکن جب دو دیشوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے، تو مقابلے کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہاں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔

According to the *Times of Israel* – I am quoting the Times Israel, I am not quoting Times of Palestine -- 'the UN Ambassador, Riyadh Mansoor wept during his speech at the UN Security Council Meeting held on Friday, 18th July afternoon to deliberate on the situation in Gaza.' The *Times of Israel* is quoting, and I quote the Ambassador, according to the newspaper, 'With every moment that passes, the life of another Palestine child or mother or father is cruelly taken by the Israeli occupying forces in their murderous rampage of airstrikes and artillery bombardment of civilian area and now a massive ground invasion in the Gaza Strip, threatening the safety and survival of the entire Palestinian civilization and civilian population.' The Palestinian Ambassador said that Israel is not acting in self-defence, which is being made out by some big countries, but with planned 'vengeful military aggression'.

† مانئے اپ سبھا پتی جی، میں پانچ منٹ اور لوں گا، ہمارے دیش کی ایک ایسٹیبلشڈ پالیسی رہی، اس طرح کے دیشوں کو سمرتھن کرنے کی، سپورٹ دینے کی۔ آزادی سے پہلے مہاتما گاندھی نے فلسطین کے سمبندھ میں کہا۔ 1938 میں بھارت کی آزادی سے 10 سال پہلے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت "دی ہریجن" نام کا ایک اخبار نکلتا تھا، جس کو گاندھی جی ایڈٹ بھی کرتے تھے اور اس کے لئے لکھتے تھے بھی تھے۔ اس میں 1938 کا، گاندھی جی کا جو لیکھ ہے، اس کا ٹائٹل ہے - The Jews in Palestine what ٹائٹل ہے 'ہریجن' میں، 1938 کا اخبار ہے۔ And Gandhiji writes ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Karimpuri, please. ... *(Interruptions)*...

جناب غلام نبی آزاد : میں آپ کو بتاؤں گا ---(مداخلت)---میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں گا، اس وقت، 1930 میں ایک اخبار تھا، اس کا وہ نام تھا، جیسے آج ایک اخبار ہے، جس کا نام 'ہندو' ہے۔ ہم اسے صبح پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں ---(مداخلت)---

†Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a name.... *(Interruptions)*... आप बोलिए। آپ بولئیے۔

†[جناب غلام نبی آزاد : تو میں بسٹری تو چینج نہیں کر سکتا ہوں۔ جو اخبار 1938 میں تھا، میں اس کو دوسرے نام سے کیسے بلاؤں؟

شری اپ سبھا پتی: ٹھیک ہے، آپ بولئیے، پلیز کنکلوڈ۔

جناب غلام نبی آزاد : 'دی ہریجن' ، تو اس میں مہاتما گاندھی کیا کہتے ہیں وہ سنو۔

I quote, "Palestine belongs to the Arabs in the same sense that England belongs to English or France to French. It is wrong and inhuman to impose the Jews on the Arabs. The nobler course would be to insist on the treatment of the Jews wherever they are born and bred. ..." The Jews born in France are French, in precisely the same sense the Christians born in France are French."

یہ گاندھی جی تب سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے پنڈت جواہر لال نہرو، شاستری جی، اندرا جی، راجیو جی سے لے کر آج تک، اگر میں صرف کانگریسی لیڈروں کو کوٹ کروں گا تو شاید سدن کے اس طرف کے لوگ کہیں گے کہ یہ صرف کانگریس کی پالیسی تھی، بی جے پی کی پالیسی نہیں تھی، اس لئے ماننے اٹل بہاری واجپئی، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سب سے بڑے ٹولیسٹ لیڈر تھے اور سبھی پولیٹکل پارٹیز ۔۔(مداخلت)۔۔

وزیر خارجہ (شریمتی سشما سوراج) : ہاں۔

جناب غلام نبی آزاد : I am sorry. I take my words back اس وقت جو لیڈر شپ تھی، بھگوان کرے کہ اس کی عمر لمبی ہو، ہم سب ان کا آدر کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، میں اپنا بڑا سوبھاگیہ مانتا across the party lines. ہوں کہ پانچ سال تک وہ اس سدن میں لیڈر آف اپوزیشن رہے اور میں ان پانچ سالوں میں پارلیمنٹری افیئرس منسٹر رہا۔ اس لئے سب سےزیادہ اگر کانگریس میں کسی کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو مجھے ملا، اسی لئے میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔]

*On an official visit to Syria, in November 2003, the then Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, said, "We fully support the Palestinian cause and there is no change in India's position on establishing peace in West Asia." Shri Yashwant Sinha, the then External Affairs Minister, reportedly briefed the Media after Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's meeting with Syrian Prime Minister, Bashar al-Assad. He quoted Vajpayeeji, as telling Syrian President, that India was fully with Palestinian cause.*

†Transliteration in Urdu Script.

†[ہم یہ کوئی نئی ریکھا، نئی لائن آج نہیں کھینچ رہے ہیں۔ 1938 سے لے کر، آزادی سے پہلے، آزادی کے بعد، پنڈت جواہر لال نہرو سے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی تک، کانگریس کے پردھان منتریوں کے وقت میں اور ان پردھان منتریوں کے وقت میں، جن کا ہم نے سمرتھن کیا، ان پردھان منتریوں کے وقت میں، جنہیں آپ نے بھی سمرتھی دیا، مرارجی ڈیسائی سے لے کر مانئے اٹل بہاری واجپئی جی تک کے وقت میں یہ پالیسی رہی ---(وقت کی گھنٹی)--- میں آج اس سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری فارن پالیسی میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ ---(وقت کی گھنٹی)--- گاندھی جی کی پالیسی، نہرو جی کی پالیسی، اندرا جی کی پالیسی، راجیو گاندھی جی کی پالیسی، لال بہادر شاستری جی کی پالیسی، اٹل بہاری واجپئی جی کی پالیسی، ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کی پالیسی جو کل تک تھی فلسطین سے سمبندھت وہی پالیسی آج بھی اس سرکار کی ہے۔ کیا اس میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ مانئے اپ سبھا پتی مہودے، ایک تو فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ ایشیا میں ہندوستان کا سیلف-انٹرسٹ بھی ہے۔ 70 لاکھ کے قریب ہمارے ہندوستانی، کشمیر سے کنیاکماری تک آج ویسٹ ایشیا میں رہتے ہیں، جہاں سے ہندوستان کے لئے 70 فیصد تیل، پیٹرول، ڈیزل اور باقی چیزیں آتی ہیں اور تقریبا چار لاکھ کروڑ، یہاں میرے ساتھی آنند شرما جی بیٹھے ہیں، یہ مجھے کریکٹ کریں گے، منسٹر یہاں نہیں ہیں، 65 بلین جو ہماری گلوبل ارننگ ہے ریمیٹنس ہے، وہ تقریبا چار لاکھ کروڑ بنتی ہے اور اس میں سے آدھا تو ویسٹ ایشیا سے ہی آتا ہے۔ مزدور سے لے کر ڈاکٹر اور نرس تک، ویسٹ ایشیا میں کون سی ایسی کمپنی ہے جہاں ہندوستانی کام نہیں کرتا؟ ان کی وجہ سے وہاں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے اور جو وہاں سے پیسہ آتا ہے، اس سے ہماری economy کو، ہندوستان کی economy، کو اور ہماری غربت کو ہٹانے میں فائدہ ملتا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ جب شری بان کی مون ویسٹ ایشیا کے دورے پر تھے، میں نے پونے بارہ بنے تک ان کا انٹرویو سنا، مجھے خوشی ہے کہ شری بان کی مون، یونائیٹڈ نیشنس کے سکریٹری جنرل نے کہا۔ ]

†Transliteration in Urdu Script.

I quote: "While I was *en route* to Doha, dozens of civilians were being killed in the Israeli strikes. I condemn the atrocious action. Israel must exercise maximum restraint. I repeat my demand to all sides that they must respect international humanitarian law. The violence must stop now." *(Time bell rings)*

Lastly, Sir, I request the Indian Government and this Parliament to rise to the occasion and pass a Resolution that Israel's heavy and disproportionate use of force must stop forthwith. Defiant rocket attacks by Hamas on Israeli territory should also come to an end. Prevent further loss of life and property in Palestine. United appeal has to be made to both the sides to de-escalate tensions. The Government needs to realize India's true status and walk its talk. India adopt a pro-active approach in the matters of West Asia.

†[ سر، میری آخری اپیل ہوگی کہ پورا سدن، جو پیلسٹائن پر حملے ہورہے ہیں، ان کو کنڈیم کریں اور ایک ریزولیوشن پاس کریں کہ یہ بھارت، ہمارا سدن اور ہماری سرکار، اس دیش کی اپوزیشن، 124 کروڑ جنتا، اس وقت humanitarian values کی قدر کرتی ہے اور جو بھی ---(وقت کی گھنٹی)--- پیلسٹائین میں ہورہا massacre ہے، وہ ختم ہونا چاہئے۔ آپ سبھاپتی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, before I call the next speaker, I have to inform that the time, actually, allotted for the discussion is one hour and thirty minutes. That was the understanding in the morning meeting and the Party Leaders also agreed to that. ... *(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, this is an important issue. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me inform you. Accordingly, the time available for the Indian National Congress: 26 minutes; BJP: 16 minutes; BSP; 5 minutes; AITC: 5 minutes; JD (U): 5 minutes; AIADMK: 4 minutes; SP: 4 minutes; CPI (M): 3 minutes; BJD: 3 minutes; TDP: 2 minutes; NCP: 2 minutes; Nominated: 4 minutes and Others: 11 minutes. So, how to adjust ? ... *(Interruptions)*...

SHRI D.P. TRIPATHI (Maharashtra): Sir, maiden speech ... *(Interruptions)*... 10 minutes. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no , please, I have only informed the decision. ... *(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we have two speakers from the Congress Party. ... *(Interruptions)*... We had given six names, but we would like, at least, two to speak. ... *(Interruptions)*...

†Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do? ... *(Interruptions)*... That is what I am saying. ... *(Interruptions)*... That is what I am informing. I will not accept any more names. Whatever names have been accepted, they will speak. ... *(Interruptions)*... I will not accept any more names. Already, that is the direction from the chairman. Therefore, please try to be brief and adhere to the time. That is all, Shri Anil Dave. ... *(Interruptions)*... Now, the BJP has given three names. I would request them to withdraw one name. Have two names and take eight, eight minutes. I would request the BJP to withdraw one name. Like that, we will manage. Now, Shri Anil Dave.

**श्री अनिल माधव दवे** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं या कहूं कि चर्चा कर रहे हैं, इस समस्या की जड़ में जाना आवश्यक है कि आखिर यह समस्या क्या है। अगर हमने इसको ठीक से डाइग्नोज नहीं किया, तो निश्चित ही इसका इलाज वह नहीं होगा, जो चाहिए। हमने आज के विषय पर यह कहा कि यह गाजा और इजराइल के विवाद के बीच का विषय है और हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं यहां प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं कि क्या विश्व के रंगमंच पर यह एक ही विवाद है? पिछले एक वर्ष के अंदर Sinai Insurgency, Syrian Civil War, Sudan conflicts. Northern Kosovo, Northern Mali conflicts, Central Africa Republic conflicts, Russia और Ukraine आपने एक ही बार में तीन सौ से ज्यादा आम नागरिकों को मार दिया, आप उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए और इस समय सीरिया और इराक के बीच जो चल रहा है, मुझे लगता है कि हमें चर्चा विश्व शांति के ऊपर करनी चाहिए। हमें विश्व के अंदर होने वाले वाले अतिक्रमणों पर चर्चा करनी चाहिए, जो एक-दूसरे पर लोग कर रहे हैं। हमारा देश गांधी और बुद्ध का देश है। जब भी हमें विचार करना हो, तो हमारा चिंतन ग्लोबल होना चाहिए, समग्र होना चाहिए और टोटेलिटी में होना चाहिए, चूंकि आज विषय इसी बात पर ले लिया गया है और उसे बिजनेस में डाला गया है।

मैं यहां कुछ दूसरी समस्याओं और विवादों पर भी चर्चा करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... आप चिंता मत करिए। आपको सुनने के बाद लगेगा ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, please. ... *(Interruptions)*... No, Mr. Soz, please. We have shortage of time. Don't interrupt. ... *(Interruptions)*... No interruptions. ... *(Interruptions)*... Mr. Dave, you continue. You address the Chair, please ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिव माधव दवे** : उपसभापति जी, जो लड़ाई इजराइल और गाजा के बीच में चल रही है, उतनी ही इंटेंसिटी से विश्व के विभिन्न देशों में विवाद चल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ... *(Interruptions)*... Please.

**श्री मणि शंकर अय्यर** (नाम निर्देशित) : आक्रमण हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. Mr. Mani Shankar Aiyar, there is no time. ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : मणि शंकर जी, आपके साथ यह प्रॉब्लम है कि आप बहुत जल्दी अनइज़ी हो जाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Anil Dave, you address the Chair. ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : मैं ISIS के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can ignore them. You address the Chair. ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : इराक पर जिस प्रकार से सीरिया का हमला हो रहा है, अगर हम पूरे इराक की डेमोग्राफी देखते हैं, तो वहां पर 15 प्रतिशत कुर्द, 15 प्रतिशत ...(**व्यवधान**)... सुन्नी और 75 प्रतिशत के आसपास शिया रहते हैं। आज समाचार पत्र के अंदर ...(**व्यवधान**)... छपे कब्रगाह के फोटोग्राफ को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ... *(Interruptions)*... Please sit down. ... *(Interruptions)*... He is saying his views, not your views. ... *(Interruptions)*... He is saying his opinion, not yours. Please sit down. ... *(Interruptions)*... He is saying his opinion only, not yours. Sit down. Mr. Dave, please proceed. ... *(Interruptions)*... There is no time. ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : विश्व के अंदर उस कब्रगाह को एक धरोहर के रूप में देखा जाता है। वहां पर पांच लाख से ज्यादा कब्र हैं और आसमान से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा शहर है।

मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमने समस्या के निदान पर ठीक से विचार नहीं किया तो समस्या का निदान होने वाला नहीं है। यह वही सदन है, जहां लोहिया को सुनने से लोग मना करते थे, यह वही सदन है जहां पर अन्य विचारकों को भी सुनने के बजाय लोगों को चीखकर-चिल्लाकर उन्हें चुप करा दिया है। आप ऐसा मत करिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जब भी ऐसी बात आएगी ...(**व्यवधान**)... अरे भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? ...(**व्यवधान**)... जब भी ऐसा विषय आएगा, जब भी यह बात आएगी, तो मुझे लगता है कि हमें इस सदन में इस समस्या पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सदन है। इसलिए जब भी इसके ऊपर बात होगी, तो उसी स्तर की होगी। हम निम्न स्तर पर बात नहीं कर सकते। आप मुझे माफ करें, मैं और किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम बहुत बड़े सदन के सदस्य हैं।

समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ यह है कि हम Interpretation को गलत ढंग से ले रहे हैं। भारत में समस्या हो सकती है। कहीं सड़कों पर समस्या है, कहीं कोई बिल्डिंग गिरा दी गई, कहीं कोई झगड़ा हो गया। ब्रिटेन में क्या समस्या है? वहां एक हजार नौजवान शस्त्र लेकर ब्रिटेन छोड़कर सीरिया चले गए। आस्ट्रेलिया से 1200 लड़के शस्त्र लेकर चले गए हैं। यूरोप में हॉलैंड और अन्य देशों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। भारत से कितने नौजवान चले गए हैं,

[श्री अनिल माधव दवे]

इसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि भारत के अंदर कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, इसकी कोई गणना नहीं होती है। यहां से कितने लोग विश्व के अंदर शस्त्र से आतंवाद करने के लिए चले गए, इसकी कोई गणना नहीं है। मित्रो, हममें से ही किसी खान अब्दुल गफ्फार खान को खड़े होकर कहना पड़ेगा। उन्होंने अपने जीते जी इस देश के विभाजन को नहीं स्वीकारा। ...*(समय की घंटी)*... वोट डालने दिल्ली आते थे और दिल्ली में अपना एक आवास रखे रहे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please conclude.

SHRI ANIL MADHAV DAVE: Sir, there is time. आप प्लीज मुझे बोले दीजिए ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : आपके तीन स्पीकर्स हैं ...(**व्यवधान**)...

**श्री अनिल माधव दवे** : मैं यह कहना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... समस्या की जड़ यह है कि कोई यह समझाने वाला नहीं है कि आपको जन्नत बंदूक और बारूद से नहीं मिलेगी। जन्नत पांच बार नमाज पढ़ने, जकात भरने, रोजा रखने और हज जाने से मिलती है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ (Jammu and Kashmir): Mr. Deputy Chairman, Sir, he is not speaking on the issue. ... *(Interruptions)*... He is not ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : मेरा यह कहना है कि हमें युवकों को यह बताने की जरूरत है कि मित्रों, अगर हमें जन्नत और जन्नत में हूर की इच्छा हो रही है ...(**व्यवधान**)... तो उसका रास्ता बंदूक की नली से होकर नहीं जाता है। हम गांधी के देश के लोग हैं और हमें गांधी के रूप में ही यह बात कहनी पड़ेगी। जहां तक इस बात का सवाल है ...(**व्यवधान**)... भारत के लोगों की समस्या यह है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ... *(Interruptions)*... Please sit down. It is over. Shri Brajesh Pathak. You told me, five minutes and three speakers. How can I do that? ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : उपसभापति जी, आप मुझे कम से कम आठ मिनट तो बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You said something and now ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : आपने 1924 में ऐसा ही किया था ...(**व्यवधान**)... हम खिलाफत आंदोलन के ...(**व्यवधान**)... समय में गए थे ...(**व्यवधान**)... हमने वहां पर कहा क्या था और हमें जवाब क्या मिला था? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you want three speakers? Reduce it by one speaker. ... *(Interruptions)*...

**श्री अनिल माधव दवे** : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें इस समस्या का कोई निदान चाहिए और हम विश्व के अंदर शांति का कोई निदान ढूंढ़ रहे हैं, तो भारत को किसी एक तरफ झुकने वाला देश नहीं बनना है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is unfair. How can you do that?

**श्री अनिल माधव दवे** : भारत के तटस्थ देश बनना चाहिए ...(**व्यवधान**)... भारत को न्याय प्रधान देश बनना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... भारत को विश्व में शांति खड़ी करने की ताकत रखने वाला देश बनना चाहिए ...(**व्यवधान**)... यदि ऐसा रेजोल्यूशन पास होता है तो ठीक है, वरना यह जो गांधी का चित्र लगा है ...(**व्यवधान**)... बात गांधी की हो और दुकान दूसरी चलाएं ...(**व्यवधान**)... इसी का परिणाम है कि इस देश और इस शहर में लोग हार का दर्द लिए घूम रहे हैं। यह ऐसी ही नीति का दर्द है। हमारी जो पॉलिसीज हैं ...(**व्यवधान**)... उससे मुझे लगता है कि हम सही दिशा में विचार करें। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please conclude.

**श्री अनिल माधव दवे** : मैं अंतिम बात कहकर अपनी स्पीच खत्म करता हूं। एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए मेरे प्रदेश के एक व्यक्ति आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक बिल्डिंग में नमाज पढ़ने जा रहे थे। मेरा उनसे बहुत अच्छा परिचय था, मैंने उनसे कहा कि, भाई साहब, यहां विवाद है, आप इसके अंदर मत जाइए। यह उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं और वे उसके अंदर नहीं गए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि न्याय और निर्णय करने वालों को स्पष्ट और तटस्थ होना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)... तभी समाधान निकलेगा ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is all. Please sit down. Nothing more will go on record. Shri Brajesh Pathak.

**श्री अनिल माधव दवे** : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing more will go on record.

**श्री अनिल माधव दवे** : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dave, it is not going on record. Shri Brajesh Pathak, आप सिर्फ पांच मिनट बोलिए।

**श्री ब्रजेश पाठक** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय धन्यवाद। आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहिन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अपने विचार रखने का मौका दिया है। मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूरी दुनिया के पैमाने पर, जहां कहीं भी इस तरह के कृत्य होते हैं, वहां मानवता शर्मसार होती है। चाहे उत्तर प्रदेश का कोई मामला

*Not recorded.

[श्री ब्रजेश पाठक]

हो, चाहे देश के किसी दूसरे हिस्से या दुनिया के किसी भी हिस्से का मामला हो, जहां-जहां मानवता शर्मसार होती है, हमारी पार्टी हमेशा उस कृत्य के खिलाफ होती है। आज गाजा पट्टी इलाके में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी सभी को है। वहां पर निर्दोष व्यक्तियों, महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों का नरसंहार हो रहा है। इससे पूरी दुनिया हतप्रभ है। सभी लोग इस कृत्य को उचित नहीं मान सकते हैं। हमारी पार्टी भी इस कृत्य को उचित नहीं मानती है। हम लोग शुरू से ही इस बात पर पक्षधर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। चाहे उस पक्ष के लोग मारे जाएं या दूसरे पक्ष के लोग मारे जाएं, मारा इंसान ही जाता है। ऐसी दशा में पूरी दुनिया में भारत की ओर से यह संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके का संघर्ष उचित नहीं हैं। मानवता को शर्मसार करने वाले जो भी कृत्य हैं, मैं उनकी निन्दा करते हुए, उन पर रोक लगाने की मांग करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसे कृत्यों पर हमें बातचीत से फैसले लेने होंगे और समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाना होगा।

सभापति जी, इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

**श्री उपसभापति** : धन्यवाद पाठक जी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ahamed Hassan, you have five minutes.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, it is his maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two or three requests to make their maiden speeches. So, I am making an announcement. Now, you stick to your party's time. In the next speech, we will allow it. So, stick to your five minutes.

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Sir, I will speak in Bengali, in my mother tongue. I will also speak partly in English. * Sir, I rise to speak in this Upper House of the Parliament about the tragic human disaster that is going on in the Gaza strip. At this moment when I speak here, the trained military force of Israel is creating havoc in the land of Gaza, killing hundreds of people and destroying the basic civil infrastructure in the area, which is necessary to contain human lives. Sir, we have to see that a trained State military power यह काम कर रहा है। They are killing women and children and demolishing numerous houses, hospitals and power stations. Sir, some people told that it is a war. It is an unequal war. एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री माइट इज़राइल है,जो गाजा पट्टी में एक मिलिट्री अभियान चला रहा है। Sir, we Indians want peace – peace for everyone. We Indians want peace for everyone. But we cannot see any possibility of establishing peace in Gaza strip. Israel did not even accede to just 2 hours of ceasefire to move the injured people. In the meanwhile, the number of dead people in Gaza has crossed 450, and the injured are more than 3,500. The number is increasing in every hour. Sir, 90 percent of the killed and wounded are civilians. More than 100 of the dead are innocent children. Sir, every heart will bleed if they see the

* English translation of the original speech made in Bengali.

horrific scene of scattered limbs of the dead children. Sir, it is a new holocaust. On the other side, so far 16 Israeli soldiers are also killed. The decided stand of our party – Trinamool Congress – under the leadership of Kumari Mamta Banerjee, is that we are totally against any kind of war and killing. I can say with conviction that peace cannot be established through the use of bombs and missiles shot from tanks and war planes. Destruction and death of innocent person cannot bring peace. Renowned British newspaper 'The Guardian' and the Arab League have already raised the question of war crime. I must repeat that more than 85 percent of Gaza casualties are civilian people, women and children. Sir, Gaza is a small piece of land which is densely populated with about 20 lakh people living with much difficulty. They are now homeless people, being chased out of their homeland. Israel is now occupying the very home they had been staying at, and the land they had been living upon. There has been a blockade in the area since 2006. There is a blockade imposed on Gaza from 2006. They are not even allowing any humanitarian aid to be shipped to Gaza. The people of Gaza, even under these circumstances, do not have a place to flee to save their lives. The inhabitants of Gaza have no place to flee. Sir, everyone, every people and every nation has the right to defend itself. Everyone has the right to live in peace – peace with justice, peace with human rights and dignity, political and social freedom. Sir, it is good that hon. Prime Minister of India in BRICS Summit signed a Resolution condemning the death and destruction unleashed in Gaza. Sir, lakhs and lakhs of Indians are working at West Asian countries. If the present situation continues, it may turn this region into more instability. It cannot be good for India and also for the whole world. Sir, we need a permanent solution to the Palestine crisis. The international community has recognized the 'two-State' theory to solve the issue. Presently, this is the only solution that we can perceive. There should be a permanent solution to this problem. The international community should come forward to solve this problem between two sovereign States.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that's all.

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, Israel is not ageing to the 'two-State' theory on the pretext of some or other reason. Our government should raised these issues in various international forums.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI AHAMED HASSAN: Just one minute, Sir. Our government should raise these issues in various international forums and should also try to establish peace in the region.

He should say this. *(Time-bell rings)* We should not shy away from the problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K.C. Tyagi.

SHRI AHAMED HASAN: Sir, just the last word. Please allow me.

SHRI RAM JETHMALANI (Rajasthan): Sir, I just want to respectfully enquire from you as to how much time you are prepared to give to an expelled Member from BJP.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: For me, every Member is equal, expelled or otherwise. There is no difference for me.

SHRI RAM JETHMALANI: It is not worthwhile, Sir. I would rather go and write my paper.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But your name is not there in the list. Now, Shri K.C. Tyagi.

**श्री शरद यादव** (बिहार) : उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : क्या आप बोल रहे हैं? आपका नाम कहां है?

**श्री सीताराम येचुरी** : ये के.सी. त्यागी जी की जगह बोल रहे हैं।

**श्री उपसभापति** : क्या त्यागी जी के बाद आपका नाम है?

**श्री शरद यादव** : नहीं सर, मैं त्यागी जी की जगह ही बोल रहा हूं।

**श्री उपसभापति** : ठीक है।

**श्री शरद यादव** : उपसभापति जी, मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं, श्री माधव दवे जी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी नहीं हुई, लेकिन आपका यह जो भाषण था, यह इस मौके का नहीं था। मेरी विनती है कि जो हालात हैं, चाहे इस देश की आजादी का आन्दोलन रहा हो, उसके बाद चाहे इस बाजू के लोग रहे हों, चाहे उस बाजू के लोग रहे हों, लेकिन देश की जो विदेश-नीति है, वह देश की सम्पूर्ण सहमति से बनती है। किन्तु यह मामला टलता रहा, यह इस देश के लिए ठीक नहीं हुआ और न ही इस सरकार के लिए ठीक हुआ। इससे हमारे देश की विदेश-नीति पर अकारण का शक-शुबहा बढ़ा है। जो जानकार लोग हैं, वे इसको समझते हैं।

जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, तो उन्होंने जिक्र किया कि कुवैत पर जब सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया था, तब उस देश को फिर से ज्यों का त्यों बनाने में कितने दिन लग गये थे। यहां भी इसी तरह का जुल्म हुआ। यह जगह की बात नहीं है, किन्तु यह एकतरफा हमला है। एक छोटे से हिस्से में, एक कोने में जो लोग बसे हुए हैं, एक तरह से उन्हें हम ऐसी हालत में खड़ा कर रहे हैं कि वे पूरी तरह उस इलाके को खाली कर दें। वह उन्हीं का देश था, लेकिन उन्हें एक तरह से कहा जा रहा है कि जहां जाना चाहो, जाओ। इस पर यह सदन मौन रह जाए, यह कैसे हो सकता है? मैं भारत सरकार से और सुषमा जी से विनती करना चाहता हूं, जो इतिहास है, उसकी ओर देखा जाए। जो बात माधव दवे जी कह रहे थे, बाकी मामलों पर भी वे

अपनी बात उठाएं, उनको कौन रोक रहा है, लेकिन वक्त के अनुसार नोटिस दे करके उठाएं, तो उस पर हम भी बोलेंगे। हम इस देश का हर तरह से हित चाहते हैं।

इजराइल और पैलस्टाइन का झगड़ा कोई मामूली चीज नहीं है। इजराइल के साथ पूरी दुनिया है, यह बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जो प्रभुता वाले राष्ट्र हैं, वे उससे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उससे उनके हित जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे हित वेस्टर्न एशिया से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वक्त की कमी है। इसके बारे में श्री गुलाम नबी आजाद जी ने विस्तार से कह दिया है। लेकिन, यह जो मामला टला है, यह आपके लिए ठीक नहीं है और इस देश के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी कितनी कमाई और हमारा कितना हित इससे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कह रहे थे कि हमारे यहां से लोग वहां कई तरह की इंडस्ट्रीज और कारखानों में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के जो पैसे वाले लोग हैं, वे कितना पैसा वहां लगा रहे हैं, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार से उसे आपके सामने रखता। यह क्या बात है? सुषमा जी नहीं होतीं, तो कोई दूसरा मंत्री वक्त देता। हम कहां यह कह रहे हैं कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है, इस सरकार का अगुआ इस मामले में वहां सहमति करके दस्तखत करके आया है, फिर आप क्यों एतराज कर रहे हैं? वे किसी देश में जाते हैं तो उनका ...(**व्यवधान**)...

**श्री अनिल माधव दवे** : सर, ...(**व्यवधान**)... दूसरे दिन रेलवे बजट प्रस्तावित था। ...(**व्यवधान**)...

**श्री शरद यादव** : मैं कहता हूं कि रेलवे बजट आगे-पीछे हो सकता है। ...(**व्यवधान**)... वह भी पीछे हो गया। उसे भी हम नहीं कर पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं निश्चित तौर पर इस देश के नाते बोल रहा हूं, मैं कोई पार्टी के नाते नहीं बोल रहा हूं। यानी यह इस देश की आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे मत भूलना। आजादी की लड़ाई में जो मुद्दे उछले थे, जो मुद्दे बने थे और जो सपने बने थे, यदि आप उन्हें तोडेंगे, तो मुल्क चलाना मुश्किल होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे मानस में इधर-उधर की बहुत बातें होती हैं, लेकिन इसका ***...(समय की घंटी)...*** यह आपने टाइम का क्या मामला किया है? ...(**व्यवधान**)... यह कोई साधारण बात नहीं है। मैं पूरे सदन का सम्मानित नेता हूं। मेरी बात नहीं सुनी जाएगी? मैं उस सदन में गया हूं, वहां मुझे कोई नहीं रोकता था। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति जी, मुझे वहां कोई रोकता नहीं था। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : मैं क्या करूं? ...(**व्यवधान**)...

**श्री शरद यादव** : मुझे अफसोस है। अभी दूसरे लोग भी बोलेंगे। उनकी भी यह वेदना है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : मैं क्या करूं? ...(**व्यवधान**)...

**श्री शरद यादव** : आप क्या करें? आप टाइम बढ़ा दीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है? ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : टाइम ओनली वन ऑवर है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री शरद यादव** : अगर यह देश इधर से उधर जाएगा, तो आने वाले भविष्य पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसका असर नहीं पड़ता, तो मैं यह बात नहीं बोलता। मैं आपका आदर करता हूं। मैं तो आपकी सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं। आप मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन एक बात बताइए कि पांच मिनट में मेरे जैसा आदमी क्या बोले?

**श्री उपसभापति** : सबकी प्रॉब्लम यही है। ...**(व्यवधान)**... सबकी यही प्रॉब्लम है। मैं क्या करूं? ...**(व्यवधान)**...

**श्री शरद यादव** : मैं क्या बोलूं?

**श्री उपसभापति** : ठीक है, आप बोलिए।

**श्री शरद यादव** : यदि यही आपका आदेश है, तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन, सुषमा जी, मेरी विनती है कि इस मामले में एक तरह का जो भ्रम देश में बन गया है, इसे आज आप पूरी तरह से समाप्त करिए।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : कर देंगे।

**श्री शरद यादव** : आप इसको पूरी तरह से समाप्त कीजिए। माधव दवे जी, आपकी किसी भी बात से मैं असहमत नहीं हूं। इराक में जो चल रहा है, उस पर आप नोटिस लाइए, हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन, आज के दिन तो उन लाचार, बेबस, तनहा तथा अपनी धरती, अपनी जमीन और अपने घर से हटा दिए गए लोगों के साथ यह जो व्यवहार हो रहा है कि वहां की मां, बहन, बेटी और बच्चे, अस्पताल और छः किलोमीटर की breadth वाला इलाका, इसको आप कुचल कर कहां जाएंगे? यदि ऐसा हो गया, तो प्रभु राष्ट्रों ने तो पूरे दुनिया में तबाही मचा दी। उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि अफगानिस्तान तबाही में है, इराक तबाही में है और लीबिया भी तबाही में है। आज आप जान लीजिए कि सवाल आपने धर्म का कहा। अब क्या करें, इंसान जो है, वह औरत और धर्म के बगैर नहीं रह सकता। इसे आप कैसे टाल देंगे? मैं तो कह रहा हूं कि दो चीजों के बगैर इंसान नहीं रहता है। सीधी बात यह है कि दुनिया भर की एक बड़ी आबादी के मन में उनके लिए हर तरह की दया, ममता और प्रेम छलकता है। ऐसी एक बड़ी आबादी हमारे यहां भी रहती है। मैं तो इस बात के लिए उन्हें जिन्दा आदमी मानता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति** : अब आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री शरद यादव** : उपसभापति जी, ठीक है मैं आपके आदेश का कैसे पालन न करूं, लेकिन सुषमा जी, हम और आप बहुत वर्षों तक साथ रहे। मेरी चिन्ता यही है कि भारत सरकार हमारी सरकार है। कहीं ऐसा न हो कि ...**(व्यवधान)**...

**श्री रामदास अठावले** (महाराष्ट्र) : सर, ...**(व्यवधान)**...

**श्री शरद यादव** : मुझे ज्यादा छेड़ोगे, तो मेरे जैसी दाढ़ी करनी पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**... आपकी दाढ़ी छोटी हो जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

**1.00 P.M.**

सर, मैं आपका आदेश मानकर बैठ जाता हूं। लेकिन, मुझे अफसोस है, मुझे वक्त मत दीजिए, लेकिन सब लोगों का इतने कम समय में बोलना मुश्किल है। यह मामला देश के साथ, देश के हितों के साथ, दुनिया के हितों के साथ और इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : आपने मुझे सुझाव नहीं दिया। मैं क्या करूं? ...(**व्यवधान**)...

**श्री शरद यादव** : मेरी विनती है कि इसमें समय restrict करना मुझे उचित नहीं लगा।

**श्री उपसभापति** : आप सुझाव दीजिए।...(व्यवधान)...

**श्री गुलाम नबी आजाद** : वाइस चेयरमैन साहब, तीन दिन तो हमने हाउस चलने नहीं दिया, हमें बहुत अफसोस है कि हाउस नहीं चला, अगर हमारी मांग पूरी होती, तो इसको पहले दिन करते। ...(**व्यवधान**)... इतनी पार्टीज के लीडर्स इस पर बोलना चाहते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, पूरी दुनिया जैसे मैंने कहा, यूनाइटेड नेशंस से लेकर, ब्रिक्स से लेकर, यू.एन. के सेक्रेटरी जेनरल तक इस पर बोल रहे हैं और हम एक घंटे में क्या बोल पाएंगे? हम समय की पाबंदी में क्यों बंध रहे हैं? एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा जितना समय लगे, इस पर बोलने दीजिए।

†[**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد** : وائس چیئرمین صاحب، تین دن تو ہم نے ہاؤس چلنے نہیں دیا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہاؤس نہں چلا، اگر ہماری مانگ پوری ہوتی، تو اس کو پہلے دن کرتے- ---(مداخلت)--- اتنی پارٹیز کے لیڈرس اس پر بولنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل، نیشنل، پوری دنیا جیسے میں نے کہا، یونائیٹیڈ نیشنس سے لیکر، برکس سے لیکر، یواین کے سکریٹری جنرل تک اس پر بول رہے ہیں اور ہم ایک گھنٹے میں کیا بول پائیں گے؟ ہم وقت کی پابندی میں کیوں بندھ رہے ہیں؟ ایک گھنٹہ، دہ گھنٹہ، تین گھنٹہ جتنا وقت لگے، اس پر بولنے دیجئے

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have no objection in this suggestion. In the morning, we started this, the Leaders decided one hour and thirty minutes for this discussion. ... *(Interruptions)*...

**श्री नरेश अग्रवाल** : इसको बदल दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute. ... *(Interruptions)*... The House can extend the time. If the House wants to extend the time, I have no problem. If the Government also agrees, I have no problem. ... *(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir; extend the time. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want the view from this side also. ... *(Interruptions)*... We can take one hour more. We can take two-and-a-half hours. ... *(Interruptions)*... I want the view from this side also. Sushmaji, instead of one-and-a-half hours, we can discuss it for one more hour, that is, for two-and-a-half hours, if you agree.

---

†Transliteration in Urdu Script.

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत)** : माननीय उपसभापति महोदय, जो तय हुआ है, उसी का अनुपालन होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

**श्री नरेश अग्रवाल** : सर, इसके लिए वोटिंग करा लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, try to be brief. Shri Maitreyan, you have got five minutes. ... *(Interruptions)*...

**श्री नरेश अग्रवाल** : सर, टाइम एक्सटेंड कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, please extend the time. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There should be a consensus for that. There is no consensus. ... *(Interruptions)*...

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : सर, मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, लोग बोलना चाहते हैं, तो बोलें। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That means, we are extending the time for, maybe, one more hour. ... *(Interruptions)*... No; for two-and-a-half hours only. That is the rule. Rule is for two-and-a-half hours. I cannot go beyond that. That means, at 1.30 p.m. ... *(Interruptions)*... Please sit down. ... *(Interruptions)*... We will sit up to 1.30 p.m., then we take lunch-break for thirty minutes and then at 2.00 p.m., we will again continue this discussion for one hour. So, accordingly, time will be revised. Now, Dr. Maitreyan.

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Thank you, Sir. On behalf of All India Anna DMK, I strongly condemn the killing of innocent civilians in the Gaza - West Bank region. In fact, my Partly strongly condemns the killing of innocent civilians whether they are in Gaza, Palestine or in Ukraine or in the Syria-Iraq region or in Lanka. We do not discriminate at all. All innocent civilians, wherever they are killed, we strongly object to that and we strongly condemn it. In fact, ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Silence please.

DR. V. MAITREYAN: In fact, it is very unfortunate that more than 400 innocent civilians have been killed and more than 3,000 people have been very seriously wounded. Sir, I was very attentive to the speech made by our hon. Leader of the Opposition. Nobody can disagree with him when he said that the more than 3,000 people who were wounded, there were not enough hospitals, not enough medicines for them. It is a humanitarian problem. I entirely agree with him. It is a humanitarian issue. In fact, this House should condemn it. In fact, this House should pass a Resolution as demanded by our Leader of the Opposition. Nobody can disagree. I would like to bring to the knowledge of our hon. Leader of the Opposition that yes, there were aerial bombings; yes there were cluster

bombings; yes, there were chemical weapons used; yes, children were not spared; ten-year old, twelve-year old were also killed; yes, people were driven away from their own original land which belonged to them for centuries. Everything is more or less the same, but the only difference is, instead of 400 people being killed and 3000 people being injured, one-and-a-half lakh people were killed, and of them, in the last three or four years on the war, more than 40,000 people were killed. I would have been very happy if our Leader of the Opposition here had demanded the same condemnation in this House, had demanded the same Resolution being passed by this House. Unfortunately, for them their country was a friendly country. ... *(Interruptions)*...

**श्री शरद यादव** : मेरा प्वॉइंट ऑफ आर्डर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please.

**श्री शरद यादव** : मैत्रेयन जी, आप मेरे मित्र हैं।

DR. V. MAITREYAN: Sir, I am a *mitra* of everybody. ... *(Interruptions)*...

**श्री शरद यादव** : मैं यह कह रहा हूं कि मैं माधव जी के लिए बोला था। आप भी नोटिस लाइए। ...**(व्यवधान)**... हमने सपोर्ट किया है। ...**(व्यवधान)**...

DR. V. MAITREYAN: Sir, forget about the resolution condemning if, they did not even pass a condolence resolution. ... *(Interruptions)*...

**श्री शरद यादव** : आप बैठिए । ...**(व्यवधान)**...

DR. V. MAITREYAN: The mistake they did was ... *(Interruptions)*... Those one-and-a-half lakh people who were killed were poor Tamils. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: They did not even have a condolence ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: The reason why they did not bring a condolence resolution was that * ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: That is what we accused then. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: We accuse now also. ... *(Interruptions)*...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: I sincerely sympathise with the people who were killed ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan. ... *(Interruptions)*... आप बैठिए। The point is this. We are discussing a particular subject. That is a focused subject. If you want to bring in any other atrocity in any other place, of course, I am also concerned. I am equally concerned about the subject you are mentioning. I had gone to Sri Lanka. I am equally concerned. We can discuss that on another occasion. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, I am only supporting the ... *(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Let the House take note of it. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't bring it in between. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, I am only supporting the move of the Leader of the Opposition to bring a resolution here and to bring a condolence ... *(Interruptions)*... But I want you to apply the same yardstick to my Tamil brethren also. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you doubt? ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, let him bring a resolution condemning the killings of innocent civilians, the Tamil brethren in Lanka, and pass a condolence resolution... *(Interruptions)*... If he moves that also now, I am willing to support him. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is another subject. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: The concept of the resolution was moved by the Leader of the Opposition, Sir. ... *(Interruptions)*... That is why I am appealing to him. ... *(Interruptions)*... That is why I am appealing to him. ... *(Interruptions)*... The problem is that when you think that my enemy is your friend, I am forced to think that you are also my enemy. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this? ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, I am saying this with anguish.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not enemies. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, I am saying this with anguish. ... *(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, this should be expunged. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will have to look into that and remove that. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, I have not spoken anything unparliamentary. ... *(Interruptions)*... It might have hurt some of our friends ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will look into it. ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Sir, what about the years of wait? ... *(Interruptions)*... Not a single condolence resolution was passed in the House on this issue. ... *(Interruptions)*... Sir, I support the Leader of the Opposition. ... *(Interruptions)*... Bring a resolution. ... *(Interruptions)*... We will support you. ... *(Interruptions)*... My party's eleven Members of Parliament, on the instruction of my party leader *Puratchi Thalaivi Amma,* will support the resolution condemning this provided you condemn that also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Maitreyanji , we are all concerned about the killings. ... *(Interruptions)*...

**प्रो. राम गोपाल यादव** (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह जो समस्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने इसकी जड़ की तरफ इशारा किया था। हम सब जानते हैं और जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, वे भी जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज की नीति के चलते सारी दुनिया से यहूदी धीरे-धीरे फिलिस्तीन पहुंचने लगे और एक साजिश के तहत यहूदियों को इतना मिलिटेंट बनाया गया, इतनी ताकत दी गई कि वे अपने होम लैंड की मांग करने लगे और इसके पीछे इशारा ब्रिटेन का ही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लोग पराजित हुए उनके कब्जे में जो हिस्से थे, वे लीग ऑफ नेशंस के लिए जरिए कुछ देशों को दे दिए गए कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन आप करें। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन की व्यवस्था कर दी गई कि इसका प्रशासन ब्रिटेन देखेगा। यह सब जानते हैं, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद ब्रिटेन ने एक दिन अकस्मात् जबकि चर्चा चल रही थी, अपने को विद्ड्रा कर लिया। महोदय, उस वक्त तक यहूदी इतने मजबूत हो चुके थे, इतने हथियार उन्हें दे दिए गए थे और ओरिजनली इजराइल का नाम देश नहीं था, केवल फिलिस्तीन था, उस पर से जब ब्रिटेन ने अपने को विद्ड्रा कर लिया, उसका कोई प्रशासक नहीं रहा, अगले दिन यहूदियों ने फिलिस्तीन की जगह इजराइल राज्य की घोषणा कर दी और उसके अगले ही दिन अमेरिका ने उसे मान्यता दे दी। उस दिन से यहूदियों ने फिलिस्तीन के रहने वाले लोगों को, जो उनका मूल रूप से घर था, उन्हें बेघर कर दिया। उनमें से कोई लेबनान चला गया, कोई सीरिया चला गया, कोई मिस्त्र चला गया, कई लोग कैंपों में रहे और उन कैंपों में लोग मारे भी गए। फिर पी.एल.ओ. एक संगठन बना और यासिर अराफत के नेतृत्व में उनका लगातार संघर्ष चला। उसमें भी जाने कितने लोग मारे गए?

महोदय, मैं कहना यह चाहता हूं कि ब्रिटेन ने इस मामले को बढ़ाया और जैसे ही इजराइल राज्य बना, अमेरिका ने इसे ताकत दी। महोदय, पहले दिन से ही हिन्दुस्तान की यह पॉलिसी रही है और पंडित नेहरू ने शुरू में कहा था कि जब भी अगर कहीं अत्याचार होगा, अन्याय होगा तो

[प्रो. राम गोपाल यादव]

हम तटस्थ नहीं रह सकते। मैं माधव जी की एक बात से सहमत नहीं हूं। हमारी विदेश नीति में तटस्थ शब्द नहीं था, हम नॉन अलाइंड थे, हम असंलग्न थे। पंडित जी ने कहा था कि असंलग्नता का मतलब तटस्थता नहीं है। अगर कहीं अन्याय होगा, तो हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे, जिसके साथ अन्याय होगा, हम उसकी मदद करेंगे। शुरू से लेकर आज तक हिन्दुस्तान ने मिडिल ईस्ट में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसमें चूंकि न्यायवाला पक्ष फिलिस्तीन का था, इसलिए न्याय का साथ दिया। उसका साथ दिया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इस स्थिति में इतने गंभीर विषय पर जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हो, हमने चर्चा तक देर से शुरू की। श्रीमन्, मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है, तो देश का हित सर्वोपरि होता है। उसमें सारे सिद्धांत आगे-पीछे छूट जाते हैं और राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। अभी शरद यादव जी भी बता रहे थे और आप सब जानते हैं व सारा देश जानता है कि मिडिल ईस्ट से कितने बड़े पैमाने पर हमारे यहां पैसा आता है। मिडिल ईस्ट जिसे कुछ लोग पश्चिमी एशिया कहते हैं, वहां कितने लोगों को जॉब मिला हुआ है। इसलिए हमारा हित इसी में है कि मिडिल ईस्ट में काम करने वाले हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें। वहां इजराइल जो कार्यवाही कर रहा है, वह अमेरिका से प्राप्त हथियारों के बल पर कर रहा है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका जो हथियारों का बड़ा सौदागर है, उसके पूरे बिजनेस पर यहूदियों का कब्जा है। वे अमेरिका में जिसे चाहते हैं, राष्ट्रपति बनवा देते हैं। उनके पास इतनी ताकत है। इसलिए अमेरिका में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति हो, वे हमेशा इजराइल का समर्थन करते हैं। महोदय, इजराइल वह देश है जिसने यूनाइटेड नेशंस के सर्वसम्मत प्रस्ताव की भी परवाह नहीं की क्योंकि वह जानता है कि उसकी पीठ पर अमेरिका का हाथ है। तो जब इजराइल अन्याय कर रहा है, उसकी भर्त्सना करने में, उसे कंडेम करने में, उसकी निंदा करने में हमें क्या दिक्कत है?

महोदय, सुषमा जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। वे जानती हैं कि हमारे देश का इंटरेस्ट इसी में है कि मिडिल ईस्ट में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, उनके हित सुरक्षित रहें। जो हमें फॉरेन करेन्सी आ रही है, वह सुरक्षित बनी रहे। यह तो इसी में रह सकती है कि इजरायल वाले मामले में जो फिलिस्तीन लोग हैं, जो अरब लोग हैं हिन्दुस्तान उनकी मदद करे, उनका समर्थन करे और जैसी शुरू से हमारी नीति बनी रही है, उसको किसी तरह से डिसकन्टिन्यू न करे। सरकारों के बदलने से, या इधर से उधर होने से विदेश नीति कभी नहीं बदलती है। तमाम दूसरी ऐसी बातें हो सकती हैं जो बदल जाती हैं, लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती है, क्योंकि विदेश नीति में राष्ट्र हित जुड़ा होता है और हमारा राष्ट्र हित इसी में है कि हम अपने लोगों को वहां बचाए रखकर वहां से जो हमारे देश में पैसा आता है, जो लोगों के काम आता है, वह बचा रहे। इसलिए मेरी मांग है कि इजरायल के इस हमले की यह सदन निंदा करे, जैसे इराक पर अमरीका का हमला हुआ था तब भी निंदा हुई थी, लेकिन तब भी आप लोग डरे थे, 'कंडेम' और 'डेप्लोर' शब्द पर कई दिनों तक झगड़ा रहा था, हिन्दी में 'निंदा' कहा गया और अंग्रेजी में 'डेप्लोर' कहा गया। उस समय इधर आप लोग थे। ऐसा हुआ, लेकिन मैं मांग करता हूं कि सदन इजरायल की निंदा करे, जिस तरह की कार्रवाई इजरायल कर रहा है, जिस तरह से बच्चों, लड़कियों, माताओं, बहनों और निर्दोष लोगों पर हमला किया जा रहा है, उसकी कठोर शब्दों में यह सदन निंदा करे और फिलिस्तीन को मोरल सपोर्ट प्रदान करे। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sitaram Yechury.

PROF. SAID-UD-DIN SOZ: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do you want?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: I am on a point of order. I respect Madam Sushma Swaraj because she is a balanced, better politician and good behavior. But she has made a very brief statement here. She wrote a letter to the hon. Chairman. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is no point of order.

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Rule 258 says ... *(Interruptions)*... Just listen to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the rule?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Rule 258.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know that.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): What is the point of order during Short Duration Discussion?

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Kindly hear me. She wrote a letter to the hon. Chairman ... *(Interruptions)*... She made a brief remark on that day. ... *(Interruptions)*... She has said that neither it is admissible nor ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. it already admitted. ... *(Interruptions)*... Not allowed. Mr. Yechury, please. Mr. Soz, please sit down. ... *(Interruptions)*... I have given the floor to Mr. Yechury. Mr. Soz, please sit down. The floor is given to Mr. Yechury. Mr. Soz, why are you doing this? Mr. Yechury, please.

SHRI SITARAM YECHURY: Mr. Deputy Chairman, Sir, please start counting my time from now. Don't stop in between.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Agreed.

SHRI SITARAM YECHURY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise here with a great degree of anguish and concern. I share the opinion of everybody who said that there are also atrocities elsewhere in the world, so, we should condemn them. I fully agree. Please come forward and condemn the U.S. aggression that has happened in Iraq, please come forward and condemn what has happened in Libya, please come forward and condemn what has happened in Syria. I appeal to my friend, Dr. Maitreyan, to condemn all that, including the question of Tamils in Sri Lanka; and condemn every atrocity against

[Shri Sitaram Yechury]

humanity. We are for that. But what we are discussing today is simply the unacceptable and inhuman atrocity in the Gaza Strip. There is only an Urdu word that can explain it and that is called *insaniyat*. This is something against *insaniyat*, completely anything concerning basic elementary human values.

Sir, as we have discussed this morning, 476 people were killed, more than 3,000 injured, one-third of them were women and children. According to the United Nations, seventy seven percent of them were civilians. This sort of 'genocide' is taking place today. I use this word deliberately. It has been condemned by the United Nations Security Council saying that it is violative of the international humanitarian laws.

It is being termed by the U.N. Secretary - General as atrocious, and this is something where we cannot remain silent to continuous violations of international law, the accepted U.N. Security Council Resolutions. Therefor, Sir, I demand two things, in addition to the demand that has been raised here, namely, a resolution condemning this is the Resolution where we have condemned the U.S. aggression, the military aggression against Iraq in the past. Yes, it was the NDA Government at that point of time headed by Shri Vajpayee, and I know for fact, -- it is on record and a history now – that Mr. Vajpayee used this on a number of occasions to India's advantage by telling them, "We have a democracy and my Parliament in India has condemned it. Therefore, I will have to take this and use this for our advantage in international fora." And this is what has been done by various democracies. The U.S. President repeatedly uses the Congress's Resolutions whenever he doesn't want to agree to anything. And here, when you have this august House demanding a resolution, please accept that. This is my first point.

The second point which I want to make is, immediately suspend all military purchases from Israel. India is the largest military purchaser from Israel in the world. We are paying Israel the profits which they are using to do this genocide in the Gaza Strip. India cannot be a party for this genocide to continue. And what is the basic issue here? People here said, "You go to the basic issue." The basic issue is, my good friend Shri Ram Gopal Yadav, referred to the Balfour Declaration. But, I am saying, the basic issue is, even after that, if you take from 1947, for 66 years-plus, the Palestinians are being denied their legitimate right to a homeland. And it is this that we must oppose. Everybody has their legitimate right to a homeland. Denial of a homeland to Palestinians is the cause that is dear to all of us and until that demand is fully met, -- even the Prime Minister of India today has endorsed in the BRICS Declaration of a two-nation concept, through peaceful talks, with East Jerusalem as the capital of the State of Palestine and he has signed that Declaration – until that is accepted, India must suspend all military purchases from Israel and that is the only way by which pressure can be put on them. Now the argument that is being given is

that Israel officially has said, and I quote: "They are targeting those affiliated with Hamas terrorists." Whatever be my personal opinion or my party's opinion about Hamas, and I may consider many of their activities objectionable, but they have been democratically elected in their country to rule there as a democratically elected Government. I may have my hundreds of disagreements with the BJP today. They have been elected by the people of this country, and I will be the first one to honour this and protect this Government as Indian Government, wherever I am, in case, I think, my country is under attack or under danger. My political disagreements remain. But a Government of India is a Government of India. Here is a Government of Palestine which, in spite of whatever one may say, has been elected by Palestinians. The world recognized it. An International Team of Observers went there during elections and said that it was a democratically conducted election. Then, how are you saying that anybody affiliated with Hamas are terrorists? How is this being allowed? And the Defence Minister there goes on to say, "What is this affiliation?" He says, "We are destroying arms, terror infrastructures, command system, Hamas institutions, regime buildings, terrorist houses and killing terrorists of various ranks of command." Countries can go to wars. There have been three wars with Pakistan. But has there ever been a demand here saying that we are against an elected Government there? Can anybody say that we are going to unsettle an elected Government in another country and go to war? And that is exactly what is happening here. Can we accept that? Is that India's tradition, Sir? Now, if at all you want to go into the genesis, there is only one thing that I want to state very clearly in this House, which is my party's position, and I am very sure that a very large number of people would agree to this. Let Israel today vacate all the illegally occupied territories of Palestine and after that if there is one terrorist attack against Israel, I will be the first one to stand up here and condemn it and will ask the Indian Parliament to condemn it. As long as they occupy illegally Palestinian lands, there is no justification of terrorism involved. They are the biggest official terrorist occupying genuine lands of Palestine; that cannot be allowed and that is our tradition. You have heard Mahatma Gandhi's quotation here. We have grown up with that quotation. France is for France. England is for English speaking and Palestine is for the Palestinians. We have gone through that. We have got innumerable resolutions. Sir, remember, before this august House became the august House of an independent India, Pt. Jawaharlal Nehru convened the Asian Relations Conference in New Delhi, India, in 1947 and in that Conference, one of the earliest resolutions to be passed was on the question of Palestine. Sir, remember, India is the only non-Arab country in the world that opposed the partition of Palestine in 1947. Please remember our history. Every one of us is part of that history. All that we are saying today is that India must exercise its force. India must exercise its basic moral force and the little economic force it has. Stop your arms' purchases from Israel and you will cripple Israel profits of attacking the Palestinians. At least suspend

[Shri Sitaram Yechury]

them now till the violence in Gaza Strip is over. And remember, Sir, we recognize Israel. The P.V. Narasimha Rao's Government recognized Israel. We were critical even then, but there was a point then. That is when Mr. Yasser Arafat said, 'For the first time Israel has accepted in the Oslo talks that were going on that Israel has agreed to two-State solution, a State of Palestine with East Jerusalem as the Capital.' That is when India recognized that. Otherwise, I have travelled, you must have travelled, all of us have travelled on passports that were printed. It was not valid for Israel and South Africa. That is exactly what Mr. Narendra Modi, as the Prime Minister of India today, in the BRICS Declaration has endorsed and signed saying, *(Time-bell rings)* – please, Sir, -- a two national solution with East Jerusalem as the Capital. He signs it, Sir, in the BRICS Summit. Why are we afraid of today moving this Resolution? Therefore, finally what I would like to say is that do not reduce this. Please do not reduce this. I heard the ruling party Members speaking here. But I am pained to hear this. Don't reduce this as though it is some sort of a communal relationship between various issues. You don't need an Abdul Gaffer Khan type of person. Of course, we need an Abdul Gaffer Khan type of personalities always. We want such personalities. But don't have those imputations. Like once it happened, we were very unfortunate, Sir, that a former External Affairs Minister of India, when he actually talked of saying that we are today supporting Palestine cause because we are appeasing the Muslims in India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please conclude.

SHRI SITARAM YECHURY: Please don't reduce my time. I am thankful to my friend, Mr. Mani Shankar Aiyar, for pointing this out. Finally, therefore, I am saying that there are also a lot of evidences. If you don't permit me, I can't help it, but I think the august House will also benefit that how – just one reference I will make before I end, Sir – here I have references of Israeli Members of Parliament who actually say that the civilians have to die, they are producing the terrorists of the future; therefore, all the mothers have to be killed. Sir, this sort of a thing comes and, then, Israeli historians who have gone on record, Mr. Sternell, historian at the Hebrew University of Jerusalem, says and I quote, Sir, "Israel thought it was a smart ploy to push the Islamists against the PLO". And they, therefore, supported Hamas in the initial stages." Whatever be those facts, here is an elected Government. You negotiate; you have a two-State solution, with East Jerusalem as the Capital and stop this genocide.

Therefore, I reiterate, finally, two demands. The first one is that we pass a resolution like we passed when the US invaded Iraq. And the second one is, the Government should be urged immediately by the House to suspend all military purchases from Israel and that is the only way in which we can express our solidarity. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House adjourned for thirty minutes.

*The House then adjourned at thirty minutes past one of the clock.*

*The House re-assembled, after lunch, at two minutes past two of the clock,*

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Majeed Memon.

**श्री नरेश अग्रवाल** : माननीय उपसभापति जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग इस विषय पर गंभीर नहीं हैं।

**श्री उपसभापति** : ये लोग लंच के लिए गए हैं।

SHRI MAJEED MEMON (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, my time begins now, the stop watch is there and for such a sensitive matter where we are talking of humanity as a whole, we are talking about India's image and reputation in the world, we should have such constraint that we have to curtail our talking seconds ! I am extremely sorry about it. Nonetheless, thank you very much for extending to me this benefit of speaking on this occasion. Several friends before me have already highlighted what has been happening in Gaza during the past few couple of weeks. But, I will only talk about what precisely happened even yesterday. Every moment, while this House is discussing this issue, in a sense, people are being killed every hour. Yesterday, the Shifa Hospital Director Nasir said that 17 children, 14 women and 4 elderly persons were among the 87 killed on Sunday itself, yesterday. We must understand the gravity when we talk of humanity, we should forget who are the victims or who are against us. But, when we are condemning this massacre, I am sorry to refer to what has come from the Treasury Benches. They said, 'Well, this kind of bloodshed is going on all over the world, why do we not discuss other things?' Well, as my friends have already said, we have to discuss every case of innocent people being killed, But, today, the subject is that of Gaza and we must confine ourselves to this. Now, I must only say this, Mr. Deputy Chairman, Sir, that we are silent spectators to what has been happening during the past two weeks. I am quoting here the famous words of Martin Luther King Jr., when he said, "The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by bad people, but silence over that by good people." How can we be silent? Why didn't India for all this while raise an objection to this civilian killing at the hands of Israelis? Now, we may dispute it. Well, we may have some interests with the Israel Government; we may have some kind of trade, commerce or any other interest with them. But, then, if you want to do justice, if you want to be a subscriber to truth and justice, then, please remember that if I enter your house and start creating trouble, you can't ask the other person to be the aggressor. Who is the aggressor, who is the victim, need not be elaborated any further.

[Shri Majeed Memon]

Sir, as Shri Sitaram rightly, said, and, I, on behalf of my party, say that a very hard-worded resolution be passed, condemning every single human killing. In keeping with what Shri Yechury suggested, I fully endorse that we must express our anguish at Israel's conduct.

Mr. Deputy Chairman, Sir, before ending my speech, I would say that when Civil War was on in America, centuries ago, Abraham Lincoln was asked by one of the field persons, "Sir, you know that war is evil, and you can stop the war in a minute". Abraham Lincoln said, "It is the weakness and jealously and folly of man that makes a thing so wrong possible that we are all weak, jealous and foolish, that is how the world is, and we cannot outstrip the world". This was centuries ago. Now, the whole world has progressed so much over the centuries. We are not that weak; we are not that jealous; we are not that foolish; and we must stop war at all costs.

Before I wind up, Sir, since I have a very little time, I must only quote a few beautiful couplets by Sahir Ludhianvi:

जंग मशरिक में हो या मग़रिब में, अमने आलम का खून है आखिर,
खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर।
जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी।
आग और खून आज बख्शेगी, भूख और ऐहतयाज कल देगी।

इसलिए ऐ शरीफ़ इंसानों, जंग टलती रहे, तो बेहतर है, आप और हम, सभी के आंगन में शमां जलती रहे तो बेहतर है।

Rise for Palestinians; rise for the victims; rise for the oppressed; as your silence is becoming culpable. So, I am sure that the House, with absolute majority, will adopt a very strong-worded resolution, condemning every killing and also finding fault with the aggressor without reservation, without any other external interest. Thank you very much, Sir.

SHRI D. RAJA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand to condemn the killings of Palestinian people, largely the children, by Israeli forces. We, the Communists, always stand up against genocide, human rights violations wherever they take place. Sir, Israel has a declared agenda behind the current war. Firstly, to sabotage the Fatah-Hamas unity in West Bank on Gaza, and to demonize the Hamas which has the popular support of the people of Palestine; secondly, to deny full fledged sovereignty to the people of Palestine; and, thirdly, to oppose any peace deal with Iran and the West. This has been made very clear by the Israeli Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu in a Press conference recently.

Sir, in the name of fighting Hamas, a full-scale war is continued against Palestinian people. It is the character of all those war-mongers, all those who commit genocide and human rights violations in the world. We had the experience of what happened in Sri Lanka. In the name of fighting LTTE, a full-scale war was waged against Tamil people. Even today, there is no political solution to the Tamil problem. There is no credible investigation into the war crimes, human rights violations and genocide which took place in Sri Lanka. That is why I urge upon this august House to give serious thought to what is happening in Gaza. It is not just a conflict between two countries; it is a conflict between an occupier and occupied; it is a conflict between the aggressor and the victim. India should be on the side of occupied and victims. India should be on the side of the Palestinians. It is not that today I am asking the NDA Government or the BJP-led Government to be on the side of Palestinians. Since the days of Mahatma Gandhi we have been supporting the cause of Palestinian people. India should have a moral political position on this issue. India has a stature; it has a status in the comity of nations. India should not behave like any other country. India has its own position on the international arena. That is where I think now India must take a categorical stand condemning Israel, and, at the same time, extending solidarity and support to the people of Palestine. Sir, India and Palestine relationship went to the height when Madam Indira Gandhi was Prime Minister, Mr. Yasir Arafat was lending the PLO and India was one of the first countries which recognized the Palestinian cause. Why should India now keep equidistance at this crisis time? Why should India keep equidistance between Palestine and Israel? What is the justification? The Government of India should understand. I think we should take note of what Ban Ki-moon, the Secretary – General of the United Nations has said. He has condemned Israel. He has said that what Israel is doing is atrocious and is a gross violation of human rights. It is not only Ban Ki-moon, take the statement made by Madhu Pillai who is the Chairperson of the United Nations Human Rights Commission. She has condemned Israel and she has called upon the world to express its view on this issue. In such a situation. India should not keep quiet or India should not maintain equidistance. I think there is a need for resolution to express India's position in clear terms. There is nothing wrong in India expressing its stand through a Parliament resolution. In the past on several issues, we have such resolutions and India expressed its position in a Parliament resolution. I think there is a point in what LOP is saying or my colleague, Shri Sitaram Yechury and others have been saying that we need to pass a resolution. I also agree that it is time India reviewed its position towards Israel concretely saying India's present position to buy arms from Israel. India is the second largest purchaser of arms or Israel is the second largest country from where we purchase arms. India should suspend the purchase of arms. India should send a message to Israel that if what is happening in Gaza continues, India cannot have such a relationship with Israel and India will suspend

[Shri D. Raja]

its purchase of arms from Israel. Such a strong message should go. Therefore, I think it is time that India strongly condemned the Israeli aggression, the war that has been waged against the people of Palestine and India should extend its support and solidarity with the people of Palestine. Indian Parliament should pass a resolution on this issue. India as a nation should give a strong message to Israel that India is considering the suspension of arms purchase from Israel. Let us forget for a minute which party we belong to, you belong to BJP or I belong to CPI. It is an issue concerning a section of the humanity. For how many decades can the Palestinian people undergo such suffering? I am asking you. Let us touch our conscience. Let us speak out. If India cannot speak, I don't think we are doing service to our country. India, as a nation, should take a moral political position. *(Time-bell rings)* Ours is a great civilization. In the name of that great civilization, I appeal to the House that we should take a moral political position to condemn Israel and support the Palestinian people and their cause at this moment of time in history of the world.

SHRI ANAND SHARMA (Rajasthan): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. This House has been discussing the situation in Gaza and the West Asia, in particular, with regard to ongoing cycle of violence and killings, which is a matter of grave concern for the entire world, and has been affirmed as such by the UN Security Council, by the UN Secretary-General, by the major countries of the world. They have not only expressed their concern, but have also criticized and condemned the violence. We have to understand, as the LOP, Shri Sitaram Yechury, Prof. Yadav, Sharad*ji*, and other speakers have said, India has historically always had a position, a position with regard to the rights of the people, the rights of the people of Palestine to have a secure homeland of their own, a sovereign country within defined borders, with their own capital, so that they can – after the tragedies of decades that was forced upon them – live a life of dignity and freedom, which every citizen of the world is entitled to, which has wrongly and unjustly been denied to them. It is not today that India is speaking. Right from 1917 that position has been there. But, particularly after 1967, when there was annexation and the occupation of the land belonging to the Palestinian people, that land should be vacated and they should be allowed to have a country of their own.

It is only the violence, the attacks, but it is also the use of brute force, disproportionate force, indiscriminate usage of the force, which is in particular targeting the civilian population. When a conflict takes place, Yes, there is damage caused. But, here, we have to be very clear in our understanding about the history as to why this has happened. It is not a development of today. It is because of the denial, because of the injustice that this situation has continued to fester. In Gaza, in particular, since 2006 there has been siege. People in Gaza are living in an open prison. They cannot go out of Gaza. They cannot come back to Gaza. And, when there is any conflict or tension, even if there is a minor

conflict, humanitarian assistance does not reach them, food and medicines do not reach them. And, for this, the international community is compelled to intervene.

Sir, as we are discussing this matter today, we know that there are efforts afoot internationally to bring about a cessation of the hostilities, to negotiate a cease fire, the UN Secretary-General, whose statement was quoted here, yesterday left for Doha in Qatar. And, what my understanding is, all concerned parties are meeting there. There have been earlier attempts by Egypt, by the Arab League, which were not successful. I was, over the days, listening very carefully what position India has taken. Other countries have spoken – including the UN Secretary-General, UN Security Council – and have not only disapproved, but condemned. Even the United States of America is critical of misuse of Force and killing of women and children. India's lack of response, India not speaking out and India not making an effort should concern us. India has always had a bipartisan approach when it came to humanitarian issues and when it came to fight for justice, for liberation. When people fought for their freedom, whether it was in Asia or in Africa or in Latin America, India always stood up. When there was a big fight against apartheid, again colonialism in Africa. It was Pandit Jawaharlal Nehru – soon after India's independence the 1947 Asian Relation Conference which was referred to – who said that India's independence shall not be complete as long as Africa is in bondage. So, today if it is being said, why we are discussing, we will be committing the grave mistake and disrespecting the tradition of this country, this Parliament, if we do not stand up and speak, speak what is morally correct, so that a message goes that the land of Gandhi, the land of Nehru, the land of Buddha is not going to remain silent when such atrocities are taking place.

Sir, I would like to say one thing. After the 1992 Oslo Accord, which was hailed by everyone, including the PLO, the Palestinian Authority was established. The Government of Palestine has first time got the recognition from many nations or most nations. India recognizes the Government and the United Nations also recognizes it. Sushmaji will go there for the UN General Assembly. You have been there in the past. They sit there as a country which has been recognized. The only thing is that their secure borders and their sovereignty remain a fundamental issue. Therefore, when we see that we have not reacted promptly, we ask for discussion. Sharad Yadav*ji* was right when he said, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को मान लेना चाहिए था। कोई वजह नहीं थी कि आप इस बात को न मानते। यह कोई विवादित विषय नहीं है। इसमें भारत की पोजीशन स्पष्ट है। अगर किसी नीति में बदलाव नहीं है, कभी सत्ता परिवर्तन से नीति में बदलाव नहीं होता, कम से कम विदेश नीति में तो नहीं होता है। विदेश नीति में आम सहमति होती है, देश की सहमति होती है, उसके बिना भारत की कोई विदेश नीति नहीं होती है। सत्ता बदलने के साथ देश की विदेश नीति नहीं बदला करती। And, particularly, as has been said here, Sir,

[Shri Anand Sharma]
the Prime Minister was away. It was being given as a reason. We fail to understand. He went for a Summit. The House did not discuss. That Summit adopted a declaration. We pointed out that. Para 38 of the Fortaleza Declaration refers to this issue, refers to Palestine, refers even to the United Nations' observing 2014 as a Year of Solidarity with Palestine. But, yet, we were silent.

Sir, I refer to the ceasefire since 2006. There were developments in 2008. Through you, I would like to inform this House that there was violence, there was attack by Israel and there was killing. At that time, again, Hamas was cited. But the fundamental issue is: do we make a distinction between the Palestinian people and the militants? That distinction was never made. Those who get killed, are actually helpless, innocent and poor people. India stood up then in 2008. There were two Statements issued by the Government of India. India talked to other countries. India was having the Presidency of the UN Security Council. We sent humanitarian assistance. We insisted that this should be allowed so that people in Gaza get medicines, get food and get what they require, which was allowed. In 2012, again, there were hostilities, there was attack; and at the time of the ceasefire what is very important for us to remember is, 2012 ceasefire made it clear that the siege will be lifted, the airport in Gaza will be made operational again, the seaport will be opened so that the people of Palestine, people living in Gaza and the authority and the elected Government there can operationalize and operate it. But that has not happened. The siege continues. The seaport is not with the people of Gaza. They cannot use the airport. They cannot freely move out. What the world is talking about is the tunnels, the tunnel system. It is only because of that through Egypt some tunnels were made which is in the knowledge of everyone and from where movement could take place – people who were sick could be taken out for medical treatment, some humanitarian assistance and supplies could reach. The situation has aggravated because of the developments also in Egypt and that region, and that is why the countries of Middle East are concerned. It is not a question of what happens in one part, it need not concern us. We know history and that has been said in great details by LOP and by my other colleagues. But what is important for us to understand is that India cannot disengage, India cannot be silent, India has to be proactive. Therefore, my question to the Government and to the hon. External Affairs Minister is: Did the Prime Minister discuss this matter in his bilateral meetings with the President of Russia , with the President of China, with the President of Brazil, with the President of South Africa? It is because we are still waiting to hear from the Government when the Prime Minister will come before the House to make the statement which he is obliged to make in both the Houses so that we get to know whether India raised this matter or not, whether India communicated its concern or not. I would also like to know whether India has taken this up at the United Nations formally. Have you written to the

UN Security Council which has already met and deliberated upon this more than once? When other countries have done it, if we have not – I will take two minutes more – why this has not happened, the House would like to know.

As I have said, it has to be a bipartisan consensus. It is not a partisan issue. We should speak as we have spoken in the past and, therefore, I would like to say two things before I conclude. The first is, like in the past in similar situations, is the Government of India going to announce immediately the humanitarian assistance which is badly needed by the civilians and the people there, and ensure that it reaches them as has been ensured by us in the past? Second that this House passes a Resolution in line with the UN Security Council deliberations, in line with the UN Secretary-General Ban Ki-moon has said yesterday and also in line with the Fortaleza Declaration of the BRICS summit. *(Time-bell rings)* Unless and until we do that, we won't convey a message that India stands in solidarity, India stands for its principles, India is consistent when it comes to the rights of the people of Palestine to have a State of their own and to live with freedom and in dignity.

DR. CHANDAN MITRA (Madhya Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in what has been a very detailed and, I would say, a knowledgeable debate. But, as expected, it has been more full of emotion than logic in many cases. But that was expected, of course.

Sir, since many points have already been made, I just want to make a few fundamental observations and I hope the House and the Government will be in agreement with them. Let us just lay down some of the core aspects of the issue at hand. Sir, it is obvious, and I think it is something that every Member of this House shares, that India can and shall never support any human rights' violations anywhere in the world. There has never been a question. We have ourselves been victims of human right' violations by other countries. So, as victims of human rights' violation ourselves, there is no question of India supporting human rights violations by any country anywhere in the world. So, I think this is an established corner stone of our foreign policy and must continue as that.

Sir, the fact is that hundreds of innocent lives have been lost, and nobody in his or her senses can possibly support the loss of innocent lives. This, again, is another cornerstone of our foreign policy, and we all stand united in condemning the loss of innocent human lives anywhere in the world. But, Sir, there is also another cornerstone of our policy, and that is that both the countries engaged in the conflict in Gaza are friendly towards India; both are our friends and we must keep that in mind that in matters of foreign policy, a particular tilt this way or that way could impact our overall foreign policy, economic stability, and so on and so forth. We all know that in Iraq Indian citizens are still either

[Dr. Chandan Mitra]

being held hostage or are unable to come out of Iraq because of various terrorist and other groups that are holding them hostage. We have to keep that in mind because this entire region is a disturbed area. It is an arc of instability and anything we do in the context of one country will have implications on another country and another situation. This is an area which supplies India with the maximum amount of oil and petroleum requirements and we need to keep that in mind as well. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ... *(Interruptions)*...

DR. CHANDRA MITRA: But similarly, we have to keep it in mind that India and Israel have long been friends. We have been repeatedly told about a bipartisan policy. Mr. Anand Sharma just reminded us of that bipartisan nature and even the hon. LoP had mentioned that earlier. Sir, after all, Israel was accorded diplomatic relations by a Government led by the late Shri P.V. Narasimha Rao of the Congress Party. So, the first major step in cementing India-Israel ties were taken by the Congress Government. That bipartisanship has continued and over time, India's relations with Israel have been strengthened, just as India has traditionally supported the Palestinian cause. We have to recognize that there is a balancing act that has been done by successive Indian Governments over many, many years. If you quote statements in support of Palestine, many statements could be support of Israel too, about Israel's right to exist. So, keeping that in mind, I think we need to be extremely careful as to what. ... *(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Can you yield for a minute? ... *(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I am not yielding. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, Mr. Rajeeve, please sit down. ... *(Interruptions)*... He is not yielding. ... *(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, the statement of the Government or Parliament supporting this or that. ... *(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: I am not yielding. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding.

DR. CHANDAN MITRA: The fact is that there has been a bipartisanship in India's relations with the Arab world, with Palestine and with Israel. Successive Governments have signed agreements with Israel for supply of military equipment, for agriculture and various other commercial activities. Similarly, the issue of Palestine has always been close to our hearts since the time of Mahatma Gandhi, as rightly pointed out by Members of the Opposition. So, Sir, we need not get too emotional about one issue without keeping in mind what is happening today, what may happen tomorrow and keeping a balance, because this is not the first time that this kind of a conflict has taken place.

Sir, there is a long history behind this and if you look at it, India has always supported the cause of Palestine. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ... *(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I would defer to Sharad Yadavji.

**श्री शरद यादव** : उपसभापति जी, चंदन मित्रा जी का भाषण दोनों को बराबर करने वाला है जबकि वहां एक तरफा से हमले और बुचरिंग लगातार हो रही है। मित्रा जी, आप तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं आप से विनती करूंगा कि इन दोनों को इक्वेट कर के क्या आप भारत के इतिहास को ही पोंछ देंगे? दूसरी बात, यह कि वहां जिस तरह एक छोटी सी पट्टी के इंच-इंच पर बम गिर रहे हैं, वहां बच्चे मारे जा रहे हैं और इज़राइल किसी की बात मानता ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे इक्वेट मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down. ... *(Interruptions)*... Sit down. ... *(Interruptions)*... Sit down. ... *(Interruptions)*...

**डा. चंदन मित्रा** : महोदय, मैं अपने वरिष्ठ नेता शरद यादव जी को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि दुनिया के जिस किसी भी कोने में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, भारत की यह परंपरा रही है हम उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ... *(Interruptions)*... Sit down. ... *(Interruptions)*... He is not yielding. ... *(Interruptions)*... आप लोग बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

**डा. चंदन मित्रा** : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते ...(**व्यवधान**)... समझना नहीं चाहते या समझने की शक्ति नहीं है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down.... *(Interruptions)*... Sit down. ..*(Interruptions)*...

**प्रो. राम गोपाल यादव** : आप इस कार्यवाही की निंदा कर रहे हैं या नहीं? ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : राम गोपाल जी, बैठिए। Sit down... मित्रा जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... अंसारी जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. ... *(Interruptions)*...

**श्री अली अनवर अंसारी** : *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ansariji, please take your seat. ... *(Interruptions)*... That is not going on record. ... *(Interruptions)*... That is not going on record. ... *(Interruptions)*... Sit down. ... *(Interruptions)*... Sit down. ... *(Interruptions)*... Ansariji, sit down, please. ... *(Interruptions)*... That is not going on record, Why are you shouting? ... *(Interruptions)*...

**डा. चंदन मित्रा** : सर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, अगर लोगों ने ठीक से सुना नहीं, समझा नहीं, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं।

---

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is saying only his opinion, not your opinion. ... *(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: I am not responsible if they have not understood. ... *(Interruptions)*... They don't want to understand. What can I do? ... *(Interruptions)*... Sir, I said that it is a fact that we have had very good relations with the Palestinians. We have supported the creation of Palestine Authority. Late Yasar Arafat was a regular visitor to India and we have accorded him the highest respect and welcome. At the same time, say, from the time of Shri Narsimha Rao, when India - Israel relations were formally established, India and Israel have had a very good relationship. ... *(Interruptions)*...

**श्री उपसभापति** : आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... यह उनकी राय है, आपकी राय नहीं है। ...**(व्यवधान)**... नरेश जी, आप बैठिए।

**डा. चंदन मित्रा** : देश की नीति क्या होनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Chandan Mitraji, please ignore comments. You address the Chair. ... *(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: I am trying to. But they are deliberately obstructing me. ... *(Interruptions)*... They do not even like what I am saying. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But they like you. ... *(Interruptions)*... Don't worry; they like you. You speak. ... *(Interruptions)*... Please sit down. ... *(Interruptions)*... Don't disturb, please. ... *(Interruptions)*...

DR. CHANDAN MITRA: I can only appeal that they should appreciate when somebody is I talking for the country and talking for India, instead of talking for some foreign country. ... *(Interruptions)*... Sir, I would like Members to remember that India has always supported a sustainable ceasefire in the Middle East. Even now, in this conflict, it must be kept in mind that all the major countries or those who are involved with the conflict, are appealing for the ceasefire. Egypt, the Palestinian Authority, the U.N. and even the Arab League have all appealed for a ceasefire so that the loss of human lives stops. India is totally in support of a sustainable ceasefire coming to effect immediately. That must be the first priority and if we can do anything for the ceasefire, India must do that. Let us not go into the merits, demerits, who is right, who is wrong at this point of time. The urgency is to stop this bloodshed, to stop the war. I am not going into the issue of who is responsible, who started it, who dug tunnel, who is doing this or who is doing that. The first thing is that people are dying. We have to stop those deaths. And, that is

where India, as a country which has always been a votary of peace, must intervene and act in solidarity with all those Arab countries which are working towards sustainable ceasefire. *(Time-bell rings)* I don't want to go into who has been violating the ceasefire, but the ... *(Interruptions)*... fact is that the ceasefire has to be made permanent. We urge restraint from all sides involved in this conflict. ... *(Interruptions)*... We must remember that India has a role of a votary of peace and this is what we must do. This is the traditional role we have played and we have to ensure that West Asia become an area of peace as it used to be.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, this discussion was first listed for the last week. Since that time, it is estimated that more than 470 civilians have been killed and thousands wounded. Some reports have indicated that there have been rocket attacks against innocent civilians. We are quite used to situations like that. It has even happened in our neighbouring countries. We were silent then, but, at least, it is very nice and it is very good that this House is coming together to pass a Resolution about this.

Though Israel has a right to defend itself, this House must condemn the disproportionate attacks, specially the use of indiscriminate force, which has resulted in the deaths of children, women and the elderly.

Sir, this also happened in Sri Lanka. We were silent spectators and nobody in the House, except for parties and Members from Tamil Nadu, had raised this issue. ... *(Interruptions)*... But then, they said that Sri Lanka was a friendly nation and a friendly neighbour. So, we could not say anything against Sri Lanka. So, I hope, after this discussion, this will be a precedent and later, we will have an opportunity to discuss Sri Lanka here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, Kanimozhiji, we are discussing something else.

SHRIMATI KANIMOZHI: Yes, Sir, I am only talking about a concern about both the places.

Sir, Archbishop Desmond Tutu once said, "if you are neutral in times of injustice, then you have chosen the side of the oppressor." India cannot be seen as siding with the oppressor. India cannot keep silent. India cannot say that we are neutral; both the countries are our friends and, therefore, we cannot interfere and take a stand in this matter. India cannot do this. We have to understand that it is not just a case of one country against the other. It is invasion. You are coming into other country's territory. You are taking away other people's land and this is aggression. This is taking away the rights of people and in this case, India cannot remain silent and say that we cannot take a stand in this. India has to set an example. Now, we are actually aspiring to become a world leader and you can't become a world leader just by improving economy or by trading with the world. We have

[Shrimati Kanimozhi]

to take stands when it comes to very important issues like humanitarian issues. India has to take a strong stand. Otherwise, we will be never become a world leader. Even the UN Secretary General, Ban Ki- moon, has condemned the ongoing violence. This morning, the UN Security Council has called for ceasefire but nothing has happened. So, India should take the lead. While making sure that other nations are also included , we should spearhead this.

Sir, there is one more thing, which I would like to bring to your notice, India was one of the first countries to recognize the State of Palestine in 1988 and India opened its representative office in Gaza in 1996. Sir, India co-sponsored the draft Resolution, 'The Right of Palestinians to self-determination" during the 53rd Session of the UN General Assembly, and, voted for it. After doing so much for the recognition of a nation, India, today, cannot move away from it, and, say, we will be just observers to this. Sir, we have to think of their rights. Sir, the killing of people is condemnable and it cannot be accepted but more than that, India has a duty to protect a nation, which is being invaded, and, against which aggression is being shown. India should take a stand and we have to pass this Resolution.

I really request this House to make sure that it will show more involvement and care, and another resolution will be passed in this House regarding what is happening in Sri Lanka because those people have not got justice till today. Thank you, Sir.

**श्री तरुण विजय** (उत्तराखंड) : आदरणीय उपसभापति महोदय, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी दानवी हरकत हो, पाशवी हरकत हो, अगर पहली आवाज उठेगी, तो वह हिन्दुस्तान की उठेगी, चाहे आप हों या हम हों। आनन्द शर्मा जी अपना होम वर्क करके नहीं आए। वे भूल गए कि जब वे पंडित नेहरू का नाम ले रहे थे, तो नरसिंह राव जी का नाम भी ले लेते, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम भी ले लेते। अगर फिलिस्तीन में किन्ही मजलूमों पर जुल्म होता है, तो राम गोपाल जी, शरद यादव जी और येचुरी जी, आपके साथ तरुण विजय और नरेन्द्र मोदी भी खड़े होंगे और यह हमने ब्रिक्स में कहा है। हमने कहा है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी दुनिया में किसी ने ऐसी दानवी हरकत की है, तो हिन्दुस्तान ने जो किया, उस पर हमारे इकबाल साहब, जो बाद में अल्लामा इकबाल कहे गए, उनके पुरखे कश्मीर से लाहौर में बसे थे, उन्होंने कहा था- "उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा।" जब संजान में पारसी उतरे, जिनको 80 देशों ने शरण देने से मना कर दिया था, जब हिन्दुस्तान में यहूदी आए जिनको तमाम दुनिया ने शरण देने से मना कर दिया, सेंट थॉमस जब केरल में आए, तो हिन्दुस्तानियों ने यह नहीं पूछा था कि बताओ, तुम्हारा मजहब क्या है? उन्होंने कहा था, शरण लेने आए हो, मुहब्बत का पैगाम लेकर आए हो, तो हम तुम्हारे साथ हैं। यह हिन्दुस्तान की विरासत और यह आपके और हमारे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत है कि जब चीन ने तिब्बियों पर अत्याचार किए, तो पंडित नेहरू ने दलाई लामा और तिब्बतियों शरण दी थी, हिम्मत की, चिंता नहीं की थी कि भविष्य में क्या होगा। येचुरी साहब ने कहा, इज़राइल से हथियार मत लो, मै समझता हूं कि जब चीन ने

तिब्बतियों के मानवाधिकारों का हनन किया, तो कोई यह भी कहता कि चीन के साथ संबंध न रखो, वह मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। कोई यह बात भी करता कि जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में ...(**व्यवधान**)... अत्याचार किए, तो तब यह बात कहते कि सोवियत संघ के साथ संबंध नहीं रखें, किंतु ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : मैंने कहा, हथियार मत खरीदो।

**श्री तरुण विजय** : सुनने की बात है ...(**व्यवधान**)... देखिए, यह बात गुलाग और साइबेरिया ...(**व्यवधान**)...

SHRI SITARM YECHURY: Sir, he is distorting what I said. ... *(Interruptions)*...

**श्री तरुण विजय** : जब तक मन की बात नहीं कहोगे, मैं सुनूंगा नहीं ...(**व्यवधान**)... और जब मेरे मन की बात कहोगे, तभी मैं सुनूंगा, तो यह गुलाग और साइबेरिया है, यह हिन्दुस्तान की जम्हूरियत नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : मुझे गलत रिप्रेजेंट मत करो। Sir, he is representing me wrongly. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you. ... *(Interruptions)*...

**श्री तरुण विजय** : अभी मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिक्स में उन्होंने तमाम बातें कही हैं और टू स्टेट्स की बात कही है। उन्होंने कहा है कि "We oppose the continuous construction and expansion of settlements in the occupied Palestinian territories by the Israeli Government." नरेन्द्र मोदी उस पर हस्ताक्षर करके आए हैं, आप क्या बात करते हैं? हिन्दुस्तान की बात करो। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : वह हमने कहा है, वह हमने कहा है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री तरुण विजय** : हिन्दुस्तान की बात करो। ...(**व्यवधान**)... आप जब बात करते हैं तो हिन्दुस्तान की बात करो। आप बात करते हो, 'तुम' की। 'तुम' की बात नहीं है, यह 'हम' की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 'we welcome recent efforts to achieve intra-Palestinian unity, including the formation of a national unity Government'. ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, आप लोग आधी बात बताते हैं क्योंकि आज फिलिस्तीन में फतह और हमास में आपस में झगड़े हैं। हम किसके लिए लड़ेंगे? हमास के लिए? हम हमास का साथ देंगे? दूसरी बात है। We cannot be more Arab than Arabs. We can only be more Indian than Indians. अरब यूनिटी नहीं है। फिलिस्तीन के बारे में कहां अरब एकता है? इजिप्ट संधि के लिए मदद कर रहा है, तुर्की संधि के लिए मदद कर रहा है? वहां के लोग चाहते हैं कि इज़राइल और हमास में संधि हो जाए। संधि हुई। आप वहां का बता रहे थे, मेरे पास हमास का वक्तव्य है जो कहता है कि इज़राइल के साथ हम संधि तोड़ेंगे, रॉकेट फेंकेगे। मेरे हाथ में यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी यू.एन.आर.डब्ल्यू.ए. का बयान है, जिसमें उसने कहा है कि हमास ने यू.एन.आर.डब्ल्यू.ए. के स्कूल पर बीस रॉकेट फेंके हैं और यूनाइटेड नेशंस ने इसकी भर्त्सना की है। मैं यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मित्रो, जब हिन्दुस्तान की बात हो तो हिन्दुस्तान

[श्री तरुण विजय]

का हित सर्वोपरि है - न इज़राइल का, न फिलीस्तीन का और न दुनिया के किसी मुल्क का - हमारा हित सर्वोपरि है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेल्यूट करता हूं। 1962 में जब कम्यूनिस्ट चाइना ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो पंडित नेहरू ने इज़राइल की मदद स्वीकार की, 1971 में स्वीकर की, 1970 में, Moshe Dayan हिन्दुस्तान आया। 29 जनवरी ...(**व्यवधान**)... मेरे पास कागजात हैं। I have the documents to prove.

SHRI ANAND SHARMA: This is incorrect. ... *(Interruptions)*... You cannot ... *(Interruptions)*... Will you yield? ... *(Interruptions)*... I request you to yield. ... *(Interruptions)*... One minute. ... *(Interruptions)*... One minute. ... *(Interruptions)*...

**श्री तरुण विजय** : 29 जनवरी 1992 को नरसिंह राव ने इज़राइल के साथ संबंध सुधारे और उसके बाद उन्होंने कहा ...(**व्यवधान**)... I am not yielding. ... *(Interruptions)*... I am not yielding. ... *(Interruptions)*... This is not democracy. ... *(Interruptions)*... आप यह नहीं कह सकते कि आपकी ही बात मैं कहूंगा। I will say what I have to say and you can ... *(Interruptions)*... Don't shout. ... *(Interruptions)*... You cannot do this. ... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no ... *(Interruptions)*... Mr. Vijay ... *(Interruptions)*...

**श्री तरुण विजय** : आप गुस्से में आकर मेरी आवाज दबाएंगे? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tarun Vijay, what happened to you? ... *(Interruptions)*... Mr. Tarun Vijay, what happened to you. ... *(Interruptions)*... Mr. Tarun Vijay, don't get agitated. ... *(Interruptions)*...

**श्री तरुण विजय** : आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन में हर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। यह हम कहते हैं। आप भूल गए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में कहा था, 2001 में उनका वक्तव्य आया था कि जब ...(**व्यवधान**)...

**श्री तपन कुमार सेन** (पश्चिमी बंगाल) : हमने बताया था। वाजपेयी जी को कोट किया था ...(**व्यवधान**)...

**श्री तरुण विजय** : जब कभी फिलिस्तीन में इस प्रकार का होगा...(**व्यवधान**)...

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Mr. Deputy Chairman, can he explain this? ... *(Interruptions)*...

**श्री तरुण विजय** : उन्होंने कहा कि India has consistently voted for a just and durable peace in the Middle-East. We are happy to enjoy traditional ties of friendship with the Arab countries and our cooperation with Israel has developed very satisfactorily, This is India's line. फॉरेन पॉलिसी में, सरकार किसी भी रंग की हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन देश के हित में हमारी विदेश नीति की निरंतरता बनी रहती है। डा. मनमोहन सिंह अभी

एक घंटा पहले बैठे थे। उनको उन्होंने एप्रिशिएट किया। मैं जापान गया था। वहां जाकर मैंने भारत की पूर्वी एशिया नीति की प्रशंसा की थी क्योंकि वे भारत के प्रधान मंत्री के नाते पूर्वी एशिया से संबंध बना रहे थे, कांग्रेस के नाते नहीं। यह हमारी मंशा है। मैंने कहा था। इसलिए आप लोग ...(**व्यवधान**)... आनन्द शर्मा जी, ध्यान रखिए, आप ऐसे करके बात नहीं करिए, हम इकट्ठा हैं। हिन्दुस्तान सर्वोपरि है और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नीति है, वह हमेशा वही रही है जो भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन के बारे में रही है। हमने हमेशा यह कहा कि वहां अगर गलत काम होता है ...(**व्यवधान**)... देखिए, इज़राइल को भी एग्ज़िस्ट करने का हक है। यह यूनाइटेड नेशंस का रेज़ोल्यूशन है।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: We say the same thing. ... *(Interruptions)*...

**श्री तरुण विजय** : आप यह नहीं कह सकते। आंखों में नफरत और दिल में तेजाब लेकर आप अमन की शायरी नहीं कर सकते। आपको अगर अमन की बात करनी है तो उस हिसाब से करनी होगी कि इज़राइल के साथ भी संबंध अच्छे रहें। दुश्मनी न करो। हम दोनों की दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन और इज़राइल में दोनों को अच्छा लगने वाला एक समझौता हो जाए। वह यूनाइटेड नेशंस के रेज़ोल्यूशन के अंतर्गत होना चाहिए। वहां अमन होना चाहिए, हम अमन के लिए काम करें। उसके लिए जरूरी है कि हम दोनों देशों के साथ संबंध बनाकर रखें और हिन्दुस्तान के हित को सर्वोपरि रखें। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि पिछले दस साल में यह गवर्नमेंट रिकार्ड है, एम.ई.ए. का रिकार्ड है, पिछले दस साल में हिन्दुस्तान और इजराइल के बीच में डिफेंस कोआपरेशन दोगुना हुआ है, हम इसे appreciate करते हैं, कांग्रेस भाइयों को appreciate करते हैं कि आपने हिन्दुस्तान के हित में एक काम किया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

**श्री तरुण विजय** : उसके बाद आपके हिसाब से सौ बिलियन डालर का व्यापार बढ़ा, जो कि दोगुना हुआ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

**श्री तरुण विजय** : ऐसे समय में हुआ, हम appreciate करते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों में अमन हो।

**श्री उपसभापति** : आप समाप्त कीजिए।

**श्री तरुण विजय** : हम दोनों देशों से चाहेंगे कि अमन हो, दोनों देशों से चाहेंगे कि युद्ध विराम हो, दोनों देशों से चाहेंगे कि मानवधिकारों का हनन न हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

**श्री तरुण विजय** : इसके साथ ही हम यह चाहेंगे कि आप शत्रुता की बात न करें। ...(**समय की घंटी**)... "दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं, तो शर्मिंदा न हों।" इसलिए हिन्दुस्तान के हितों को सर्वोपरि रखते हुए फिलिस्तीन के साथ पूरी हमदर्दी है। ...(**समय की घंटी**)... लेकिन हम चाहते हैं कि इजराइल और हमारी फिलिस्तीन में

[श्री तरुण विजय]

युद्ध-विराम होना चाहिए। दोनों देशों के साथ हिन्दुस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए। हिन्दुस्तान को अमन की बात करनी चाहिए और शांति को समाप्त करने की बात नहीं करनी चाहिए। जो हिन्दुस्तान के हित में हो, केवल वही कदम उठाना हमारी विदेश नीति का आधार होना चाहिए। धन्यवाद।

**श्री उपसभापति** : श्री के.सी. त्यागी। लास्ट स्पीकर ...(**व्यवधान**)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, you promised me to clarify what I said.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the matter? ... *(Interruptions)*... What is the problem? ... *(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I have been misrepresented. I want that to be corrected. ... *(Interruptions)*... मैं उन्हीं की शब्दावली में बोल दूं मित्रों, आपने मुझे बहुत गलत तरीके से रिप्रजेंट किया तरुण भाई। क्या गलत है, यह आप सुन लीजिए। आपने कहा कि मैंने यह कहा कि इज़राइल के साथ अपने संबंध बंद करो क्योंकि अत्याचार ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : तरुण जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : आपको मैंने सुना। मित्रों, मैंने आपको सुना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने हमें गलत रिप्रजेंट किया है। आपने चीन के बारे में कहा कि तिब्बत के लिए जो हो रहे है, उस वजह से चीन के साथ संबंध नहीं रखें। संबंध बंद करने के लिए येचुरी साहब ने नहीं बोला है। ...(**व्यवधान**)... आप एक मिनट सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप हमारी सुन लीजिए। आप हमसे ज्यादा चीन जाते हो। पता नहीं वहां पर क्या करके आते हो, अगर संबंध ही बिगाड़ने हैं, तो ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have made your point. ... *(Interruptions)*... Now, Shri K.C. Tyagi.

**श्री सीताराम येचुरी** : लेकिन इंडिया चीन से कोई हथियार नहीं खरीदता है। आज हमारा कहना है कि जो पैसा इज़राइल को हमारे द्वारा हथियार खरीदने की वजह से मिलता है, वह पैसा फिलिस्तीनीयों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : श्री के.सी. त्यागी ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : आप उसको बंद किए, यह हमारा कहना है। दूसरी बात यह है कि मोदी साहब के BRICS डिक्लेयरेशन की बात सबसे पहले हमने उठाई। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : श्री के.सी. त्यागी, प्लीज। ...(**व्यवधान**)... येचुरी जी, प्लीज ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : आप कहते हैं कि उसको नजरअंदाज कर दिया। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : येचुरी जी, प्लीज ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : सर, हमें गलत रिप्रजेंट किया गया है, इसलिए उसका स्पष्टीकरण करना है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : स्पष्टीकरण हो गया। You have corrected it. ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : आप रिकार्ड को साफ रखिए। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि आप मित्रों की सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yechuryji, please take your seat. You have explained it.

**श्री सीताराम येचुरी** : आप मित्रों को सुनकर भाषण दीजिए।

**श्री उपसभापति** : श्री के.सी. त्यागी। ...(**व्यवधान**)...

**श्री गुलाम नबी आजाद** : सर, मैं दो चीजें यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले जो हिस्टोरिकली गलत है - जोश में हमारे तरुण जी, अगर तरुण का उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो जोश होता है, वे जोश में कह गए कि 1962 में जब लड़ाई हुई थी, हिन्दुस्तान पर जब चीन की तरफ से हमला हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इज़राइल की मदद ली, यह गलत है। ...(**व्यवधान**)... इसको रिकार्ड से निकालना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तरुण जी ने कहा कि आपने BRICS का जिक्र नहीं किया। यह जो आप पढ़ रहे हैं, जिस दिन के लिए यह मोशन लगा था, तो यह मैंने की कोट किया था। आपने कहा कि आपने अटल जी जी का नाम नहीं लिया। शायद आप हाउस में नहीं थे, मैंने उनको कोट किया, हम वन साइड नहीं हैं। हमने समय-समय पर चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो किया है या पास्ट गवर्नमेंट्स ने जो किया है, सभी को हाउस में रखा है।

†[**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : سر، میں دو چیزیں یہاں پر کلئیر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہسٹوریکلی غلط ہے۔ جوش میں ہمارے ترون جی، اگر ترون کا اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو جوش ہوتا ہے، وہ جوش میں کہہ گئے کہ 1962 میں جب لڑائی ہوئی تھی، ہندوستان پر جب چین کی طرف سے حملہ ہوا تھا، تو جواہر لال نہرو نے اسرائیل کی مدد لی، یہ غلط ہے ۔۔(مداخلت)۔۔ اس کو ریکارڈ سے نکالنا چاہئیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترون جی نے کہ آپ نے برکس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس دن کے لئے یہ موشن لگا تھا، تو یہ میں نے ہی کوٹ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اٹل جی کا نام نہیں لیا۔ شاید آپ ہاؤس میں نہیں تھے، میں نے ان کو کوٹ کیا، ہم ون-سائڈ نہیں ہیں۔ ہم نے وقت وقت پر چاہے حالیہ گوورنمینٹ نے جو کیا ہے یا ماضی کی گوورنمینٹ نے جو کیا ہے، سبھی کو ہاؤس میں رکھا ہے۔]

**श्री उपससभापति** : श्री के.सी. त्यागी।

**श्री मोहम्मद अदीब** (उत्तर प्रदेश) : सर, मेरा नाम कब आयेगा?

†[**جناب محمد ادیب** : سر، میرا نام کب آئے گا؟]

†Transliteration in Urdu Script.

**3.00 P.M.**

**श्री उपसभापति** : आपका नाम इसमें नहीं है।

**श्री मोहम्मद अदीब** : सर, मेरा नाम क्यों नहीं है?

†[ **جناب محمد ادیب** : سر، میرا نام کیوں نہیں ہے؟ ]

**श्री उपसभापति** : नहीं है। आप छोड़िए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री मोहम्मद अदीब** : मैंने अपना नाम पहले दिया था ...(**व्यवधान**)...

**جناب محمد ادیب** : میں نے اپنی نام پہلے دیا تھا...(مداخلت)...

**श्री उपसभापति** : मैं देखूंगा। ...(**व्यवधान**)... आपने नाम दिया है, तो मैं देखूंगा। सुनिए, आधे घंटे के बाद दिया है, तो नाम नहीं लिखा जाएगा। ...(**व्यवधान**)... वह तो चेयरमैन साहब का रूल है। ...(**व्यवधान**)... यदि आपने पहले नाम दिया होगा, तो मैं देखूंगा। आपका नाम जरूर होगा। ...(**व्यवधान**)... I will check that. Now, Shri K.C. Tyagi. ... *(Interruptions)*...

**श्री रामदास अठावले** : सर, ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : आपका नाम नहीं है। ...(**व्यवधान**)... No, no, I cannot violate the rules. Sit down. ... *(Interruptions)*... Everybody wants to speak. ... *(Interruptions)*... Sit down. ... *(Interruptions)*...

**श्री के.सी. त्यागी** : उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही हुई बात से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, "हमारी सही संस्कृति सहिष्णुता पर कायम है। भारत सारे विश्व की चिंता करने वाले, सारे ब्रह्मांड की चिंता करने वाले देशों में से एक है।"

अभी तरुण विजय जी बता रहे थे कि प्रसंग 1978 का है। इज़राइल के रक्षा मंत्री, Moshe Dayan जो एक आंख वाले थे, वे बहुत बदनाम थे। वे 1978 में हमारे देश में आए थे, जब मोरारजी भाई देश के प्रधान मंत्री थे और M.J. Akbar ने इन्टरव्यू में जो कहा है, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मोरारजी भाई ने कहा, "हमारे यहां फिलिस्तीन के लिए इतनी हमदर्दी है कि अगर उन्हें पता लगे कि मैं आप से मिल रहा हूं, तो हिन्दुस्तानी मेरा गला दबा देंगे।" It was in 1974, Shri Atal Bihari Vajpayee to M.J. Akbar in Sunday Magazine. एक जमाना वह था, जब इज़राइल की तारीफ करना गुनाह माना जाता था। सुषमा जी की जो एक सप्ताह की अनुपस्थिति है, शरद यादव जी जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, उसने बहुत सारी गलतफहमियों को, बहुत सारे विवादों को जन्म दे दिया। जो फॉरेन स्पोक्स-मैन सैयद अकबरुद्दीन साहब हैं, उनका बयान पढ़कर सुनाता हूं। "India is alarmed at the cross-border provocation resulting from rocket attack against targets in the parts of Israel." यह हमारी विदेश नीति नहीं थी। तरुण भाई, आप बुरा मत मानिएगा। हम और आप पचास साल इन्हीं के खिलाफ लड़े हैं,

†Transliteration in Urdu Script.

लेकिन विदेश नीति के बारे में यह 1950-60 की नीति जनसंघ की नीति हो सकती है या हमारी सनसोपा की हो सकती है। यह आज के एन डी ए की और आज की सरकार की नीति नहीं हो सकती। मैं उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में चीन होकर आ रहा हूं। उन्होंने हमसे पूछा कि नरेन्द्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको पता है कि मेरी राय डोमेस्टिक लीड पर, उनके विरोध में है, लेकिन मैंने कहा कि वे चीन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। जब हिन्दुस्तान इस तरह से बिहेव करेगा और प्रधान मंत्री जी यहीं पर कह कर गए थे कि हम बहुमत में हैं, लेकिन आप से पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे। आज आप इज़राइल को और फिलिस्तीन को कैसे equate कर सकते हैं?

दूसरी बात यह है कि सुषमा जी, मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूं कि आपकी गैर हाजिरी में क्या-क्या खराब काम हुए? आपके एक मंत्री जी हैं, यहां उनका नाम लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, "Domestic policies should not affect our foreign policy." जबकि विदेश नीति की जो ABCD है, वह यह है कि विदेश नीति देश के खूंटे से बंधी होती है। हमारे राष्ट्रहित क्या हैं, आज 80 लाख आदमी ईराक के अंदर रोजी-रोटी की तलाश में हैं वे सभी धर्मों और सभी इलाकों से हैं। सुषमा बहन को वहां से लोगों को निकालने में कितनी मुश्किल हुई होगी। हालांकि उनमें जो मलयाली Industrialists हैं, जो व्यापार में लगे लोग हैं, उनका भी diplomatic कार्यों में योगदान रहा है। अगर कोई ऐसी सरकारी होती, जो pro-India होती या pro-Israel होती या pro-Palestine होती, तो शायद आपको वहां से लोगों को निकालने में दिक्कत न आती।

दूसरी बात यह है कि आपके मंत्री महोदय का बयान है कि "India has diplomatic relations with both the countries." He again says, "Opposition for treating the issue as an issue of minority in India... *(Interruption)*... अगर कोई ऐसी बात कहता है। हिन्दुस्तान के मुसलमानों का ध्यान रखकर, आपसे कोई नहीं कह रहा है, यह आपके मंत्री का बयान है। मैं जानबूझकर उनका नाम नहीं ले रहा हूं। श्री नायडु साहिब, It is on record. I am saying that. मैं नाम लेना नहीं चाहता था। अगर हम आपसे फिलिस्तीनियों के पक्ष में और इज़रायल के खिलाफ बात करते हैं, तो वह हिन्दुस्तान के मुसलमानों को खुश करने के लिए नहीं है। यह हमारे देश की स्थापित नीति है। मुझे याद ...(**व्यवधान**)...

DR. CHANDAN MITRA: Will the hon. Member authenticate that statement?

SHRI K.C. TYAGI: My dear good friend, I am not yielding. 1991 में नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे। उस समय कश्मीर को लेकर जिनीवा में कांफ्रेंस हो रही थी। भारतीय जनसंघ के नेताओं के कश्मीर के बारे में जो विचार हैं, वे सर्वविदित हैं, मैं उनको आलोचना के तौर पर नहीं कहना चाहता हूं। नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कश्मीर पर हिन्दुस्तान के विचार व्यक्त करने के लिए भेजा था। यह हमारी विदेश नीति थी। 1962 में चीन और हमारा झगड़ा हुआ था। ...(**व्यवधान**)... मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं। ...(**व्यवधान**)... आईएमसॉरी ...(**व्यवधान**)... 1962 में जब हिन्दुस्तान और चीन का सीमा संघर्ष हुआ था, तो यह हमारी विदेश नीति का ही कमाल था ...(**व्यवधान**)...

**श्री आनन्द शर्मा** : एक मिनट त्यागी जी। What Tyagiji has referred to, I will add one information. In 1988 when the U.N. General Assembly had met, visas were not given

[श्री आनन्द शर्मा]

to the Palestinian delegation, including late Yaser Arafat. The session was shifted to Geneva. At that time, Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. Atal Bihari Vajpayeeji and I were sent to Geneva to attend the special session on Palestine.

**श्री के.सी. त्यागी** : 1962 में चीन और आपका जो विवाद था, उस पर जो निश्चित हुआ था, वह विदेश नीति थी। अगली पंक्ति में बैठे हुए हमारे साथी ठीक कह रहे थे कि हमने वह आजादी के आंदोलन के दौरान ग्रहण की थी। उसमें सोवियत यूनियन ने चाइना का पक्ष नहीं लिया था। 1965 और 1971 की इंडो-पाक वार के दौरान आधे से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज ऐसी थीं, जो हिन्दुस्तान के साथ खड़ी थीं, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी थीं। वह जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति थी। वह महात्मा गांधी की आजादी के आंदोलन में इकट्ठा की हुई हमारी विरासत थी। मुझे अफसोस है ...(**व्यवधान**)... मैं सुषमा बहिन से कहना चाहता हूं - बहिन जी नहीं, आजकल ये हमारी सुषमा बहिन हो गई हैं, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम एक ऐसा प्रस्ताव यहां से पास हो जाए ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : खत्म कीजिए।

**श्री के.सी. त्यागी** : मैं आपसे यह इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि आप इस कैबिनेट की सबसे वरिष्ठतम और काबिल मंत्रियों में से एक हैं और परंपरा भी रही है। मंत्री महोदया का यह कहना भी गलत है कि नहीं, यहां से कभी वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव इराक को लेकर ...(**व्यवधान**)... पास हो चुका है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. बस खत्म कीजिए। यह ठीक नहीं है।

**श्री के.सी. त्यागी** : मेरा इतना निवेदन जरूर है कि आप इज़राइल और फिलिस्तीन को एक तराजू पर नहीं माप सकते हैं। इजराइल का जन्म फिलिस्तीनियों के हितों के खिलाफ ...(**व्यवधान**)... आज 80 लाख आदमी बाहर निकले हुए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. मैंने श्री मोहम्मद अदीब को बुलाया है।

**श्री के.सी. त्यागी** : वहां की जेलों में बंद हैं। ...(**व्यवधान**)... आप इन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इक्वेट नहीं कर सकते हैं।

**श्री तरुण विजय** : उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि हम इक्वेट नहीं कर रहे हैं। हम फिलिस्तीन के दुख में उनके साथ हैं। हमने विदेश नीति बदली नहीं है, कंटीन्यू की है। हम यही बात कह रहे हैं।

**श्री मोहम्मद अदीब** : डिप्टी चेयरमैन साहब, जब सैकड़ों बच्चे मर गए, जब बेपनाह औरतें घरों से उजड़ गईं, जब पूरी आबादी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और दुनिया चीख पड़ी, लंदन, पेरिस, जर्मनी और दुनिया के हर कोने से लोग निकलने लगे, तब इस सदन को ख्याल आया कि हम इस पर बात करें या हो सकता है कि इस सरकार को इसके लिए मजबूर होना पड़ा हो। मुझे अफ़सोस हैं। अफ़सोस इसलिए है कि यह जो मुल्क है, इसने बुनियाद पड़ने से लेकर हमेशा फिलिस्तीन की मदद की थी। जैसा कि हमारे एल.ओ.पी. ने कहा है, सन् 47 में, गांधी जी से लेकर, "फिलिस्तीन बंटेगा" के खिलाफ पहली बार हिन्दुस्तान ने रेजोल्यूशन पास

किया था। उसके बाद सबसे पहले 1974 में हिंदुस्तान ने सबसे पहले पी.एल.ओ. को रिकॉग्नाइज किया था। उस स्टेट को 1988 में हिन्दुस्तान ने रिकॉग्नाज किया था। लेकिन उसके बाद भी, इन सब बातों के बावजूद भी सरकार को यह ख्वाहिश क्यूं है, मैं यह समझ नहीं पाया हूं। मेरी समझ से मैं क़ासिर हूं कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हो और जिसने 2003 की यूनाइटेड नेशन्स की कांफ्रेंस को फिलिस्तीन की हिमायत के लिए को-स्पॉन्सर किया है...। मैं नहीं कहना चाहता कि औरों ने क्या किया, लेकिन मैंने जब बी.जे.पी. के अपने साथियों को सुना, तो मुझे कुछ तकलीफ भी हुई। यह तकलीफ कहीं और दूर तक गई। इसलिए मुझे ख्याल आया कि एक कर्नल पुरोहित साहब आतंकवाद के नाम पर जेल में बंद है। करकरे साहब ने जब उनकी डिस्क को पकड़ा और वह रेकार्ड निकाला गया, जो पब्लिक डोमेन में है, ...(**व्यवधान**)... तो उसमें कहा गया कि इज़राइल के साथ उनके ताल्लुकात हैं। वह डिस्क पार्लियामेंट में लानी चाहिए, ...(**व्यवधान**)... क्योंकि कर्नल पुरोहित ने यह बात कही कि मैं इजराइल के साथ ताल्लुकात पैदा कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)... इम्तिहान ले रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : आप बैठिए।

**श्री मोहम्मद अदीब** : क्योंकि एक हिन्दू राष्ट्र बनाना है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : चंदन मित्रा जी, आप बैठिए।

**श्री मोहम्मद अदीब** : जिस दिन इस हाउस में बहस हो रही थी, उस दिन इज़राइल का एम्बैसडर बी.जे.पी. के ऑफिस में बैठा हुआ था। यानी कहीं कुछ और मामला है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। ...(**व्यवधान**)... मैं समझता हूं कि बी.जे.पी. को खुल कर कहना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री अविनाश राय खन्ना** (पंजाब) : यह आप कैसे कह सकते हैं?

**श्री मोहम्मद अदीब** : नहीं तो क्या मसला है कि जिस मुल्क की पॉलिसी यह रही हो कि जब उसके पास कुछ नहीं था, तो वह दुनिया का हाकिम था, जब आज सब कुछ है, तो यह मुल्क अमेरिका और इजराइल का गुलाम बन कर रह गया है। ये चंद लोग हैं, जैसा मैंने कहा, जिनका खाका बहुत दूर तक जाकर मिलता है। वह डिस्क मौजूद है, जिसमें कर्नल पुरोहित ने यह कहा है, करकरे साहब ने वह डिस्क पकड़ी थी, कि हम इज़राइल के साथ मामलात कर रहे हैं, हमको वहां से असलहा भी मिलेगा और हम एक हिन्दू राष्ट्र बनाने में मदद भी करेंगे। मुझे यह लगता है कि अगर सुषमा स्वराज साहिबा इतनी बेहतरीन मिनिस्टर हैं, इतनी बेहतरीन शख्सियत हैं, मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं, तो मैं समझता हूं कि आप अल्लाह के वास्ते इस मुल्क की सियासत को इस तरफ मत ले जाइएगा, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने सीखा था, जिस मुल्क का ख्वाब देखा था। हमेशा यह मुल्क मिसकीनों के साथ खड़ा रहा है। यह जंग नहीं है, यह जमीन पर कब्जे का मसला है। अगर कब्जे के मसले पर भी आप नहीं उठेंगे, आप तसव्वुर कीजिए, हमारे दिल को तकलीफ पहुंचती है, जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उस फिलिस्तीन पर, जहां कब्जा हो गया, वहां आवाज उठाने में आपको क्या परेशानी है? आपने इसको आठ दिन डिले करके एक गलत पैगाम दिया है। मैं समझता हूं कि शरद यादव जी ने जो बात कही थी, वह

[श्री मोहम्मद अदीब]

गाइडलाइन है, वह एक पूरी सीधी रोशनी है कि अगर आपको इस मुल्क का हित चाहिए, तो खुल कर कहिए, यह पर्दादारी मत करिए। कुछ-न-कुछ तो है, जिसकी पर्दादारी है, जिसके लिए आपको बेचैनी है, जिसके लिए इजराइल का सफीर बी.जे.पी. के दफ्तर में बैठता है। वह बी.जे.पी. के दफ्तर में उस दिन बैठता है, जिस दिन इस पार्लियामेंट में कहा जाता है कि इस पर बहस हो। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं समझता हूं कि वह रिजोलूशन पास होना चाहिए, जो एल.ओ.पी. साहब ने दिया है। वह सजेशन, जो सीताराम येचुरी जी ने दिया है, उस पर भी इस हाउस को अमल करना चाहिए। दोनों हाउसेज में, इस हाउस में और उस हाउस में, इस पर बहस होकर इजराइल के खिलाफ एक रिजोलूशन पास होना चाहिए और उनसे हमारे तिजारती मामलात को खत्म किया जाना चाहिए। इन अल्फाज के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

†ڈپٹی چیئرمین صاحب، جب سینکڑوں بچے مر گئے، جب بے : **(اتر پردیش)جناب محمد ادیب**
پناہ عورتیں گھروں سے اجڑ گئیں، جب پوری آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئی اور دنیا چیخ پڑی، لندن، پیرس، جرمنی، اور دنیا کے ہر کونے سے لوگ نکلنے لگے، تب اس سدن کو خیال آیا کہ ہم اس پر بات کریں یا ہو سکتا ہے کہ اس سرکار کو اس کے لئے مجبور ہونا پڑا ہو۔ مجھے افسوس ہے۔ افسوس اس لئے ہے کہ یہ جو ملک ہے، اس نے بنیاد پڑنے 1947سے لے کر ہمشہ فلسطین کی مدد کی تھی۔ جیسا کہ ہمارے ایل۔او۔پی۔ نے کہا کہ سن کے خلاف پہلی بار ہندوستان نے ریزولیشن "فلسطین بنٹے گا"میں، گاندھی جی سے لے کر، میں ہندوستان نے سب پہلے پی۔ایل۔او۔ 1974پاس کیا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں ہندوستان نے ریکاگنائز کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد 1988ریکاگنائز کیا تھا۔ اس اسٹیٹ کو بھی، اس سب باتوں کے باوجود بھی سرکار یہ خواہش کیوں ہے، میں یہ سمجھہ نہیں پایا ہوں۔ واجپئی ہو اور جن نے میری سمجھہ سے یہ قاصر ہے کہ جس ملک کا پرائم منسٹر اٹل بہاری اسپانسر کیا ہو۔یونائیٹڈ نیشنس کی کانفرنس کو فلسطین کی حمایت کے لئے کو کی 2003 میں نہیں کہنا چاہتا کہ اوروں نے کیا کیا، لیکن میں نے جب بی جے پی کے اپنے ساتھیوں کو سنا، تو مجھے کچھہ تکلیف بھی ہوئی، یہ تکلیف کہیں اور دور تک گئی۔ اس لئے مجھے یہ واد کے نام ۔خیال آیا کہ ایک کرنل پروہت صاحب جیل میں بند ہیں۔ کرنل پروہت صاحب آتنک پر جیل میں بند ہیں۔ کرکرے صاحب نے جب انکی ڈسک کو پکڑا اور وہ ریکارڈ نکالا گیا، جو --- تو اس میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ساتھہ ان کے تعلقات ہیں۔ وہ (مداخلت)پبلک ڈومین ہے --- --- کیوں کہ کرنل پروہت نے یہ بات کہی کہ میں (مداخلت)ڈسک پارلیمنٹ میں لانی چاہئے --- ---(مداخلت)--- امحتان لے رہا ہوں ---(مداخلت)اسرائیل کے ساتھہ تعلقات پیدا کر رہا ہوں ---

آپ بیٹھئے۔: **شری اپ سبھا پتی**

†Transliteration in Urdu Script.

**:جناب محمد ادیب** کیوں کہ ایک ہندو راشٹر بنانا ہے۔

**:شری اپ سبھا پتی** چندن مشرا جی آپ بیٹھئے۔

**:جناب محمد ادیب** جس دن اس ہاؤس میں بحث ہو رہی تھی، اس دن اسرائیل کا سفیر یعنی کہیں کچھ اور معاملہ ہے، پردے کے پیچھے بی۔جے۔پی۔ کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ...میں سمجھتا ہوں کہ بی۔جے۔پی۔ کو کھل کر کہنا (مداخلت)کچھ اور چل رہا ہے ... ...(مداخلت)چاہئے...

**:شری اوناش رائے کھنہ** یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

**:ادیب محمد جناب** یہ رہی ہو کہ جب اس کے پاس نہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ جس ملک پالیسی کچھ نہیں تھا، تو وہ دنیا کا حاکم تھا، جبکہ آج سب کچھ ہے، تو یہ ملک امریکہ اور اسرائیل یہ چند لوگ ہیں، جیسا میں نے کہا، جن کا خاکہ بہت دور جاکر ملتا کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ ہے۔ وہ ٹسک موجود ہے، جس میں کرنل پروہت نے یہ کہا ہے، کرکرے صاحب نے وہ ٹسک پکڑی تھی، کہ ہم اسرائیل کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ ہم کو وہاں سے اسلحہ بھی ملے گا اور ہم ایک ہندو راشٹر بنانے میں مدد بھی کریں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سشما سوراج صاحبہ اتنی بہترین منسٹر ہیں، اتنی بہترین شخصیت ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کے واسطے اس ملک کی سیاست کو اس طرف مت لے جائیے، جو ہمارے آباؤاجداد نے، ہمارے بزرگوں نے سیکھا تھا، جس ملک کا خواب دیکھا تھا۔ ہمیشہ یہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ زمین پر قبضے کا مسئلہ ہے۔ ملک مسکینوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اگر قبضے کے مسئلے پر بھی آپ نہیں اٹھیں گے، آپ تصور کیجئے، ہمارے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے کشمیر کے کچھ حصے پر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو اس فلسطین پر جہاں قبضہ ہو گیا، وہاں آواز اٹھانے میں آپ کو کیاپریشانی ہے؟ آپ نے اس کو آٹھ دن ڈیلے کرکے ایک غلط پیغام دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرد یادو جی نے جو بات کہی تھی، وہ گائڈ لائن ہے، وہ ایک پوری سیدھی روشنی ہے کہ اگر آپ کو اس ملک کا ہت چاہئے، تو کھل کر کہئے، یہ پردہ داری مت کرئیے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے، جس کی پردہ داری ہے، جس کے لئے آپ کو بے چینی ہے، جس کے لئے اسرائیل کا سفیر بی۔جے۔پی۔ کے دفتر میں بیٹھتا ہے۔ وہ بی جے پی کے دفتر

[श्री मोहम्मद अदीब]

میں اس دن بیٹھتا ہے جس دن اس پارلیمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ اس پر بحث ہو۔ میں آپ کا بہت آبھاری ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریزولیوشن پاس ہونا چاہئے، جو ایل۔او۔پی صاحب نے دیا ہے۔ وہ سجیشن، جو سیتارام یچوری جی نے دیا ہے، اس پر بھی اس ہاؤس کو عمل کرنا چاہئے۔ دونوں ہاؤس میں، اس ہاؤس میں اور اس ہاؤس میں، اس پر بھی بحث ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک ریزولیوشن پاس ہونا چاہئے اور ان سے ہمارے تجارتی معاملے کو ختم کیا جانا چاہئے۔ ان الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the allotted time is over. We are running out of time. Three hon. Members are pressing me for two minutes each. If the House allows, I will give them two minutes.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, let them speak.

**श्री हुसैन दलवई** (महाराष्ट्र) : सर, गाजा पट्टी के मुद्दे पर आज बहस हो रही है। गाज़ा पट्टी में जो सबसे ज्यादा डेनसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहां 15 लाख लोग 144 स्क्वायर मीटर में रहते हैं। वहां कहीं भी बम्बार्डमेंट होती है, तो बेचारे लोग मरते हैं। आज इस ढंग से बम्बार्डमेंट हो रही है कि इजराइल के प्रेसिडेंट यह कहते हैं कि अगर ओबामा भी हमें बोलेंगे, तो भी हम यह बम्बार्डमेंट बंद नहीं करेंगे। वहां इतनी * चल रही है। वहां से जो तीन विद्यार्थी भगाए गए, किडनैप हुए, कैसे वे किडनैप हुए, उस पर भी बहस होनी बहुत जरूरी है। इजराइल में खास करके नौजवान लोग सैटलमेंट जमीन लेते हैं और वहां से पैलस्टीनियन लोगों को भगा देते हैं। इसकी वजह से वहां पर हमेशा झगड़ा होता है। पहले 1917 में पी.एल.ओ. के पास इतनी जमीन थी, लेकिन आज की हालत क्या है? आज उनकी 95% जमीन इजराइल के हाथ में है, खाली 5% में बेचारे पैलस्टीनियन लोग रह रहेक हैं, जैसे उनको जेल में रखा गया हो।

मैं वहां पीस मिशन पर गया था, लेकिन वहां की हकीकत देख कर मुझे बहुत बुरा लगा। वहां स्थिति यह है जैसे वहां की सारी बस्ती एक जेल में रह रही हो। उनको जहां भी जाना हो, हर जगह वॉल्स बना रखी हैं। वहां भाई-भाई में भी दुश्मनी बनी हुई है। भाई को भाई नहीं मिल सकता, बच्चों को बच्चे नहीं मिल सकते, ऐसी स्थिति वहां है। मेरे ख्याल से इन सारी चीजों को ठीक तरह से देखना बहुत जरूरी है।

गांधी जी ने क्या कहा अथवा नेहरू जी ने क्या कहा, इसकी बहस यहां हो चुकी है। हमारे देश की एक परम्परा है। अगर हम अपनी उस परम्परा को छोड़ेंगे तो बहुत गलत होगा। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, गांधी जी या नेहरू जी परम्परा की बात आप छोड़िए, आप वाजपेयी जी से तो सीखिये और उनकी तरह उदार मतवादी हो जाइए।

* Expunged as ordered by the Chair.

यह सवाल हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है। आप इसे हिन्दू-मुस्लिम का सवाल समझकर बिल्कुल मत देखिए। यह इन्सानियत का सवाल है। ...(**समय की घंटी**)...

**श्री उपसभापति** : आप बैठिए।

**श्री हुसैन दलवई** : एक मिनट। मेरा कहना यह है, मैं जिस भाग से आया हूं, वहां से बड़े पैमाने पर लोग नौकरी-धंधे के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए गए हुए हैं। ...(**समय की घंटी**)... जैसे वहां केरल के बहुत लोग गए हैं, हमारे यहां के लोग भी गए हैं, उसका कारण यह है ...(**समय की घंटी**)...हमें सब खत्म करने की बात बिल्कुल नही करनी चाहिए। इजराइल से आपको कोई फायदा नहीं है। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please sit down.

**श्री हुसैन दलवई** : इजराइल एक ऐसा देश है ...(**समय की घंटी**)... आप क्या रिश्तों की बात करते हैं ...(**समय की घंटी**)...

**श्री उपसभापति** : आपके दो मिनट हो गए।

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Sir, thank you for allowing me to speak a few words on this important issue. First of all, I would remind my friends that India, since its independence, has been supporting this struggle of the Palestinian people. We supported them not only within the country but also in the U.N. and other international fora Everybody knows that the State of Palestine came into existence not only because of the heroic struggle of the Palestinian people but also because of international support. Asia, Africa, Latin America, all these countries and National Liberation Movements have stood behind the Palestinian people. And it is also known that before the formation of Palestine, Israel had been opposing it. They were not only opposing it but there had also been many aggressions from the Israeli soil taking place from time to time during these years. It is also well-known in the international arena that Israel does not want the Palestine State on its border. So, this is not a new aggression, a new attack, on the Palestinian people. India, since the times of Pandit Jawaharlal Nehru to Shri Atal Bihari Vajpayee and, lately, to our present Prime Minister, has supported the very existence of Palestine. Now I am astonished as to why it took us six of seven days to decide whether we should discuss this matter or not. Two friends are there, Sir. If one friend attacks another friend to kill him and if we stand as a mute spectator and let the two decide who will kill whom, then the stronger one will kill the weaker one. So I oppose openly and ask Israel to stop aggression immediately. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. अठवाले जी, आपके पास सिर्फ दो मिनट का समय है। जल्दी बोलिए।

**श्री रामदास अठावले** : सर, मुझे लगता है कि यह विषय अपने हाउस को डिवाइड करने वाला विषय नहीं है। यह विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देश की परम्परा शान्ति की परम्परा है, बुद्ध की परम्परा है। आज तक दुनिया में जहां-जहां भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जिन्होंने काम किया है, उनके खिलाफ भारत रहा है। नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं। फिलीस्तीन और इजराइल के इश्यू पर, जहां मानवतावाद का उल्लंघन हुआ, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। मुझे लगता है कि वहां दो कंट्रीज बनाने के सम्बन्ध में भी किसी प्रस्ताव के बारे में विचार हो सकता है। अमेरिका अगर बोलता था कि इराक में से हमें आतंकवाद खत्म करना है, तो अमेरिका आज क्या कर रहा है? रशिया यूक्रेन का क्या कर रहा है? मलेशिया के विमान में जो लगभग 299 लोग जा रहे थे, उनको वहां पर मार गिराया गया है। मुझे लगता है कि फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल ने कब्जा किया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया है, उसी तरह उन्होंने वहां कब्जा किया है। मुझे लगता है कि इज़राइल के साथ संबंध बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि इजराइल के पास जितने हथियार हैं, उतने ले लो, ताकि वह युद्ध बन्द करे। ...(**व्यवधान**)... हथियार की बात नहीं है, अपने देश की इकानॉमी की बात है। यह सही बात है कि 1991 से ही इजराइल के साथ अपने सम्बन्ध अच्छे रहे हैं। इजराइल एक कंट्री है, वहां का विवाद उनका है। लेकिन इजराइल की तरह फिलिस्तीन भी एक कंट्री है। इसलिए इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारे संबंध अच्छे थे और अच्छे रहने भी चाहिए। मगर इजराइल वहां अन्याय कर रहा है, तो भारत को इजराइल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इजराइल को बोलना चाहिए कि वहां हथियार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

सर, मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा आज से पहले ही होनी चाहिए थी। पहले भी जब रेल बजट होता था, तो दूसरी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन विरोधी पक्ष वालों को हंगामा करने की आदत लग गई है। वह आदत पहले हमें थीं और अब यह आदत इन लोगों को लग गई है। इसलिए हाउस का टाइम बचाने का काम भी आप लोगों को करना चाहिए। हम जो कर रहे थे, अगर वही आप करेंगे तो उससे हाउस नहीं चलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों को यहां इजराइल कंट्री का विरोध नहीं करना है, बल्कि इजराइल ने जो स्टैंड लिया है, उस स्टैंड का हमें विरोध करना है। यहां कोई मुसलमान या किसी अन्य बात का विषय नहीं है। 1917 में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल का निर्माण करने का काम हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने 1948 में इस कंट्री को मान्यता दी। लेकिन, यह जगह फिलिस्तीन की है और वहां इज़राइल के लोग ज्यादा हैं। मैं इज़राइल को कहना चाहता हूं कि आप शान्त रहो। दुनिया में जब कहीं मानवता का उल्लंघन होता है, तब पूरी दुनिया को उसके खिलाफ रहना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... लेकिन, अगर ऐसे युद्ध ही करना है, तो अगर, इजराइल फिलिस्तीन के साथ युद्ध कर रहा है, ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : बस करो, बस। ...(**व्यवधान**)... बस, बस। ...(**व्यवधान**)... हो गया। ...(**व्यवधान**)... बस कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रामदास अठावले** : तो एक दिन पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध करना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : हो गया। ...(**व्यवधान**)... बस कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रामदास अठावले** : इसलिए पाकिस्तान अगर हमारे कश्मीर का एरिया नहीं देता हैं, तो एक बार ऐसा भी करना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : श्री मोहम्मद शफ़ी ...(**व्यवधान**)... लास्ट स्पीकर। ...(**व्यवधान**)...

**श्री रामदास अठावले** : लेकिन, यह युद्ध की बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)... हमें युद्ध नहीं चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री उपसभापति** : श्री मोहम्मद शफ़ी ...(**व्यवधान**)... लास्ट स्पीकर। ...(**व्यवधान**)...

**श्री मोहम्मद शफी** (जम्मू और कश्मीर) : सर, इजराइल की खुली जारहियत के हवाले से ऐवाल में दो घंटे से ज्यादा वक्त में बहस हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से जो करारदात यहां पेश हुई है, मैं अपनी जमात जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से उसकी भरपूर हिमायत करता हूं। इजराइल का वजूद तारीखी लिहाज से अरब दुनिया पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मे जुल्म की एक दास्तान, जो साम्राज्यवादी ताकतों ने रकम की है, उसकी एक मिशाल है। उसकी मिसाल है। बड़ी तफसील के साथ यहां पर इज़राइल के वजूद में आने और फिलिस्तीनी अवाम के हुकूक के बारे में बात हुई है। मैं उन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर इस ऐवान में रखूंगा कि हमारे मुल्क की एक तारीख रही, इस मुल्क की कयादत ने आजादी से पहले भी, जैसे गांधी जी का यहां हवाला दिया गया है इजराइल जो है, वह तो बैनलगामी सत्ता पर जुल्म के एक पैकर के तौर पर वजूद में रहा। जब कभी भी फिलिस्तीन के हुकूक के हवाले से बात हुई बैनुअकवामी सतह पर हिन्दुस्तानी क़यादत ने हमें मज़लूम फिलिस्तीनी आवाम के हुकूक की हिमायत की। मुझे देख हो रहा था, यहां तो फिलिस्तीन के आवाम के हुकूम की बात हो रही थी और उस पर होने वाला इस वक्त जो हमला हो रहा है, उसके हवाले से बात हो रही थी। हूकुमरां जमात के एक हमारे साथी यहां पर नमाज और जन्नत की बात कर रहे थे। मैं अपने आप पर तरस खा रहा था। हम इतने बड़ ऐवान में इस वक्त एक बड़े सियासी मसले की बात कर रहे हैं और वे यहां नमाज और जन्नत के हवाले से हम पर वार कर रहे हैं। वे यहां नमाज और जन्नत के हवाले से हमें बता रहे हैं, हम जानते हैं कि उनके जेहन में क्या बात थी। ...(**समय की घंटी**)... यह मुसलमान का मसला नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

†**[جناب محمد شفیع (جموں وکشمیر) :** سر، اسرائیل کی کھلی جارحیت کے حوالے سے ایوان میں دو گھنٹے سے زیادہ وقت سے بحث ہورہی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کی جانب سے جو قرارداد یہاں پیش ہوئی ہے، میں اپنی جماعت جموں وکشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ اسرائیل کا وجود تاریخی لحاظ سے عرب دنیا پر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں ظلم کی ایک داستان، جو سامراجیہ وادی طاقتوں نے رقم کی ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یہں پر اسرائیل کے وجود میں آنے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ میں ان باتوں کو یہاں دوہرانہ نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ضرور اس ایوان میں رکھوں گا کہ ہمارے ملک کی ایک تاریخ رہی ہے، اس ملک کی قیادت نے آزادی سے پہلے بھی، جیسے گاندھی جی کا یہاں حوالہ دیا گیا اور آزادی کے بعد ظالم کا ساتھ نہیں دیا، مظلوم کا ساتھ دیا۔ اور اسرائیل جو ہے، وہ تو بین الاقوامی سطح پر ظلم کے ایک پیکر کے طور پر موجود رہا۔ جب کبھی بھی فلسطین کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی بین الاقوامی سطح پر ہندستانی قیادت نے ہمیشہ مظلوم فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کی۔ مجھے دکھ ہورہا تھا، یہاں تو فلسطین کے عوام کے حقوق کی بات ہورہی تھی اور اس پر ہونے والا اس وقت جو حملہ ہورہا ہے، اس کے حوالے سے بات ہورہی تھی۔ حکمراں جماعت کے ایک ہمارے ساتھی یہاں پر نماز اور جنت کی بات کررہے تھے۔ میں اپنے آپ پر ترس کھا رہا تھا۔ ہم اتنے بڑے ایوان میں اس وقت ایک بڑے سیاسی مسئلے کی بات کررہے ہیں اور وہ یہاں نماز اور جنت کے حوالے سے ہم پر وعظ کررہے ہیں۔ وہ یہاں نماز اور جنت کے حوالے سے ہمیں بتارہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا بات تھی۔ ...(وقت کی گھنٹی)... یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

**श्री मोहम्मद शफ़ी** : यह मुसलमान का मसला नहीं है, यह तो ज़ालिम और मज़लूम का सवाल है। ...(**व्यवधान**)...

†[**محمد شفیع (جموں وکشمیر)** : سر، یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ظالم اور مظلوم کا سوال ہے ...(مداخلت)...]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

**श्री मोहम्मद शफ़ी** : यहां पर ये यह बात कह रहे थे कि मामलात के हवाले में यहां पर हमेशा एक इत्तफाक राय रहा है consensus रहा है। ...(**व्यवधान**)... सर, दो मिनट और दे दीजिए।

†[**محمد شفیع (جموں وکشمیر)** : یہاں پر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہر معاملات کے حوالے میں یہاں پر ہمیشہ ایک اتفاق رائے رہا ہے، consensus رہا ہے۔ ...(مداخلت)... سر، دو منٹ اور دے دیجئے۔]

**श्री उपसभापति** : नहीं, नहीं, दो मिनट नहीं मिलेंगे, कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

**श्री मोहम्मद शफ़ी** : आज आपका इम्तिहान है। अगर consensus रहा है, तो आज जो कंरारदादे मुजम्मत यहां पर पेश होने वाली है ...(**व्यवधान**)...

[**محمد شفیع (جموں وکشمیر)** : آج آپ کا امتحان ہے۔ اگر consensus رہا ہے، تو آج جو قرارداد مذمت یہاں پر پیش ہونے والی ہے ...(مداخلت)...]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Now, Shafi*ji*, please conclude. बैठिए, बैठिए। Now, please take your seat. Don't take advantage. That is okay. Sit down.

**श्री मोहम्मद शफ़ी** : आपके लिए इम्तिहान है आप इस करादाद की भरपूर हिमायत कीजिए ...(**व्यवधान**)... और मुजम्मत की करादाद इजराइल के खिलाफ पास कीजिए।

†[**جناب محمد شفیع** : آپ کے لئے امتحان ہے آپ اس قرارداد کی بھرپور حمایت کیجئے ...(مداخلت)... اور مذمت کی قرارداد اسرائیل کے خلاف پاس کیجئے۔]

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : धन्यवाद, उपसभापति जी। उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। गुलाम नबी आजाद साहब से शुरू होकर मोहम्मद शफी साहब तक, 20 साथियों ने इस चर्चा में हिस्सेदारी की है। नेता प्रतिपक्ष, गुलाम नबी आजाद जी ने चर्चा की शुरुआत की और प्रारंभ में ही

†Transliteration in Urdu Script.

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कहा कि मुझे इस बात का खेद है कि अगर यह चर्चा 16 तारीख को हो जाती, तो भारत उन देशों में शामिल हो जाता, जो इस पर कठोर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि गुलाम नबी आजाद साहब इस बात को भूल कैसे गए? 16 तारीख को आपने चर्चा लगाई थी, लेकिन भाईजान, एक दिन पहले ही 15 तारीख को भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका था और सार्वजनिक तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से दे चुका था। "ब्रिक्स" कोई छोटा-मोटा मंच नहीं है, चीन, रूस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, उनके साथ मिल कर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और जो संयुक्त स्टेटमेंट वहां जारी हुआ था, सीताराम येचुरी जी ने उसकी बहुत सराहना की। उसके एक-एक शब्द की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। क्या कहीं कोई कमी आपको उसमें दिखाई दी? किसी तरह की कोई कमी उस वक्तव्य में, उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं है तो, 15 तारिख को जब भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका, तो आपका यह कहना कि भारत चूक गया, यह अपने आप में गलत है और मुझे उससे भी ज्यादा आश्चर्य हुआ जब भाई आनन्द शर्मा बोले, क्योंकि कांग्रेस से इसमें दो ही लोग बोले है, नेता प्रतिपक्ष ने शुरूआत की थी और बाद में भाई आनन्द शर्मा जी ने जोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं विदेश मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या रशिया के साथ बाइलेटरल में यह चर्चा हुई थी? चाइना के साथ बाइलेटरल में यह चर्चा हुई थी? आनन्द भाई, आप यह जानते हैं कि अगर उन पांचों देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा नहीं हुई होती तो संयुक्त वक्तव्य बनता कैसे? उन सब के साथ चर्चा हुई थी तभी तो पांचों देशों के अधिकारी बैठे और यह संयुक्त वक्तव्य इसमें से निकला। जब मल्टी लेटरल फोरम पर एक वक्तव्य गया है, आप उसकी अहमियत कम करके आंक रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि बाइलेटरल चर्चा हुई कि नहीं। अगर द्विपक्षीय चर्चाएं हुईं रशिया के साथ नरेन्द्र मोदी जी की बात हुई, मि. पुतिन के साथ, चाइना के साथ Mr. Xi Jinping के साथ बात हुई, ब्राजील के साथ बात हुई, साउथ अफ्रीका के साथ बात हुई और उनमें एक सहमति बनी, तभी तो यह ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला। इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि आनन्द शर्मा जी जैसा व्यक्ति जो इंटरनेशनल अफेयर्स का मालिक समझा जाता है, वे ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं।

**श्री आनन्द शर्मा** : इसका स्पष्टीकरण अगर आप दें। ...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : अब आप मुझे पूरा सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री आनन्द शर्मा** : दो बातें होती हैं सुषमा जी, एक तो शिखर सम्मेलन का घोषण पत्र जिसकी हम सराहना करते हैं, हमने उसकी चर्चा की, वह अलग होती है। जब वन टू वन होती है, हैड ऑफ स्टेट और हैड ऑफ गवर्नमेंट की, उसमें कई विषय चर्चा में आते हैं जो शिखर के एजेंडा से अलग होते हैं। मैंने यह मालूमात करने की कोशिश की कि कभी जिक्र हुआ कि क्या प्रधान मंत्री जी आकर अपना बयान देंगे। ...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : आप स्वयं की इस बात का जवाब दे रहे हैं कि एजेंडा में वह क्यों आया? आपने कहा कि वह एजेंडा में आते हैं, वे एजेंडा में चर्चा में आए तो स्टेटमेंट में आए तो बाइलेटरल चर्चा हुई। दूसरी बात आप कह रहे हैं प्रधान मंत्री जी के बयान की और आपने इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया, "He is obliged to make the statement." मैं पूछना चाहती हूं कि इससे पहले 5 बार शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ। कितनी बार यह ऑब्लिगेशन डॉ. मनमोहन सिंह जी ने निभाई है? ...(**व्यवधान**)... नहीं-नहीं, आप मुझे बताइए न, हर बार बाइलेटरल स्टेटमेंट

होता है। आप एक बार भी मुझे बता दीजिए। प्रधान मंत्री श्री मोदी जी बयान देंगे या नहीं देंगे, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपकी बात पर केवल यह कह रही हूं कि आपने कहा "He is obliged to make the statement." आप जाकर देख लीजिए कि एक बार भी हुआ या नहीं। एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी ब्रिक्स की सम्मिट के बाद बयान नहीं हुआ। एक बार बयान केवल EAM का आया था और वह भी इस पर BRICS, IBSA और एक न्यूक्लिअर ट्रीटी, तीनों का मिलाजुला एक बयान उस समय पर सलमान खुर्शीद साहब ने दिया था EAM ने लेकिन कभी भी आज तक ब्रिक्स सम्मिट के बाद प्रधान मंत्री का कोई बयान दोनों सदनों में से एक में भी नहीं हुआ। लेकिन मैं इस विषय पर आती हूं, चूंकि आपने प्रश्न उठाया था इसलिए मैंने कहा। फिर आपने कहा कि क्या आप वहां पर मदद देंगे, यदि आपने प्रश्न पूछा मुझसे कि कोई माली मदद देंगे? तो मैं सदन को बताना चाहती हूं कि 20 बिलियन यू.एस. डॉलर तो बजटरी सपोर्ट देते हैं फिलिस्तीन को, लेकिन वन मिनियन यू.एस. डॉलर केवल UNRWA को, जो यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है, उसको देते हैं। केवल फिलिस्तीन रिफ्यूजी का कुछ सहायता करने के लिए और उनको चीजें मुहैया कराने के लिए। तो जो दो बातें, नेता प्रतिपक्ष ने पूछी हैं और एक आनन्द शर्मा जी ने पूछी है, उन दोनों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया है कि ब्रिक्स में भारत अपनी प्रतिक्रिया दे चुका था और बाइलेटरल टॉक्स में यह बात आई तभी तो शिखर एजेंडा के उसमें आई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीन लोग बोले। सबसे पहले अनिल माधव दवे जी बोले, फिर चंदन मित्रा और फिर तरुण विजय जी बोले। मुझे नहीं मालूम कि आपने उनकी भावनाओं को क्या समझा। दवे जी महज इतना बतलाना चाह रहे थे कि आज पूरे विश्व में जितनी अशांति है, बजाय टुकड़ों-टुकड़ों में एक-एक जगह चर्चा करने के, अगर सदन पूरी चर्चा समग्रता में करता तो शायद कोई निदान और समाधान तक हम पहुंच पाते। अब इस बात को मुझे नहीं पता कि कैसे भाई शरद यादव ने यह समझ लिया कि वे धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, मजहब के आधार पर बांटना चाह रहे हैं।

शरद भाई, यह सरकार मजहब के आधार पर कतई कोई तफरका नहीं करती, यह मैं आपको बहुत साफ कह देना चाहती हूं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देना चाहती हूं। आपके पीछे अंसारी साहब बैठे हैं। इसी महीने की 2 जुलाई को सऊदी अरब का एक मसला लेकर वह मेरे पास पाए थे। उसमें 40 लोग, जिसमें से ज्यादातर बिहार के थे और 11 राजस्थान के थे और ये सारे-के-सारे मुस्लिम समुदाय के थे। इन्होंने मुझे आकर कहा कि सऊदी अरब में ये बच्चे सजा काट चुके हैं। उन्हें कहीं नारे लगाने की सज़ा मिली थी। उन्हें दो महीने की कैद और 50-50 कोड़े की सजा दी गई थी। इन्होंने कहा कि उन्हें कोड़े भी लग चुके हैं, वे सज़ा भी काट चुके हैं, लेकिन वहां एक साल से बंद पड़े हैं। मैंने कहा बहुत बेइंसाफी हो रही है। हमने उसी दिन 2 तारीख की रात को अम्बैसडर से बात कर के, पूरी जटिल प्रक्रिया समाप्त कर के, 17 तारीख की रात को उन्हें सऊदी अरब से भारत के जहाज में चढ़ा दिया गया और 18 तारीख को वे बच्चे भारत पहुंच गए। मैंने यह नहीं देखा कि वे किस मजहब के हैं। वे हिंदुस्तानी है। अगर बाहर विदेश में एक भी व्यक्ति के साथ बेइंसाफी हो रही है, तो वह चाहे किसी भी मजहब का क्यों न हो, हम उसके लिए पूरा न्याय करेंगे। उपसभापति महोदय, आप तो साक्षी हैं, केरल की वे नर्सें, जिनमें से अधिकतर क्रिश्चियंस थीं, मैंने तो उनका मजहब नहीं देखा। हम दो दिन की कैप्टिविटी के बाद उन्हें वहां से निकालकर ले आए। अभी भी मेरे 39 बच्चे इराक में बंधक हैं, जिनमें से ज्यादातर सिख समुदाय

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

के हैं, पंजाब के हैं। हम उन्हें वहां से निकालने के लिए दिन-रात एक किए हुए हैं। इसलिए शरद भाई बिल्कुल मत सोचिए कि यह सरकार किसी को मजहब के आधार पर देखती है या मजहब के आधार पर किसी चर्चा को स्वीकार या समाप्त करती है।

**श्री शरद यादव** : मेरी बात को आपने ठीक से नहीं समझा। मैं तो इतनी बात कह रहा था कि आज का विषय फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में हो रही हिंसा का है। इससे बाहर जाएंगे तो बात लंबी खिंचेगी और न्यायसंगत भी नहीं होगी।

**श्री सुषमा स्वराज** : उसे कहते-कहते आप यह कह गए कि दवे साहब मजहब के आधार पर बांटने की बात कर रहे थे। उसका उत्तर मैंने दिया।

महोदय, जदयू से दो साथी बोले। शरद यादव जी के बाद भाई के.सी. त्यागी बोले थे। त्यागी जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप यहां आधी-अधूरी बात रखेंगे। आपने 10 जुलाई का मिनिस्ट्री का बयान पढ़कर सुनाया, लेकिन आपने जो वाक्य पढ़ा, उससे पहले भी उसमें एक वाक्य लिखा था। वह वाक्य मैं पढ़कर सुनाती हूं। हमने पहले वाले 10 जुलाई के बयान में कहा था, "The Ministry of External Affairs issued a Statement on 10th July, 2014, expressing deep concern at the escalation in violence, particularly through air strikes in Gaza resulting in loss of civilian lives and damage to property." यह आपने नहीं पढ़ा, आपने क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन पढ़ लिया।

**श्री के.सी. त्यागी** : मैंने जिस अखबार में यह स्टेटमेंट पढ़ा है...

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : उसमें आधा लिखा था। ...(**व्यवधान**)... विदेश मंत्रालय के बयान के पहले जिक्र गाज़ा का हुआ है, बाद में इजराइल के हमले का हुआ है। बाद में क्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन की बात हुई है। सबसे पहले हमने ग़ाजा के वॉयलेंस की बात की है और उसमें सिविलियन लाइव्ज व प्रॉपर्टी के डैमेज की बात की है। मैंने आपको वह बयान पढ़कर सुना दिया। इसलिए मैं कहूंगी कि आप मुझसे आधी-अधूरी बात न करें।

महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने मुझसे सीधा प्रश्न किया कि क्या विदेश नीति में कोई बदलाव हुआ है? महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि विदेश नीति में रत्ती-भर, तिल-भर बदलाव नहीं हुआ है। मगर वह नीति यह है कि पैलस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इज़राइल से संबंध बनाए हुए हैं। उपसभापति जी, 1988 में हमने फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दी और 1992 में हमने इजराइल को मान्यता दी। डी. राजा साहब कह रहे थे, 1974 में हमने पी.एल.ओ. यानी पैलस्टियन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन को मान्यता दी थी, लेकिन पैलस्टेनियन को स्टेट के तौर पर 1988 में मान्यता दी थी।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have one correction. After Oslo Accord in 1992, we established diplomatic relations. India had recognized it.

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : मैं वही बताने जा रही हूं।

SHRI ANAND SHARMA: But after PLO accepted the two-nation theory, then, India started establishing diplomatic relations.

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : मैं वही बताने जा रही हूं। वर्ष 1992 में हमने अपने डिप्लोमैटिक रिलेशंस इजरायल से बनाए। आनंद भाई, 1992 में हमने अपने डिप्लोमैटिक रिलेशंस स्थापित किए और संयोग की बात है कि दोनों समय कांग्रेस की सरकार थी, 1988 में श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और 1992 में श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और 1992 से लेकर 2014 तक यह पांचवीं सरकार है, जो आई है। देवेगौड़ा जी की सरकार आई, इन्द्र कुमार गुजराल जी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और अब 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आई। लगातार यही नीति, क्या नीति, कि पैलस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए हम इजराइल से अपने संबंध बनाए हुए हैं। यह नीति लगातार 2014 तक चल रही है। दो महीने पहले तक आपकी सरकार थी और हर बार का राष्ट्रपति अभिभाषण उठाकर आप पढ़ लीजिए, पहला पैरा पैलस्टाइन के बारे में होता था और उससे लगा हुआ दूसरा पैरा इज़राइल के बारे में होता था। मैं तो कहूंगी कि केवल संबंधी बनाए नहीं, संबंध बढ़ाए हैं। तो पैलस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए इजरायल से हमने संबंध बनाए रखे और संबंध बढ़ाए। उसका हम बराबर उल्लेख करते थे। वह जो नीति है, उसमें कभी भी इतना भी तिल भर परिवर्तन न नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के आने पर हुआ और न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ। ज्यादातर यह पीरियड जो गया, उसमें 6 साल हम थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार थी और डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यू.पी.ए. की सरकार थी। ये 16 साल हम लोगों की सरकारें रहीं, लेकिन जो बाकी सरकारें भी रहीं, वे भी गठबंधन की सरकारें थीं, तो अगर मैं यह कहूं कि उन गठबंधन की सरकारों में लगभग-लगभग हिन्दुस्तान के हर बड़े राजनैतिक दल की हिस्सेदारी रही है, तो इसका मतलब यह नीति मुल्क की रही है, हिन्दुस्तान की रही है। यह नीति कांग्रेस या बी.जे.पी. की नहीं रही, एन.डी.ए. या यू.पी.ए. की नहीं रही, बल्कि हिन्दुस्तान की यह नीति रही है कि पैलस्टीनियन कॉज का भरपूर समर्थन करते हुए इजराइल से संबंध बनाए रखो।

महोदय, उसके बाद सी. पी. एम. से भाई सीताराम येचुरी बोले। इन्होंने दो बातें कहीं, एक तो कहा कि रेजोलूशन होना चाहिए और दूसरी बात इन्होंने कही, मैं तरुण विजय की तरह तोड़-मरोड़ नहीं रही हूं, कि उससे हथियार खरीदना बंद करना चाहिए। आपने यह तो कहा था।

**श्री सीताराम येचुरी** : तत्काल।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : तत्काल, यही कहा था आपने। अब मैं आपको अपना समय याद दिलाती हूं। यह जो 2014 में घटना घटी है, इससे पहले बिल्कुल इसी तरह की दो घटनाएं, एक 2008 में और एक 2012 में घटीं। जब 2008 में इज़राइल ने कास्ट लीड आपरेशन किया, उस समय 1400 पैलस्टीनियन्स मारे गए थे और आप उस समय सरकार को समर्थन दे रहे थे, यानी आप सरकारी पक्ष थे। ...(**व्यवधान**)... जी, बाहर से समर्थन दे रहे थे। आप कोर्डिनेशन कमेटी के मेम्बर थे। मैं पूछना चाहती हूं कि जो आपके सहयोग से सरकार चल रही थी, उस समय 2008 में ऐसी हिंसा हुई थी, 1400 पैलस्टीनियन्स मारे गए थे, क्या उस समय आपने उस सरकार को, जिसको आप समर्थन दे रहे थे, यह सलाह दी थी कि आप हथियार खरीदने बंद कर दीजिए? यह हमारी सरकार आते ही आपका रुख क्यों बदल जाता है?

**श्री सीताराम येचुरी** : सर, एक मिनट। मैडम, हमने उस समय भी यही सलाह दी थी। अफसोस है कि वह सलाह नहीं मानी गई, इस समय तो आप मान दीजिए। हमारा यही कहना है।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : आप तो स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने बात आपकी सुनी नहीं। आप आपस में सुलझा लीजिए। किसने कहा था और किसने नहीं कहा था? यह तो आप आपस में उलझ रहे हैं। आप अपने आप सुलझा लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

**श्री तपन कुमार सेन** : उस समय नहीं किया, तो हमने सपोर्ट विदड्रा कर लिया।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : उस समय सपोर्ट विदड्रा नहीं किया था। आप गलत फैक्ट मत रखिए। वह आपने न्यूक्लीयर डील पर विदड्रा किया था, इस पर नहीं किया था तो मेरा कहना यह है कि जब हम किसी बात को यहां पर रखें, तो पूरी चीज का खुलासा करके रखें।

उपसभापति जी, स्थिति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण अनसुलझा विवाद है, वह इज़राइल और फिलिस्तीन का है। अनेकानेक शांति प्रयास हुए, 1993 में ओसलो एग्रीमेंट हुआ, 2002 में अरब पीस इनीशिएटिव हुआ, इंटरनेशनल क्वार्टलैट एफर्ट हुआ, इसमें चार अलग-अलग, युनाइटेड नेशंस था, युनाइटेड स्टेट्स था, रशिया था, इयू था। इंटरनेशनल क्वार्टेट एफर्ट के थ्रू संयुक्त प्रयास हुआ। उसके बाद 2000 में अमरीका समर्थित केम्प डेविड समिट हुआ। और अभी लेटेस्ट 2013 की जुलाई में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी की मध्यस्थता के साथ, उनकी पहल पर यह शांति वार्ता शुरू हुई। इसमें समायवधि भी तय कर दी गई कि नौ महीने के अंदर-अंदर यह शांति वार्ता समाप्त होगी, किसी समाधान के साथ, लेकिन नवां महीने आते-आते सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि 23 जुलाई को प्रेज़ीडेंट महमूद अब्बास ने युनिटी गवर्नमेंट की घोषणा कर दी, जिसमें वैस्ट बैंक से फतह और गाजा से हमास, दोनों ने एक सरकार बनाने की घोषणा की, लेकिन हमास ने कहा कि हम सरकार के अंदर नहीं जाएंगे, सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। इस पर इज़राइल ने शांति वार्ता तोड़ दी और उन्होंने कहा कि जिस सरकार को हमास का समर्थन है, हम उससे बात नहीं करेंगे और उसके बाद इजराइल के तीन किशोर उम्र के बच्चे अपहरण कर लिए गए और बाद में उनकी हत्या हो गई। इजराइल का कहना है कि यह हमास ने किया है और हमास इससे इंकार करता है। अब ये साक्ष्य हैं, पक्ष हैं, लेकिन उसके बाद हिंसा भड़क गई और उस हिंसा का व्याप बढ़ता चला गया। जैसे हमने भी 10 जुलाई को एक स्टेटमेंट दिया, युनाइटेड नेशन्स से भी एक स्टेटमेंट आया, ब्रिक्स से भी स्टेटमेंट आया, लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आए, उन तमाम स्टेटमेंट्स में लोगों ने उनसे शांति वार्ता पहल करने की बात की। 15 जुलाई को इजिप्ट ने सीज़फायर का प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव को इज़राइल ने स्वीकार कर लिया। उस प्रस्ताव को पैलेस्टीनियन स्टेट, पी.एल.ओ. का भी समर्थन मिल गया, एन्डोर्समेंट मिल गया, लेकिन हमास ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चाहिए तो यह था कि आज सारे लोग बोलते-बोलते जो ऑपरेटिव पार्ट लाते, वह यह लाते कि हमें कहना चाहिए कि इजिप्ट अभी भी यह कह रहा है that ceasefire is on the table. अभी वह सीज़फायर का प्रस्ताव खत्म नहीं हुआ है। सीजफायर का प्रस्ताव अभी जिंदा है। चाहिए यह था कि यह सुर इस सदन से निकलता कि हम कहें, उन दोनों देशों को कि आप लोग वापस शांति वार्ता की मेज पर जाइए और जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर काम कीजिए और देश तथा विश्व में शांति स्थापित करने की बात कीजिए, जो नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : सीज़फायर तो हम कह ही रहे हैं।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : हमास नहीं कह रहा है। हमास का मिलिट्री विंग नहीं कह रहा है। अगर हमास का मिलिट्री विंग मान जाता ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : हम तो कह रहे हैं।

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हमास का मिलिट्री विंग मान जाता, तो इसमें आगे बढ़कर अभी तक शांति हो जाती, लेकिन सवाल इस समय वहां खड़ा है और मुझे एक बात की खुशी है कि सारे अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यह कहा है कि यह शांति वार्ता होनी चाहिए। यू.एन., यू.के., यू.एस., चीन, रशिया तो कह ही रहे हैं, वे तो कह ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खाड़ी के देशों के, अरब देशों के सभी विदेश मंत्री कह रहे हैं और इसीलिए मैं यह कह रही हूं कि आज के सदन का सुर यह होना चाहिए था। हम बार-बार कह रहे हैं कि हम एक रिजॉल्यूशन करें, आप तो खुद ही नियमों का हवाला देते हैं, जिस नियम के तहत आप यह चर्चा करने आए हैं, क्या उस नियम के तहत कोई प्रावधान है रिजॉल्यूशन का? क्या उसके नीचे कोई मोशन आ सकता है? क्या उसके नीचे कोई वोटिंग हो सकती है? जिस समय मैंने चेयरमैन साहब को पत्र लिखा था, उस समय चेयरमैन साहब ने मुझे जवाब दिया था और वह जवाब मैं पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने लिखा था-"As per Rule 178, in case of a Short Duration Discussion, there shall be no formal Motion before the Council, nor voting."

यह चेयरमैन साहब का मुझे दिया हुआ जवाब है कि जिसके तहत आपने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन माना है, उसके नीचे कोई मोशन होता ही नहीं, उसके नीचे कोई वोटिंग होती ही नहीं, तो भी आप बार-बार रिजॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई रिजॉल्यूशन... होना क्या चाहिए? होना वह चाहिए, जो हमारे एन.सी.पी. के माजीद मेमन साहब ने कहा। माजीद मेमन साहब ने साहिर लुधियानवी की एक कविता पढ़ी, एक नज्म, जो जंग के खिलाफ थी। आज का जो हमारा ब्रीफ है इस सदन का वह यह होना चाहिए कि जहां-जहां हिंसा हो रही है, उस हिंसा की हम निंदा करे और हिंसा की निंदा करते हुए दोनों देशों को यह कहें कि समाधान केवल शांति से निकल सकता है, और किसी चीज से नहीं निकल सकता, इसलिए वापस टेबल पर बैठिए और इजिप्ट ने जो प्रस्ताव सीज़फायर का दिया है, उसको दोनों स्वीकार कीजिए और पूरे विश्व में शांति स्थापित करने की एक पहल कीजिए - यह सुर निकालना चाहिए और मैं समझती हूं कि यही सुर हमारी संसद का हो, यही सुर संसद से होना चाहिए, यही सुर सरकार का होना चाहिए... और यही सूर हमारे पूरे मुल्क का होना चाहिए। मेमन साहब, आपने जो साहिर लुधियानवी की नज्म सुनाई, मुझे जाहिर साहब की उसी नज्म से और चार लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। बजाय रेजोल्यूशन के यह संदेश दीजिए इस सदन से, और इस संदेश को बहुत उम्दा तरीके से साहिर साहब ने पेश किया है।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

चलो कि चल के उन सियासी मुक़ामिरों से कहें
कि हमें जंगो-जदल के चलन से नफ़रत है।
जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास न आए,
हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है।

इस संदेश के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सीताराम येचुरी** : सर, हमने रूल 167 के अंतर्गत चर्चा की मांग की थी जिसके अंदर रेजोल्यूशन का प्रावधान था। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yechury, let the Leader of the Opposition speak.

**श्री सीताराम येचुरी** : तब चेयरमैन साहब ने कहा कि इस रूल के तहत सरकार नहीं मान रही है, तभी यह शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के अंदर आया ...(**व्यवधान**)...

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : जो आया, उसी को करो।

**श्री सीताराम येचुरी** : हमने मांग तो उसी की की थी। ...(**व्यवधान**)... सरकार अगर इस बात को मान लेती तो वह रेजोल्यूशन जरूर होता। हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि यह बहुत गंभीर मसला है, इसके ऊपर एक प्रस्ताव के रूप में सदन से जरूर कुछ जाना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, the Leader of the Opposition.

**श्री गुलाम नबी आज़ाद** : माननीय मिनिस्टर साहिबा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सिर्फ दो चीजें, आपने कहा कि यहां उभरकर आनी चाहिए। मैंने आखिर में, अपना भाषण समाप्त करने से पहले पांच-छह मुद्दे पढ़े थे, उसमें मैंने यही कहा था, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कहा। हमने कहा था,

†[**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : مانّنے منسٹر صاحبہ، آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ صرف دو چیزیں، آپ نے کہا کہ یہاں ابھر کر آنی چاہئے۔ میں نے آخر میں، اپنا بھاشن ختم کرنے سے پہلے پانچ-چھہ مدّعے پڑھے تھے، اس میں میں نے یہی کہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے کہا تھا۔ کہ]

Israel's heavy use of force must stop immediately. Defiant rocket attacks by Hamas on Israeli Territory should also come to an end. I also said, prevent further loss of life and property and a united appeal should be made to both the sides to de-escalate tensions. ऐसा नहीं है कि ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ...(مداخلت)... कि हमने ...(**व्यवधान**)...

**श्री सीताराम येचुरी** : सीज़फायर भी कहा।

---

†Transliteration in Urdu Script.

**श्री गुलाब नबी आज़ाद** : और भी बहुत सारी चीज़ें जुबानी बतायी थीं। हम लोगों ने यहां पर यह सब कहा था। ...(**व्यवधान**)... बहुत सारी चीज़ें थीं, मैं सब नहीं पढ़ रहा हूं, बहुल लम्बा-चौड़ा था, मैं कागज़ अंदर ऑफिस में छोड़कर आया हूं। माननीय महोदय, हम लोगों ने, अपोजिशन ने – पूरी जितनी अपोजिशन है–यह मांग की थी कि यहां चेयर की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बल्कि पूरे सदन की तरफ से, भारत के सदन की तरफ से, चेयर की तरफ से एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। हम लोगों ने, अपोज़िशन ने जो बनाया था, वह आपको भी दिया था, माननीय फॉरेन मिनिस्टर को भी दिया था। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जानना चाहती हैं कि उसके बारे में आपकी क्या रूलिंग है?

†[ **جناب غلام نبی آزاد :** اور بھی بہت ساری چیزیں زبانی بتائی تھیں۔ ہم لوگوں نے یہاں پر یہ سب کہا تھا ---(مداخلت)--- بہت ساری چیزیں تھیں، میں سب نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت لمبا چوڑا تھا، میں کاغذ اندر آفس میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ مانئے مہودے، ہم لوگوں نے، اپوزیشن نے، پوری جتنی اپوزیشن ہے، یہ مانگ کی تھی کہ یہاں چیئر کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں، گوورنمینٹ کی طرف نہیں بلکہ پورے سدن کی طرف سے، بھارت کے سدن کی طرف سے، چیئر کی طرف سے ایک ریزولیوشن آنا چاہئے۔ ہم لوگوں نے، اپوزیشن نے جو بنایا تھا، وہ آپ کی بھی دیا تھا۔ مانئے فارن منسٹر کو بھی دیا تھا۔ سبھی پولیٹکل پارٹیز جاننا چاہتی ہیں کہ کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رولنگ ہے؟ ]

DR. V. MAITREYAN: Sir, the resolution should be comprehensive and it should include all. We demand that.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That is your demand. ... *(Interruptions)*... Sir, we would like to know ... *(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: Before the Chair gives a ruling, I want to emphasize that the resolution has to be comprehensive and should touch upon the issues that I have raised. ... *(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: We would like to know from the hon. Leader of the House what the position is. ... *(Interruptions)*... I want a response from the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will react to what you have said. See, the position is, this discussion is under Rule 176. Under Rule 176, there is no formal motion and there is no voting. That is a Rule. ... *(Interruptions)*... I will come to that. Let me complete. That is the position regarding Rule 176. This fact has been narrated here by the hon. External

†Transliteration in Urdu Script.

[Mr. Deputy Chairman]

Affairs Minister and what you said about Rule 176 is correct; it stands. On what hon. Leader of the Opposition said, hon. Leader of the Opposition has said about a resolution, whether after a discussion under Rule 176, can we take a resolution. That is the point. The Leader of the Opposition has said, a resolution should be taken with a full consensus and it should come from the Chair. Now, resolution is possible only if there is consensus from both the sides. We, even after this discussion, can have a resolution, but for that the condition is that it cannot be motion, it cannot have voting but it should be a resolution with a full consensus of the House. So, the Chair can move a Resolution or Government can move a Resolution or this side can move a Resolution only if there is consensus, full consensus. Now, the hon. LoP has made it clear that there is consensus on this side about this Resolution. The Chair can accept or agree for such a Resolution only if that side also agrees for that Resolution. I have to listen to that from this side also. What is your view? ... *(Interruptions)* ...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): Sir, we are not asking for voting. ... *(Interruptions)* ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes, not asking.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Let the Resolution come from the Chair. ... *(Interruptions)* ... We don't mind if the Resolution comes from the Leader of the House. ... *(Interruptions)* ... we are not saying that the Resolution should come from the Opposition. ... *(Interruptions)* ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the point.

SHRI GHULAM NABI AZAD: We will accept that also if the Resolution comes from the Leader of the House. ... *(Interruptions)* ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is not the point. If the Chair has to permit a Resolution, even for permission, I want consensus of this House because Rule 176 is there.

**श्री सीताराम येचुरी** : सर, साहिर लुधियानवी का आपने जिक्र किया। उनका एक नगमा आपको जरूर याद होगा - वह सुबह कभी तो आएगी, याद है ना? जब दुनिया से जुल्म को खत्म करेंगे, वह सुबह तो कभी आएगी। आप उसको लाइए। आप एक प्रस्ताव रखिए। हम लोग सभी समर्थन करेंगे। आप इसे लाइए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Is there an agreed version? I don't know. ... *(Interruptions)* ... See, as far as I am concerned, I don't know about it. I have got a copy. But this is not an agreed version. Is there an agreed version? ... *(Interruptions)* ... Is there an agreed version? I would like the Government to react.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: No, Sir. The discussion on the Short Duration Notice has already taken place, comprehensively taken place.

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : सर, हम यह कह कर सदन को बांट रहे हैं, हम बांटें ना। मैंने जिससे अंत किया है, वह संदेश देकर हम इस सदन में उठें, एक सुर में बात करें, यही संदेश दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That means there is no draft agreed by both sides. There is no agreed Resolution. ... *(Interruptions)*...

SHRI P. RAJEEVE: Sir, earlier, we had given notice under Rule 167 for a motion. At that time, the Government was not agreed for that. Only because of that, we have taken this discussion as a Short Duration Discussion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am bound by the rules. I am telling you, I am bound by the rules. The rule is very clear. Under Rule 176, there cannot a motion and there cannot be voting. So you cannot move a Resolution. ... *(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, may I request one thing?

MR. DPEUTY CHAIRMAN: Please.

SHRI SITARAM YECHURY: If the Leader of the House agrees and if the hon. Minister and along with them, if this side agrees, you please take a recess for ten minutes. Let the leaders meet and then we come to an agreement whether it is possible or not. ... *(Interruptions)*... Yes, let us have a recess for ten minutes and let the leaders meet. That is my concrete suggestion. ... *(Interruptions)*... Therefore, I am making a request. ... *(Interruptions)*... If the Leader of the House agrees, you can consult him. We can just meet for ten minutes and see it if is possible. ... *(Interruptions)*...

**श्री प्रकाश जावडेकर** : सर, ऐसा कभी हुआ है क्या? ...**(व्यवधान)**... रेल बजट पर चर्चा होनी है। कई दिन निकल गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती सुषमा स्वराज** : येचुरी जी, नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री सीताराम येचुरी** : उसके बाद कई रातें गुजर गईं, कई सुबहें चली गईं, आपको पुरानी बातें अब याद आ रही हैं। हम आज की बात कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

**श्री उपसभापति** : गुजराल जी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Yechuryji, as far as the Chair is concerned, I have no problem. But the point is, I should have consent from both sides, and even for your suggestion.

DR. V. MAITREYAN: Sir, not both sides; all sides.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, all sides. 'Both' means all sides. Yes. So, even for accepting your suggestion, there is no consensus. ...*(Interruptions)*... That is what I am saying. ...*(Interruptions)*... There is no consensus. ...*(Interruptions)*... Okay. So, I am sorry, there is no consensus. ...*(Interruptions)*... So, I am going to take up the Railway Budget. ...*(Interruptions)*...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we, the entire Opposition, walks out. ...*(Interruptions)*...

*(At this stage some hon. Members left the Chamber.)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What can I do? . ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: The Leader of the House, at least, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot talk now. . ...*(Interruptions)*... That is for them. ...*(Interruptions)*... That is for the Government. That is for them to say. ...*(Interruptions)*... I cannot influence the Government.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, this is not fair. ...*(Interruptions)*... So, we will have to walk out in protest. . ...*(Interruptions)*...

*(At this stage some hon. Members left the Chamber.)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Neither can I influence you nor can I influence the Government. ...*(Interruptions)*...

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, यह सरकार इतनी सी बात मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वाक आउट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।

*(At this stage some hon. Members left the Chamber.)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot influence. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, Railway Budget. . ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Railway Budget. ...*(Interruptions)*... We shall now take up the Railway Budget. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, I have a suggestion to make. ...*(Interruptions)*... Without having any Resolution, the Chair could make a reference, because the Government has also expressed concern. ...*(Interruptions)*... The Government has also expressed concern, and in the same manner. The Opposition too has expressed concern. The Chair could make a reference. ...*(Interruptions)*... Instead of a Resolution . ...*(Interruptions)*...

**4.00 P.M.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: A reference by the Chair would also have to be with consensus. You know that. ... *(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Well, Sir, we are staging a walk out in protest against that.

*(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)*

---

## *THE BUDGET (RAILWAYS) 2014-15, AND GOVERNMENT BILLS

**(i.) The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 2014**

**(ii.) The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 2014**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, The Budget (Railways) 2014-15, The Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 2014 and The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 2014 to be discussed together.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Sir, I move:

> That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spend on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 2012 in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

> That the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2014-15 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

*The questions were proposed.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ghulam Nabi Azad; not here. Shri Prabhat Jha.

**श्री प्रभात झा** (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, 6 दिन बाद रेल बजट 2014-15 पर बहस की शुरूआत हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है और विपक्ष धीरे-धीरे सदन में आ रहा है, इस बात की भी खुशी है। आजादी के 67 साल बाद अब तक जितने रेल बजट पेश हुए, उनमें से 60 रेल बजट कांग्रेस या कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने प्रस्तुत किए हैं। उसमें यदि सामान्य से सामान्य नागरिक से पूछा जाए कि आज भारत की रेलवे की जो दुर्दशा है, इसके लिए कौन

* Discussed together.